

2019-20

231

Impact Factor - 6.261 | Special Issue - 145 | Feb. 2019 | ISSN



INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S
RESEARCH JOURNEY

UGC Approved Journal
Multidisciplinary International E-research Journal

RECENT TRENDS IN
**ENGLISH, MARATHI, HINDI
LANGUAGE AND LITERATURE**

- GUEST EDITOR -

Principal Dr. P. P. Sharma

- CHIEF EDITOR -

Dr. Dhanraj T. Dhargar

- EXECUTIVE EDITORS -

Dr. S. S. Chouthaiwale
Dr. A. T. More | Dr. P. S. Patil

Printed By : **PRASHANT PUBLICATIONS, JALGAON**

For Details Visit To : www.researchjourney.net

52

227



VOLUME - VIII, ISSUE - II - APRIL - JUNE - 2019
AJANTA - ISSN 2277 - 5730 - IMPACT FACTOR - 5.5 (www.sjifactor.com)



CONTENTS OF HINDI PART - II



अ.क्र.	लेख आणि लेखकाचे नाव	पृष्ठ क्र.
२३	पीडा की प्रेरणा का दस्तावेज मरकत द्वीप की निलंमणी डॉ. अभयकुमार आर. खैरनार	१२९-१३१
२४	जनसंचार माध्यमों में हिन्दी डॉ. आशा डी. कांबळे	१३२-१३६
२५	स्त्री विमर्श : नासिरा शर्मा की कहानी 'गुंजादहन' एक अध्ययन प्रा. डॉ. शे. रज़िया शहेनाज़ शे. अब्दुला	१३७-१४०
२६	भारतीय समाज में स्त्रियों की स्थिती प्रा. डॉ. रेविता बलभीम कावळे	१४१-१४३
२७	दिनकर के साहित्य में दलित, पीड़ित तथा शोषितों का करुण गान प्रा. डॉ. सुभाष नागोराव क्षीरसागर	१४४-१४६
२८	तस्नीफ का कवि आरिफ कजुर्वैनी डॉ. मोहम्मद याह्या जमील	१४७-१४९
२९	दुर्घ्यंत की गज़ल में राजनैतिक संलाप डॉ. रवीन्द्रकुमार शिरसाट	१५०-१५६
३०	भारतीय राजनीति मे वंशवाद : एक विश्लेषण स्वामी विरभद्र गुरप्पा	१५७-१६२
३१	हिंदी साहित्य में कृषक जीवन प्रा. डॉ. अश्विनीकुमार नामदेवराव चिंचोलीकर	१६३-१६७



३१. हिंदी साहित्य में कृषक जीवन

प्रा. डॉ. अश्विनीकुमार नामदेवराव चिंचोलीकर
सहयोगी प्राध्यापक, राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड, जिला औरंगाबाद ।

भारत एक कृषिप्रधान राष्ट्र माना जाता है । इस कारण कृषक जीवन भारतीय अर्थव्यवस्था के रीढ़ की हड्डी माना जा सकता है । 'अमरकोश' में कृषक के संबंध में कहा गया है - " 'कुस्सित' नाशपति इति की नाशः' अर्थात् ,दुरावस्थाओं का नाश कर सुख और समृद्धि लानेवाले को कृषक कहते हैं । 'यजुर्वेद' में कृषक को श्रेष्ठ मानकर, सृष्टि के पालहार के रूप में उसे नमस्कार किया गया है ।

स्पष्ट है, कि हमारे पुराणग्रंथों में कृषक जीवन, आदर और सम्मान के साथ देखा गया है । रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्यों में राजाओं को खेती करते दिखाया गया ।

स्वतंत्रतापूर्व तथा बाद में भी काफी समय तक जमींदार तथा सेठ-साहुकारादि गरिब किसानों का शोषण करते रहे । पारिवारिक, व्यक्तिगत समस्याएँ, कर्ज का बोझ तथा प्राकृतिक आपदाएँ आदि के जंजाल में फँसा किसान आज अपना मानसिक संतुलन स्थिर रखने में असफल है, जिस कारण वह देहत्याग या आत्महत्याके लिए विवश है ।

23 अप्रैल 2015 के 'डेली न्युज एक्टिविश्' के अनुसार भारत में 5½ लाख गाँव हैं । इसमें 68 % प्रतिशत किसान एवं किसान-मजदूर हैं । अर्थात्, आधे से अधिक हिस्से में किसान आबादी है । इससे स्पष्ट है कि इस वर्ग के विकास में ही राष्ट्रीय-उत्थान नाहित है । किंतु विडम्बना है कि बी.बी.सी.न्युज रिपोर्ट 1 दिसंबर 2018 के अनुसार पीछले बीस सालों में करिबन तीन लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है ।

हिंदी साहित्य ने सदैव समाज के दर्पण का दायित्वपूर्ण प्रामाणिकता के साथ बखूबी निभाया है । हिंदी के उपन्यास, कविता, कहानी, नाटक, एकांकी, गीत, लोकगीत, निबंध तथा साहित्य की विविध विधाओं में इस राष्ट्रपाल की आदयान्त दयनीय तथा हृदयद्रावक स्थिति सजीव चित्रण पाठकों के सामने प्रस्तुत किया है ।

कबीर ने अपनी अध्यात्मिक ज्ञान की अभिव्यक्ति के लिए कृषक जीवन की दयनीय अवस्था को रूपकों में व्यक्त किया है ।

महाकवि तुलसी ने भी 'खेति न किसान को, बनिक को न बनिक, न भिखारी को भीख बलि ।' कहते हुए अपने समकालीन समाज की अवस्था को प्रस्तुत किया है ।

मैथिलीशरण गुप्त की 'किसान' कविता उनके समकालीन कृषक जीवन को दृश्यात्मक रूप में व्यक्त करने में समर्थ है । वे कहते हैं-

" अच्छी फसल को उपजाने का काम कृषक अत्यान्त प्रामाणिकता से पूर्ण करता है । किंतु उसका बीज भी ऋण के रूपों से खरीदा हुआ होता है ।" उपज के सारे अन्न के संबंध में वे कहते हैं-" आता महाजन के यहाँ वह अन्न सारा अंत में अधपेट खाकर फिर उन्हें हैं काँपना हेमंत में ।" 1

तात्पर्य जी-तौड मेहनत के बाद भी वह महिनों अधपेट खाकर जीने के लिए विवश है ।

इसी प्रकार महाकवि नागार्जून ने अपनी कविता में किसान के जीवन की आर्थिक विपन्नता का संजीव चित्र प्रस्तुत किया है -

" बैल नहीं है, बीज नहीं है । बरखा बिन अकुलाते है । पीछला कर्ज चुका न सके, साहु की झिड़की खाते है ।"²

कर्ज के बोझ तले दबा किसान स्वयं अस्वस्थता का अनुभव करता है । किंतु किसान इन दिनों ही क्यों आत्महत्या कर रहा है ? इससे पूर्व भी प्राकृतिक एवं आर्थिक आपदाओं से जूझते हुए वह जी रहा था । पहले भी वह ऋण लेता था, पहिले भी वह अपने परिवार तथा अपनी कन्या के विवाह की चिन्ता थी, पहिले भी वह अपने पुत्र के भविष्य के बारे में सोचता रहता था । इस प्रकार के विभिन्न समस्याओं के जंजाल से भी समय निकाल कर वह ईश्वर भक्ति में लिन रहता था । परंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जमींदार नहीं रहें, उसे अपने अधिकार की अपनी जमीन भी मिल गयी । किंतु आज वह अधिक अस्वस्थ होकर आत्महत्या की ओर अग्रेसर हो रहा है ।

तात्पर्य, किसान को इस दुर्दशा के लिए उकसाया जाता है । वह उकसाने वाली एक टोस, नियोजित एवं नियंत्रित व्यवस्था है, जो अत्यंत तंत्र-शुद्ध पध्दति से अपना कार्य करती है । इस व्यवस्था की ओर संकेत करते हुए 'आमने-सामने' संग्रह की कविता में कवि विवेक लिखते है -

" एक कीडा/हरा रोएंदार/जतन से पोसे / मेरे पौंधे की पत्तियाँ/खा रहा है/...पत्तियों का हमरंग/
और सबकी नजर बचाता / घिपटा है उसकी उलटी ओर ।"³

अर्थात्, समाज में रहकर, समाज या कृषक-हित का मात्र दिखावा करनेवाला और वास्तव में कृषक-जीवन को अभावग्रस्त बनाने वाला कोई एक व्यक्ति न होकर एक व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है ।

आज का कवि डा. कन्नुलाल विटोरे किसान की आत्महत्या से परावृत्त करने का आवाहन करते है - " हे मेरे देश के अन्नदाता / मत कर आत्महत्या / तू लाल है इस माटी का / तुझ से ही सजे वसुधा ।"⁴

अर्थात्, आज इन किसानों को दम भरने, स्थिर तथा निश्चिंत रहने और सम्पूर्ण देश आपके साथ रहेगा आदि का विश्वास दिलाने की आवश्यकता है ।

उपन्यास सम्राट प्रेमचंद के 'प्रेमाश्रम' और 'गोदान' में तथा 'पूस की रात' 'कफन' और 'दो बैलों की कथा' किसान जीवन से संबंधित है ।

गोदान और प्रेमाश्रम में किसान जीवन के सारे लाग-लगावों को उसकी सभी समस्याओं के साथ प्रस्तुत किया गया है ।

'गोदान' उपन्यास का नायक होरि आर्थिक विपन्नतावश इतना दुर्बल व असहाय है कि अपनी प्रिय पुत्री का विवाह एक अथेड व्यक्ति से करता है । उसी समय उसकी तात्विक मृत्यू हो जाती है । किंतु उसकी अत्याधिक दयनीयता के दर्शन में खेती का जाना, किसान से मजदूर बनना और मजदूरी करते हुए उसकी मृत्यू कृषक-जीवन की वास्तवता है ।

इसी प्रकार संजीव का 'फांस', शिवमूर्ति का 'आखरी छलॉंग' और पंकज सुबीकर का 'अकाल में उत्सव' उपन्यासों में आधुनिक कृषक जीवन का हृदय द्रावक चित्रण है ।

इसी श्रेणी में रेणुप्रभाकर माचवे, पाण्डेय बेचेन शर्मा उग्र तथा अन्य कहानीकार आते हैं। उग्र की कथा 'अभागा किसान' में नायक भिखन बड़ी कन्या के विवाह हेतु महाजन से रुपये लेता है। किंतु समय पर रुपये ना चुका पाने के कारण महाजन के कारिन्दे उसे पकड़ ले जाते हैं। उसकी पत्नी को जब स्थिति असहनीय होती है, तब वह बच्चों को तालाब के ले जाकर उनका गला ऐंठ लेती है और स्वयं भी आत्महत्या करती है। कृषक परिवार की सामुहिक आत्महत्या, तत्कालीन परिवेश की स्थिति की जीवन्त चित्र प्रस्तुत करती है।

इसी प्रकार किसानों की व्यथा को प्रकट करने में प्रमुख कहानीकार - पुन्नी सिंह, शिवमूर्ति, संजीव, मदन-मोहन, सुरेश कंटक, जयनंदन आदि हैं।

इन सभी कहानीकार ने अपनी कहानियों में वर्तमान किसान जीवन को उसकी संपूर्ण उद्विग्नता के साथ उपस्थित किया है। साथ ही उसकी इस दशा के लिए जिम्मेदार भ्रष्ट सहकार क्षेत्र और आक्टोपसी व्यवस्था की ओर स्पष्ट संकेत किया है। यह व्यवस्था उनके सीधेपन का लाभ उठाकर उनके जीवन को ही निगल जाती है।

नाटक साहित्य की अत्यंत महत्वपूर्ण एवं लोकप्रिय विधा मानी जाती है। जिसमें कृषक-जीवन की पीड़ा, व्यथा, अवस्था, अपमानजनक जीवन, शोषण और नयी क्रांति के विचारों की प्रस्तुति हुई है।

किसान-जीवन का यथार्थ चित्रण करनेवाले नाटककारों में वृंदावनलाल वर्मा, शील, उदयशंकर भट्ट, लक्ष्मीनारायण मिश्र, हरिकृष्ण प्रेमी, उपेंद्रनाथ अशक और भगवती चरण वर्मा आदि का उल्लेख किया जा सकता है।

वृंदावन लाल वर्मा के 'धीरे-धीरे' नाटक में जमींदार और कृषक जीवन की संघर्ष गाथा का अंकन है। जमींदार रक्तहीन किसानों का भी रक्तशोषण करने में मग्न था। किंतु जब किसान जाग जाता है, तब अच्छे-अच्छों के रोंगटे खड़े हो जाते यह किसान आंदोलनों में समय-समय पर सिद्ध किया है। गुजरात खेड़ा और अवध आंदोलन इसके प्रमाण हैं। वर्मा जी के प्रस्तुत नाटक में भी सुनचन्द लगान देने से इन्कार करता है तथा अपने किसान भाईयों को भी इसके प्रति सचेत करता है। वह जमींदार से कहता है-

"आप लोग बेगार न ले सकेंगे। लगान कम होगा। जंगल में चराने, लकड़ी काटने और विरासत तथा जोत को बैरेहन करने के हक किसानों को देने पड़ेंगे।" ⁵

अर्थात्, तब तक किसान जाग गया था। किंतु फिर भी इस निरिह जीव के शोषण के आनंद से बचना व्यवस्था को मंजूर नहीं था। इसलिए व्यवस्था नियोजन बध्दता से एक 'चेन-सिस्टम' तयार किया गया है। इस नयी व्यवस्था में रूपा-रानी (रुपया) सर चढकर नृत्य करती है। निर्धन किसान पीछड़ा ही का पीछड़ा ही रह जाता है। उदय शंकर भट्ट का नाटक 'पार्वती' में इसका प्रतिपादन किया गया है। शील के 'तीन दिन तीन रात' में नायक प्रभात कहता है-"यह पूँजीवादी अर्थ नीति का ही नतीजा है कि उच्च शिक्षा इतनी महंगी है कि अस्सी प्रतिशत बालक साक्षरता का दोष लेकर बेकारी के शिकार होते रहते हैं। धनियों के बेटे ऊँचे-ऊँचे पदों पर कब्जा करते हैं। यह वर्गीय व्यवस्था नहीं तो और क्या है।" ⁶

तात्पर्य किसानों को न उगनेवाले बीज देना, निरुपयोगी कीटनाशक और रासायनिक खाद के प्रयोग की प्रेरणा से जमीन को बंजर बनाकर उसपर नाममात्र दाम में कब्जा करना तथा वहाँ सिमेंट के जंगलों की स्थापना

आदि के किसानों के खिलाफ की गई कूट-नीति या षडयंत्र है। साथ ही उसके शिक्षित बेटे की बेकायद बर्बाद कर घर का बोझ बनने के लिए विवश करना भी उसकी आत्महत्या के कारणों में से एक है।

महाकवि अज्ञेय के यात्रा साहित्य से हमें वैश्विक स्तर के कृषक-समाज का परिचय प्राप्त होता है। विभिन्न देशों में स्थित कृषक समाज जीवन व उनकी संस्कृति को उन्होंने अपने यात्रा साहित्य में 'अरे यायावर रहेगायाद' और 'एक बूँद सहसा उछली' में अपने यात्राओं का वर्णन किया है। इनमें भारती प्रदेश, पहाड, नदियाँ, खेती, फसलें, लोक-जीवन, संस्कृति और लोकगीतों को प्रामाणिक रूप से और सौंदर्यवादी ढंगसे प्रस्तुत किया गया है।

धर्मवीर भारती का 'यात्राचक्र' निर्मल वर्मा का 'चींजे पर चोंदनी' और गोविंद मिश्र की 'धुंधमरी सुर्खी,' 'दरख्तों के पार श्याम,' झूलती जड़ें' और 'परतों के बीच' आदि चार यात्रा वर्णन है।

यात्रा वर्णन में लेखक स्वयं देश-विदेश के कोने-कोने का भ्रमण कर वहाँ के सौंदर्य का सूक्ष्म-संवेदनशील हृदय से वर्णन करता है।

गोविंद मिश्र जी ने अपने यात्रा वर्णन में भारत के विभिन्न क्षेत्रों, परिवेश, पहाडों, किसान-जीवन का भी चित्रण किया है। वे कच्छ प्रदेश की लोक मान्यता से विभोर होकर लिखते हैं-

" कच्छ में पानी की कमी के बारे में एक दिलचस्प तथ्य कम लोगों को मालूम है, तो यह सुखा इलाखा, लेकिन यह भी है कि अगर चार साल लगातार सुखा पडे तो भी कच्छ की अधिकांश जमीन में पानी मिल जाएगा, जब कि अहमदाबाद जैसी जगह में दो लगातार सुखों में ही पानी गायब मिलेगा। इसके लिए लोकमान्यता है कि यहाँ जमीन के नीचे -नीचे सरस्वती नदी बहती है।"

आ. शुक्ल जी निबंध को गद्य की कसौटी मानते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, अज्ञेय, कुबेरनाथ राय, कृष्ण बिहारी मिश्र, विवेकी राम और रामवृक्ष बेनीपुरी आदि प्रमुख निबंधकार हैं।

प्राकृतिक उत्पात को दृष्टिकेंद्र में रखकर उसके माध्यम से राष्ट्रीय जीवन की बिकट-समस्या का प्रकटन निबंध विधा का एक ढंग है। निबंधकार कृष्णबिहारी मिश्र अपने समकालीन कृषक जीवन को उपरोक्त ढंग के प्रस्तुत करते हैं, जिसमें स्पष्ट हो जाता है कि किस प्रकार पूँजीपती वर्ग किसानों को दबोचे रहता है-

" बेहया दूसरों की बाढ को रोकने वाली वनस्पति है। जहाँ एक बार इसकी जड जम जाती है, वहाँ दूसरी वनस्पति का अस्तित्व खतरे में पड जाता है।"

इस प्रकार हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं में कृषक-जीवन को रुपान्वित करने का भरसक प्रयास किया गया है। आए दिन हो रही किसान आत्महत्याओं में वृद्धि को रोकने के लिए हमें विशेष प्रयासों की आवश्यकता है। हमें आशा है हिंदी साहित्य इस दिशा में विशेष सहयोगी होगा।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि,

1. हिंदी साहित्य ने कृषक जीवन की सारी पीडा, व्यथा, समस्याएँ तथा उसकी आत्महत्याओं के कारणों को खोज आंशिक रूप में समाधान देने का भी प्रयास किया है।
2. हिंदी साहित्य में उदृत किसान व्यथा को समझकर कृषक-जीवन अपने अभिभावकों का समर्थन प्राप्त कर सकता है।



3. हिंदी साहित्य की विभिन्न विधाओं ने अपने-अपने स्तर पर कृषक-जीवन को रूपान्वित करने को प्रयास किया है ।
4. कृषक जो कि संपूर्ण राष्ट्र तथा विश्व समाज का पालनहार होता है, उसके समर्थन में वैश्विक समाज को खड़ा रहना चाहिए ।
5. अतः कृषक के विकास में ही राष्ट्रीय उत्थान संभव है ।

संक्षेप में हिंदी साहित्य ने मध्ययुग से लेकर आज तक किसान जीवन की विभिन्न हरकतों को बयान करने की कोशिश की है । प्रत्येक युग का कवि, नाटककार, उपन्यासकार तथा निबंधकार उसे अपनी विधा का नायक मानता आया है । अतः सम्पूर्ण समाज कृषक-जीवन का लोहा मानता है । हमें संपूर्ण आदर के साथ कृषक जीवन का सम्मान करना चाहिए । उसके विकास में राष्ट्रीय उत्थान के मूल को स्वीकार कर, उसे न्याय दिलाने के लिए हिंदी साहित्य का यह प्रयास निश्चित रूप से जाया नहीं जायेगा ।

संदर्भ

1. मैथिलिशरण गुप्त- किसान ।
2. नागार्जुन-खिचड़ी विप्लव देखा हमने ।
3. विनोदकुमार श्रीवास्तव-'आमने-सामने', सच मैंने बनाए नहीं, पृ.45 ।
4. डॉ. विटोरे के.ए.-'तलाशता सब' -हमारा अन्नदाता ' पृ.20 ।
5. संपा. डा.कृष्ण शर्मा -कथा-चयन पृ.38 ।
6. डा. गिरीराज शर्मा, हिंदी नाटक:मूल्य संकमण पृ.133 ।
7. वही पृ.143 ।
8. डा.प्रकाश मोकाशी, यात्रा साहित्य: परिवेश व परिप्रेक्ष्य पृ.102 ।

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.



Current Global Reviewer

Peer Reviewed Multidisciplinary International Research Journal
PEER REVIEWED & INDEXED JOURNAL

ISSN 2319-8648

Impact Factor - 7.139 Indexed (SJIF)

March 2020

Special Issues- 25 Vol. 3

The Current Issues in Social Sciences in India (CISSI-2020)



Chief Editor
Mr. Arun B. Godam

Guest Chief Editor
Prof. Dr. B. D. Kokate (H/C Principal)

Dr. S. S. Undare (Vice Principal)
Dr. G. A. Mohite (Vice Principal)

Editor
Dr. R. K. Kale

Co-Editors
Dr. S. V. Akulwar
Dr. B. D. Jadhavar
Dr. S. E. Ghumatkar

Balhim Arts, Science & Commerce College, Heed



Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University Aurangabad &

M.S.P. Mandal's

Balbhim Arts, Science & Commerce College, Beed. (MS)

NAAC Reaccredited 'A+' Grade | College with potential for Excellence | UGC-Mentor College Under PARAMARSH

ONE DAY NATIONAL LEVEL SEMINAR

ON

The Current Issues in Social Sciences in India (CISSI - 2020)

Organized By

Department of Social Sciences

7th March 2020

CERTIFICATE

This is to certify that Prof./Dr./Mr./Mrs. MATHE PRASHANT MALKAPPA

of Dr. B.A.M.U. AURANGABAD has actively participated in One Day National Level Seminar

on 'The Current Issues in Social Sciences in India' (CISSI - 2020), organized by department of Social Sciences,

Balbhim Arts, Science & Commerce College, Beed (MS) held on 7th March 2020. He/She delivered a Key Note

Address / a Resource talk / Chaired a session/ Presented a Paper entitled RECENT ISSUES IN

CITIZENSHIP AMENDMENT BILL




Dr. G.A. Mohite
Vice Principal

Dr. S.S. Undare
Vice Principal & IQAC Coordinator


Dr. R.K. Kale
Organizing Secretary


Dr. B.D. Kokate
I/C Principal & Chief Organizer

CURRENT GLOBAL REVIEWER

Special Issue 25, Vol. 3
March 2020

Peer Reviewed
SJIF

ISSN : 2319 - 8648
Impact Factor : 7.139



Impact Factor – 7.139 ISSN – 2348-7143

Current Global Reviewer

Peer Reviewed Multidisciplinary International Research Journal
PEER REVIEWED & INDEXED JOURNAL

March 2020 Special Issue- 25 Vol. 3

The Current Issues in Social Sciences in India (CISSI-2020)

Chief Editor
Mr. Arun B. Godam

Guest Chief Editor
Prof. Dr. B. D. Kokate (I/C Principal)

Dr. S. S. Undare (Vice Principal)
Dr. G. A. Mohite (Vice Principal)

Editor
Dr. R. K. Kale

Co-Editors
Dr. S. N. Akulwar
Dr. B. D. Jadhavar
Dr. S. E. Ghumatkar

Balbhim Arts, Science & Commerce College, Beed

Shaurya Publication, Latur

CURRENT GLOBAL REVIEWERSpecial Issue 25, Vol. 3
'March 2020Peer Reviewed
SJIFISSN : 2319 - 8648
Impact Factor : 7.139

- | | | |
|-----|--|-----|
| 29. | भारतीय अर्थव्यवस्थेवर निश्चलनीकरणाचे परिणाम
डॉ. प्रकाश बाबुराव तितरे | 89 |
| 30. | नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - २०१९
प्रशांत मलकाप्पा माटे | 93 |
| 31. | राज्यपालाची राज्यप्रशासनातील भूमिका संघराज्य व्यावस्थेमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण करणारी आहे
प्रा.डॉ. प्रविण लोंगारकर | 95 |
| 32. | महिला सक्षमीकरणातील अडथळे
प्रेरणा दिलीप दीक्षित | 98 |
| 33. | भारताच्या आंतरराष्ट्रीय निर्यातीची वर्तमान प्रवृत्ती
डॉ. राजेश गायधनी | 102 |
| 34. | भारतातील दहशतवाद: समस्या आणि ऐतिहासिक पार्श्वभूमी
प्रा. डॉ. राजू भागाजी वनारसे | 108 |
| 35. | भारतातील आघाड्यांच्या राजकारणाचे यशापयश
प्रा.डॉ. संतोष एस. खत्री, राकेश भिमराव बोरसे | 114 |
| 36. | भारतातील निश्चलनीकरण: कारणे आणि परिणाम
कदम राम भोजु | 117 |
| 37. | भारतीय नागरिकत्व : भूमिका व स्थिती
डॉ. राम प्र.ताटे, डॉ. अर्चना शिवाजी वाघमारे | 120 |
| 38. | महिला सक्षमीकरण आणि भारतीय धोरण
प्रा. रामदास खताळ | 123 |
| 39. | भारतातील बेरोजगारीची सद्य:स्थिती, कारणे व उपाय
प्रा. जाधव रामेश्वर दत्तराम | 126 |
| 40. | भारतीय संयुक्त कुटुंब पद्धतीचे बदलते स्वरूप
प्रा.डॉ. प्रमिला जाधव, रसाळ मंजूषा मुरलिधर | 130 |
| 41. | भारतीय राजकारणात कलम 370 आणि कलम 35 - अ रद्द झाल्यामुळे होणारे बदल
ईश्वर नथु राठोड | 133 |
| 42. | भारतीय राजकारणासमोरील आव्हाने - जातीवाद
डॉ. रवींद्र एम. बेले | 135 |
| 43. | "महात्मा बसवेश्वरांच्या साहित्यातील सामाजिकता"
प्रा.डॉ. मनोहर सिरसाट, रेणुका शिर्वांग आप्पा संभाहरे | 137 |

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - २०१९**प्रशांत मलकाप्पा माठे**

संशोधक विद्यार्थी, (राज्यशास्त्र विभाग) डॉ. बा. आं.म.विद्यापीठ, औरंगाबाद

प्रस्तावना :

नागरिकत्व हा जगातील सर्वच राष्ट्रांसमोरील सर्वांत कठीण प्रश्न. तेथील राजकीय व्यवस्थेसमोर उभा असल्याचे दिसते. जगातील वेगवेगळ्या भागामध्ये लक्षावधी लोक स्थलांतर करताना आपल्याला दिसतात. धार्मिक, राजकीय अन्याय, बेकारी, युद्ध या कारणामुळे हे स्थलांतर होत आहे. स्थलांतरीतांना इतर राष्ट्रांनी आश्रय द्यावा का? सर्वच राष्ट्रांसमोर हा प्रश्न आहे.

पश्चिमात्य राजकीय विचारवंत अॅरिस्टॉटल नागरिकत्वाविषयी म्हणतो की, "राज्याच्या न्याय प्रशासनात आणि विधानसभेचा सदस्य या नात्याने कायदे निर्मित होत जाणारे लोक नागरिक म्हणायचे." अॅरिस्टॉटलचे नागरिकत्वासंबंधीचे विचार आजच्या काळात मर्यादीत स्वरूपाचे असल्याचे दिसते. आज २१ व्या शतकात नागरिकत्वाचा मुद्दा सर्वच राष्ट्रांसमोर उभा आहे. पश्चिमात्य राष्ट्रांनी नागरिकत्वावर कठोर निर्बंध लादलेले आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डॉनाल्ड ट्रम्प यांचा मेक्सिकोमधील स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना विरोध आहे. युरोपमध्ये स्थलांतर करणाऱ्या लोकांना आपल्या राष्ट्रात घेण्यास विरोध दर्शविला आहे.

भारतामध्ये १९४७ नंतर फाळणीच्या काळात नागरिकत्वाविषयी जटिल समस्या निर्माण झाली. भारत व पाकिस्तान राष्ट्र उदयास आले. हिंदूंनी भारताकडे आणि मोठ्या प्रमाणात मुस्लिमांनी पाकिस्तानात स्थलांतर केले. १९७१ मध्ये बांगलादेश अस्तित्वात आल्यानंतर त्या राष्ट्रातील बऱ्याच लोकांनी भारतात अवेद्यरित्या घुसखोरी करून भारतातील पुर्वोत्तर राज्यांमध्ये तेथील प्रशासकीय व्यवस्थेवर प्रचंड प्रमाणात ताण आणला.

१९५० मध्ये भारतीय राज्यघटनेत सर्व धर्म,वंश, पंथ, जाती, जमाती व विविध भाषा असणाऱ्या स्त्री पुरुषांना नागरिकत्वाचा समान दर्जा देण्यात आला आहे. १९५५ साली नागरिकत्वाचा कायदा करण्यात आला. त्यानुसार कोणत्याही व्यक्तीचा जन्म भारतात झाला असेल तर ती व्यक्ती नागरिक ठरते. वारसा हक्काने, दफतरी नोंदणीने नागरिकत्व मिळू शकते. नागरिकत्व संशोधन विधेयक २०१९ च्या कायद्याने भारतातील जनमानसात प्रचंड प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे.

संशोधनाचे उद्देश :

- १) नागरिकत्व संशोधन विधेयक - २०१९ समजून घेणे.
- २) नागरिकत्व सुधारणा विधेयक सद्यस्थितीतील उपयुक्तता जाणून घेणे.

नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - २०१९ :

११ डिसेंबर २०१९ रोजी लोकसभेत व ०९ डिसेंबर २०१९ रोजी राज्यसभेत हे विधेयक बहुमताने पारित झाले. राष्ट्रपतींनी या विधेयकावर १२ डिसेंबर २०१९ रोजी हस्ताक्षर केले. राष्ट्रपतींच्या मंजूरीनंतर या विधेयकाचे कायद्यामध्ये रूपांतर झाले आहे. या कायदानुसार -

- १) पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, बांगलादेश या तीन मुस्लिम राष्ट्रांतून धार्मिक छळामुळे जे हिंदू, शिख, ख्रिश्चन, पारशी हे भारतात आले आहेत, त्यांना नागरिकत्व दिल्या जाईल. परंतु ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत निर्वासीत आलेल्यांनाच नागरिकत्व मिळेल अशी अट या कायद्यात आहे.
- २) या कायदानुसार नागरिकत्व मागणाऱ्या व्यक्तीचे भारतात किमान ०५ वर्षे वास्तव्य असणे आवश्यक आहे. पुर्वी किमान ११ वर्षांचे वास्तव्य आवश्यक होते.
- ३) या कायदानुसार आसाम, मेघालय, मिझोराम व त्रिपुरा या राज्यातील आदिवासी समुदायासाठी हा कायदा लागू असणार नाही. कारण हे क्षेत्र संविधानाच्या सहाव्या अनुसूचित समाविष्ट आहे.
- ४) या कायदानुसार इनर लाईन परमिट (ILP) या क्षेत्रावर हा कायदा लागू असणार नाही. बंगाल पूर्वेसिमा विनियमन १८७३ नुसार (ILP - अरुणाचल प्रदेश, नागालँड आणि मिझोरामला लागू आहे.)
- ५) शेजारील तीन देशांतून अफगाणिस्तान, पाकिस्तान व बांगलादेशातून जवळपास ३१,३१३ लोक बऱ्याच वर्षांपासून विजावर राहतात. नागरिकत्व सुधारणा विधेयकामुळे त्यांना लगेच फायदा होईल. यामध्ये २५,००० च्या वर हिंदू, ५८०० शिख, ५५ ईसाई, आणि काही बौद्ध आणि पारशी नागरिकांचा समावेश आहे.

निष्कर्ष :

नागरिकत्व सुधारणा विधेयकाला देशभरातून विरोध आहे. याचे महत्वाचे कारण म्हणजे विरोधी पक्षातील लोक राजकीय सत्तेसाठी याचा वापर करीत आहेत. NPR- राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, NCR- नॅशनल सिटीजन ऑफ रजिस्टर, CAA - नागरिकत्व संशोधन अधिनियम यांचा मुळ उद्देश समजून न घेता लोकांमध्ये असंतोष वाढतांना दिसून येतो.

260



CURRENT GLOBAL REVIEWER

Special Issue 25, Vol. 3
March 2020

Peer Reviewed
SJIF

ISSN : 2319 - 8648
Impact Factor : 7.139

- १) या कायद्यामध्ये मुस्लिम समाजाबद्दल भेदभाव करण्यात आला आहे. राज्यघटनेतील समतेच्या कलम - १४ मांडलेल्या अधिकाराचा दुरुपयोग होत आहे.
- २) लोकांचा खरा विरोध राष्ट्रीय नागरिकत्व रजिस्टरला (NCR) आहे. आसाममधील निर्वासीत लोकांना या बाबतीत जे हाल सोसावे लागले ते इतर राज्यातील मुस्लिम, आदिवासी यांना भोगावे लागतील. कारण त्यांच्याकडे नागरिकत्व सिद्ध करण्यासाठी पुरेशी कागदपत्रे असतीलच असे नाही.
- ३) अफगाणिस्तान, बांगलादेश या देशाशी भारताचे मैत्रीपूर्ण संबंध प्राचिन काळापासून आहेत, ते संबंध बिघडण्याची शक्यता आहे.
- ४) आंतरराष्ट्रीय क्षेत्रामध्ये भारताची प्रतिष्ठा खराब होत असल्याचे दिसते.
- ५) भारतामध्ये सद्यस्थितीत अनेक प्रश्न नागरिकांसमारे आहेत. बेकारी, पायाभूत विकास, शेतकऱ्यांचे प्रश्न हा विचार न करता सरकारने नागरिकत्व विधेयक मांडून अडचण निर्माण केली आहे.
- ६) संयुक्त राष्ट्रांच्या मानवाधिकार पीठाने देखील भारत सरकारच्या या पक्षपाती कृतीचा निषेध केला आहे.

संदर्भग्रंथ :

- १) पाटील व्ही. बी. (२०१७), 'समग्र राज्यशास्त्र', के. सागर पब्लिकेशन, पुणे.
- २) जैन महेंद्र, (२०२०), 'प्रतियोगिता दर्पण मासिक', संपादक आग्र.
- ३) महाराष्ट्र ट्राईम्स (डिसेंबर - २०१९), 'संपादकीय लेख', औरंगाबाद आवृत्ती.
- ४) https://m.lokmat.com/national_citizenshipamendment.bill

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.



Current Global Reviewer

Peer Reviewed Multidisciplinary International Research Journal
PEER REVIEWED & INDEXED JOURNAL

ISSN 2319-8648

Impact Factor - 7.139

Indexed (SJIF)

March 2020

Special Issues - 25 Vol. 1

The Current Issues in Social Sciences in India (CISSI-2020)



Chief Editor
Mr. Arun B. Godam

Guest Chief Editor
Prof. Dr. B. D. Kokate (I/C Principal)

Dr. S. S. Undare (Vice Principal)
Dr. G. A. Mohite (Vice Principal)

Editor
Dr. R. K. Kale

Co-Editors
Dr. S. N. Akulwar
Dr. B. D. Jadhavar
Dr. S. E. Ghumatkar

Balhim Arts, Science & Commerce College, Beed

54

CURRENT GLOBAL REVIEWERSpecial Issue 25, Vol. 1
March 2020Peer Reviewed
SJIFISSN : 2319 - 8648
Impact Factor : 7.1

16.	Cashless Transaction And Its Impact On Indian Retail Sector Mr. Ghumbre Dhammpal Nivarattirao	56
17.	"Direction of the International Trade of India" Prof. Gopal Eknath Ghumatkar, Dr. Suresh Eknath Ghumatkar	60
18.	Secularism: A Constitutional Perspective Dr. Gore B.D.	64
19.	Indian Labour Movement : A Study Mr. Govind Nivrutirao Phad	66
20.	Living And Working Conditions And Problems Of Sugarcane Harvesters In Gokak Prof. S. B. Havannavar	71
21.	Role Of Ict In Rural Development Dr. J. B. Kangane	77
22.	Role of Information Technology In Improvement of Rural health care sector Dr. Jayashri T. Birdavade- Bhandwaldar	80
23.	'Green Audit : Base of Sustainable Development' Dr. Jeevan Sudamrao Gangane	87
24.	Relevance of Gandhiji's Socio - Economic Ideas in 21 st Century Dr. Kanya Wadhwa	90
25.	Impact of Rabindranath Tagore's Philosophy on Contemporary Indian Education Dr. Kanya Wadhwa	94
26.	Impact of FDI on Haryana's Export Dr. Kartik Arora	100
27.	Impact of FDI on Haryana's Gross Domestic Product: A Comparative study between Pre and Post New Industrial Policy Dr. Kartik Arora	104
28.	Castiesm Miss. Kamble Kusum Shivaji	109
✓ 29.	Changing Composition of India's Exports Trade During 1990-91 to 2000-01 Mrs. Champawati D. Wagh, Dr. Nanasahab R. Lavand	113
30.	Ethics in Governance Dr. M.F. Rautrahe	116
31.	Ethical Values for Good Governance Dr. Magar S. R.	118
32.	Role Of Ict In Higher Education Mr. Mane Sudhir Machindra	121
33.	Banking Sector Reforms In India	124



Changing Composition of India's Exports Trade During 1990-91 to 2000-01

Mrs. Champawati D. Wagh

Research Student, Dr. B.A.M. University, Aurangabad

Dr. Nanasaheb R. Lavand

Research Student, Dr. B.A.M. University, Aurangabad

Abstract :

The composition of India's Foreign trade has undergone potential changes after LPG. This study is focusing on changing composition of India's Export commodity goods and services. from 1990-91 – 2000-01. The dominance commodity contributor of India's export is manufactured goods. In this Items Engineering good is very dominance. Which constitute 46 percent of our basket. India is need to make its commodities more competitive at the world level. There is also required to add new commodities and services in the export basket. For this India needs to wide policy measure and integrated efforts.

KEYWORDS : Trade, Foreign Trade, Export ,Composition.

I) Introduction :

Foreign trade is one of the important sector in Indian Economy. Before Independence Indian Pattern of foreign trade was typically colonial. Since independence India had faced numbers of economic problems. Like adverse Bops. Due to all these factors India had devalue the rupee in 1947 and 1966. The purpose of devaluation was to reduce value of import and to boosts exports.

In 1991 the Government introduced some Changes in the trade policy. The main focus of these policies has been liberalization, openness and export promotion activity. India's foreign trade has exports significantly changed in the post reforms period. In absolute terms trade volume rose and the composition of exports has undergone several significant changes in post reforms period, the major exports growth has been manufacturing goods. Such as Engineering goods, Petroleum products, Chemical and allied products, Gems and Jewelleries, Textiles, Electronics Goods etc.

Indias share of world exports rose 1.71% in the first quarter of 2019. From 1.58% in fourth quarter of 2017. India's export of Goods and Services as percentage of GDP is 19.74% in recent year.

Finally, export and Import play a significant role in the economics development of all the developed and developing countries.

II) Meaning and Definition of Foreign Trade :

- i) **Trade** : The exchange of goods and services between to nations.
- ii) **Foreign Trade** : Foreign Trade is also known as external trade.
- iii) **Export Trade** : Goods and Services produced in a country and sold to another countries.

III) Objective of the Study :

To Study the Changing composition of India's export trade during first ten years of post reforms period.

IV) Hypotheses :

The Share has been increasing composition of India's export trade during post reforms period.

V) Review of Literature :

- i) **Mathor and Sagar (2015)**, Studied topic on compassion of India's export trade and concluded that manufacturing goods constitute over 80 percent of our export basket in recent year.
- ii) **Sahni (2014)**, Studied topic on The Changing structure of India's Export's and suggest that the share of agriculture and allied Products has been declining but share of manufactured goods has increased the study period.



VI) Data and Research Methodology :

Data : The Study uses fully secondary data published by Economic survey of India-various years. On composition of India's export of goods and or Export commodity.

The period of study is 1990-91, 2000-01. The limitation of study is only ten years (1990-91, 2000-01) has taken for the study.

Data analysis :

Table no. 1
Composition of India's Exports Basket

		Rs. Crore	
	Commodity	1990-91	2000-01
I	Agri and Allied products	6.317 (19.5)	28582 (14.0)
II	Ores and Minerals	1497 (4.4)	4139 (2.0)
III	Manufactured goods	23736 (73.0)	160723 (78.0)
IV	Minerals & Lubricants	948 (2.9)	8822 (4.2)
V	Total Exports	32553 (100.0)	203571 (100.0)

Source : Economic Survey 1990-91, 2000-2001

Note : figures in brackets are percentages of total

VII) Conclusions :

The composition of India's exports can be concluded as follows:

- Agri and allied product : The share of Agriculture items in the total exports of India has declined between 1990-91 to 2000-01. The share of agriculture exports was 19.5% in 1990-91, it's down to 14.0 percent in 2000-01. The share of Rice has increased but fish product share has came down.
- Ores and Minerals – The overall export performance of ores and minerals is not satisfactory. The export performance of ores and minerals has decreased from 4.4 percent in 1990-91 to 2.0 in 2000-01. A major share of ores and minerals exports comes from the exports of iron ore.
- Manufactured Goods In 1991 the share of manufactured items in the total export earning, was about 73 percent of the total export earnings. It increased to 78 percent in 2000-01. In percentage terms the Share of engineering goods, rose from 12.5 percent in 1990-91 to 20.7 percent in 2000-01.

Since 1991, largest export earnings came from the export of gems & Jewelry . The share of this items in India's total export was 15.3% in 1990-91 and 15.1% in 2005-06. The readymade garments maintained an almost constant Share all through study period.

- Mineral fuel and Lubricants-There has been improvement in the export of mineral fuels and Lubricants' In percentage its share has increased from 2.9% in 1990-91 to 4.2% in 2000-01

VIII) Suggestions :

- India need to make suitable policy changes in its foreign trade policy. FDI policy and FTP must be integrated for export promotion.
- For achieving 2 percent of worlds trade by year 2020. India should be provided by global market opportunities and environment.

CURRENT GLOBAL REVIEWER

Special Issue 25, Vol. 1
March 2020

Peer Reviewed
SJIF


ISSN : 2319 - 8648
Impact Factor : 7.139



- iii) India Needs to better facilities for fishery producer.
- iv) Government Needs to re-oriented pattern of its exports to more skills and knowledge intensive goods and services of competitive international quality.

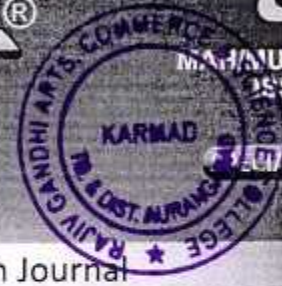
IX) Reference :

- 1) Government of India 'Economics Survey' 1990-91, 2009-10, 2013-14 and 2016-07, Oxford University Press New Delhi, India.
- 2) Gaurav Datta and Mahajan Ashvini (2016), 'Indian Economy', S. Chand Publication, New Delhi.
- 3) Sinha Manoj (2016), 'Structural change in composition of India's export during post-Economics Reform period', Business Analysis, ISSN 0973-211X, 37 (1)99-116(6).
- 4) Sahni P. (2014), 'Trends in India's Exports. A comparative study of pre and post Reform period, IOSR Journal of Economics and Finance 3,2(I),8.


PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.

विद्यावार्ता®



MA/ANUL/03051/2012
ISSN-2319 9318

ISSUE-2020 09

Peer Reviewed International Refereed Research Journal

प्रा. प्रशांत माटे

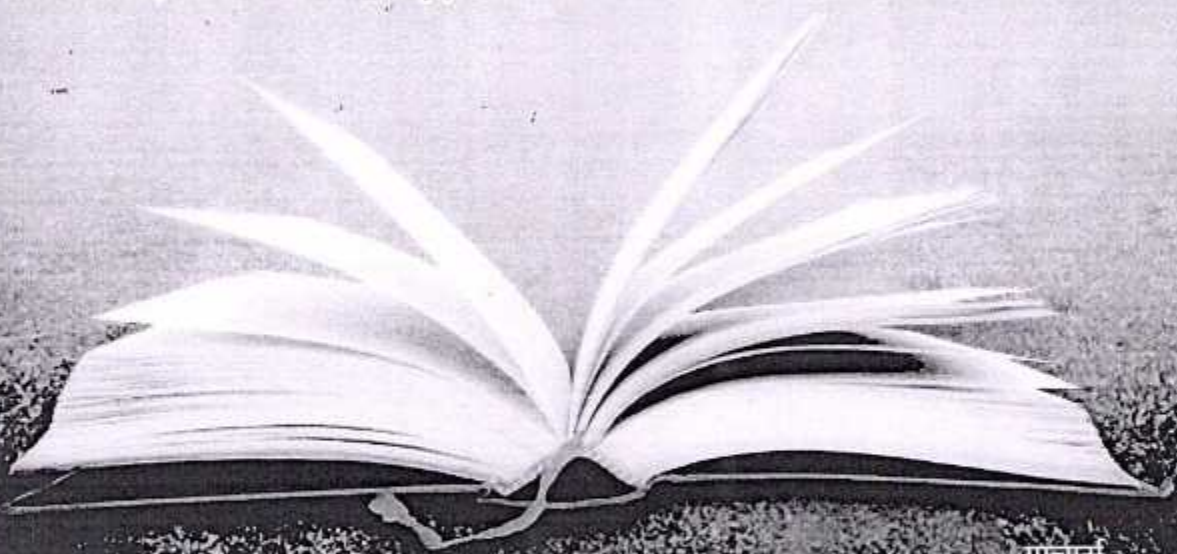


शंकरराव पाटील महाविद्यालय, भूम व
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

यांच्या संयुक्त विद्यमाने

“राजर्षी शाहू, महात्मा फुले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर
यांचे योगदान ” या विषयावर

एक दिवसीय राष्ट्रीय आंतरविद्याशाखीय परिषद



प्राचार्य

डॉ. श्रीकृष्ण चटनशिव

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318

Vidyawarta[®]
Peer-Reviewed International Publication

February 2020
Special Issue-09

01



MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318



शंकरराव पाटील महाविद्यालय, भूम
व

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद
यांच्या संयुक्त विद्यमाने
एक दिवसीय आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषद
२७/०२/२०२०

राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान

समन्वयक

प्रा. तानाजी बोराडे

डॉ. दयानंद शिंदे

डॉ. किशोरकुमार गव्हाणे

प्राचार्य

डॉ. श्रीकृष्ण चंदनशिव



Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh, Tq.Dist.Beed

Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295

harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

Vidya Vikas Mandal Pathrud's,

SHANKARRAO PATIL MAHARAJWADYALAYA

BHOOM

Tq. Bhoom Dist. Osmanabad-413504 (Maharashtra)

NAAC Re-accredited with 'B' Grade

(In Collaboration with Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad)



One Day Interdisciplinary National Conference

ON

" CONTRIBUTION OF SHANU MAHARAJ, MAHATMA PHULE & DR. BABASAHEB AMBEDKAR"

(27th February, 2020)

This is to certify that Prof./Dr./Shri./Smt./ Prashant Malkappa Mhatre

of Student, Aurangabad has participated in One Day Interdisciplinary National Conference on "Contribution

of Shahu Maharaj, Mahatma Phule & Dr. Babasaheb Ambedkar" organized by IQAC of Shankarrao Patil Mahavidyalaya,

Bhoom, Dist. Osmanabad On Thursday, 27th February, 2020. He/She Participated / Chairzed a session / Presented a paper

on श्री शानु महाराज महात्मा फुले व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विसमिती वार्षिक

Prof. Tanaji Borade
Convener

Dr. Anuradha Jagdale
Coordinator, IQAC

Dr. Shrikrishna Chandanshiv
Principal

12) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक व आर्थिक विचार डॉ. गायकवाड आर. डी, डॉ. ब्रारवकर पी. आर., मुक्तम	47
13) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार व सद्यस्थिती डॉ. जाधव जालु कन्हैयालाल, बीड	50
14) डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचो प्रसंगिकता डॉ. एन. आर. लावंड, श्रीमती. सी. डी. वाघ, औरंगाबाद	52
15) जाणता राजा छत्रपती राजर्षी शाहू यांचे सामाजिक योगदान प्रा. गायकवाड डी. डी., उस्मानाबाद	54
16) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजकीय विचार प्रशांत मलकप्या माठे, औरंगाबाद	56
17) मा. ज्योतिबा फुले यांचे शेतीविषयक विचार - काल, आज आणि उदया..... डॉ. देविदास नागरगोजे, डॉ. सावळे एकनाथ ग्यानोबा, बीड	58
18) राजर्षी शाहू महाराज आणि स्त्री मुक्ती विषयक कार्य प्रा. नागभिडे निल, उस्मानाबाद	62
19) कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आश्रु पांडुरंग मोरे, निलेश शशिकांत खिल्लारे, औरंगाबाद	64
20) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक योगदान प्रा. रसाळ मंजुषा मुरलिधर, चौसाळा	66
21) आंबेडकरी स्त्रीवाद डॉ. सारिका अशोकराव बुरगे, बीड	69
22) छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे आरक्षण विषयक विचार प्रा. राठोड बी. जे., बीड	71
23) राजर्षी शाहू महाराज : सामाजिक लोकशाहीचा पुरस्कर्ता डॉ. मुंडे सविता गंगाधरराव, जालना	74

गौरव केला जातो. सामाजिक न्यायाची भूमिका घेऊन शाहू राजांनी सामाजिक समतेसाठी प्रयत्न केले.

शाहूंनी कोल्हापूर संस्थानात संगीत, चित्रपट, चित्रकला, लोककला आणि कुस्ती या क्षेत्रातील कलावंतांना राजाश्रय देवून त्यांना प्रोत्साहन देण्याचे कार्य केले.

महाराजांनी कोल्हापूर, बेळगाव या भागातील स्वातंत्र्यवीराना वेळोवेळी आर्थिक व इतर मदत केली. शाहू महाराज व डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संबंध चांगले होते. डॉ. बाबासाहेबांनी मुकनायक हे साप्ताहिक ३१ जानेवारी १९२० ला प्रथम प्रकाशित केले. परंतु आर्थिक अडचणीमुळे पुढे ते बंद पडले. परंतु हे राजर्षी शाहू महाराजांच्या लक्षात आल्यावर त्यांनी तत्काळ आर्थिक मदत केली.

सारांश :

देशातील समाजसुधारकांच्या यादीत शाहू राज्यांच्या स्त्री स्वातंत्र्य, शिक्षण, अस्पृश्यता, जातीभेद-वाद या बहुजन समाजाला बुरसटलेल्या विचारांवर प्रहार करत या देशातील बहुजन समाजाला समतेचे जीवन देणाऱ्या कार्यामुळे अगुस्थानी आढळते. समता, बंधुता, एकात्मता ज्यांच्या कृतिशील कार्यातून या समाजाला शिकवून मिळाली. क्रांतीसुर्य शाहू महाराजांनी छत्रपती शिवरायांच्या विचारांचे वारसा ठरून या देशाला समानतेचा संदेश देऊन जाती, भेद, वर्ण, भेद अस्पृश्यता यात बुरसटलेल्या समाजाला एक नवी दिशा देऊन या बहुजन समाजात लोकशाहीची मुहूर्तमेढ रोवणारे एक महान जाणता राजा म्हणून ओळखले जाते. या कार्यामुळेच बहुजनांत एक माणूस म्हणून जगण्याची हिंमत मिळाली आहे.

संदर्भ ग्रंथ :

१. राजर्षी शाहू छत्रपती - डॉ. धनंजय किर
२. राजर्षी शाहू स्मारक-ग्रंथ - डॉ. जयसिंगराव पवार
३. राजर्षी शाहू व माणूस - क.गो. सुर्यवंशी
४. मुलभूत सामाजिक विचार - डॉ. ज्योती डोईफोडे
५. Inter Net



16

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजकीय विचार

प्रशांत मलकप्पा माटे

संशोधक विद्यार्थी,

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद

प्रस्तावना :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजकीय विचार हे भारतीय विचारवंतांना प्रेरणा देणारे विचार होते. आंबेडकर यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात इ.स.१९१९ पासून झालेली होती. आंबेडकरांनी भारतीय जनतेस सविधानाच्या माध्यमातून एक अनमोल देणगी दिलेली आहे. भारतातील सामाजिक, आर्थिक व सामाजिक संरचना यांचा अभ्यास करून भारतीय राज्यघटनेच्या माध्यमातून जनतेस अद्वितीय हक्क प्रदान केले आहेत. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी राजकारणातून सामाजिक बदल करण्याचे प्रयत्न केले आहेत. साऊथबरो कमिशनला दिलेले निवेदन व साक्ष, सायमन कमिशन, गोलमेज परिषदांतील कार्य, जातीय निवाडा, पुणे करार, १९३५ चा कायदा, स्वतंत्र मजूर पक्ष आणि शेड्यूल कास्ट फेडरेशनची केलेली स्थापना या बाबासाहेबांच्या जीवनातील महत्त्वाच्या राजकीय घटना आहेत.

अस्पृश्यांच्या मुक्तिसंग्रामासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या वृत्तपत्रांना जन्म दिला. त्यांनी स्थापन केलेल्या 'बहिष्कृत भारत' या वृत्तपत्रातून समाज, धर्म, संस्कृती, राजकारण, शिक्षण या विषयावर त्यांनी आपले विचार प्रगट केलेले आहेत. मुकनायक, बहिष्कृत भारत, जनता व प्रबुद्ध भारत या चारही वृत्तपत्रातील लेखन करतांना आपले विचार मात्र त्यांनी मायबोलीतूनच व्यक्त केलेले आहेत.

भारताच्या स्वातंत्र्य संग्रामात डॉ. आंबेडकर यांचे राजकीय विचार स्वातंत्र्यासाठी मोठ्या प्रमाणात प्रेरक ठरले होते.

संशोधनाचा उद्देश :

१. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांचा अभ्यास करणे.

२. आंबेडकरांच्या राजकीय विचारांची सद्यस्थितीतील उपयुक्तता जाणून घेणे.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार :

१. लोकशाहीसंबंधी विचार :

लोकशाही हा आंबेडकरांचा सतत चिंतनाचा विषय राहिला आहे. आंबेडकरांनी लोकशाही म्हणजे समता असे लोकशाहीचे वर्णन केले आहे. लोकशाहीच्या संदर्भात डॉ. आंबेडकर म्हणतात "ज्याच्या योगाने लोकांच्या सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात रक्तपाताशिवाय क्रांतिकारक बदल घडवून आणता येतात अशी शासनपद्धती म्हणजे म्हणजे लोकशाही." अशी व्याख्या केली आहे.

संसदीय लोकशाही व्यवस्था ही सीमित शासनाचा आदर्श असल्यामुळे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सांसदीय लोकशाहीचे समर्थन करतात. आज जगातील जवळपास १५० राष्ट्रात लोकशाही शासनपद्धतीचा अवलंब केलेला आहे. लोकशाही पद्धती ही खऱ्या अर्थाने सामाजिक समता, हक्क आणि विकासाच्या दृष्टिने अत्यंत महत्त्वाची असल्याचे दिसून येते.

१. साऊथवरो कमिटी :

मतदानाच्या हक्काबद्दल आढावा घेण्यासाठी इ.स.१९१९ मध्ये साऊथवरो कमिटी इंग्लंडहून भारतात आली. साऊथवरो कमिटीला त्यांनी दिलेले निवेदन व साक्ष ही त्यांच्या राजकीय जीवनाची सुरुवात होती. डॉ. आंबेडकरांनी अस्पृश्यांसाठी मतदानाचा अधिकार असावा, निवडणुकीस उभे राहण्याचा अधिकार, स्वतंत्र मतदार संघ असावा, एक व्यक्ती एकमत, एक मूल्य, लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्यांना जागा द्याव्यात मागण्या मांडल्या होत्या.

भारतीय स्वातंत्र्यानंतर अस्पृश्यांसाठी राखीव जागा, स्वतंत्र मतदार संघ, एक व्यक्ती एकमत, हे भारतीय राज्यघटनेत समाविष्ट करून सामाजिक समता निर्माण केल्याचे दिसून येते.

२. स्वतंत्र मजूर पक्षाची स्थापना :

१९३५ च्या कायद्याने प्रांतिक स्वायत्ता मिळून नविन सरकारे स्थापन होणार होती. डॉ. आंबेडकरांनी १९३६ मध्ये 'स्वतंत्र मजूर पक्ष' नावाचा राजकीय पक्ष स्थापन केला. स्वतंत्र मजूर पक्षाचे 'जनता' हे मुखपृष्ठ होते.

स्वतंत्र मजूर पक्षाचे ध्येयघोरण हे समाजातील कष्टकरी वर्ग, कष्टकरी जातींच्या वर्गांचे हित पाहणे असे होते. परंतु या पक्षास सर्व जातींचे पुरेसे पाठबळ मिळाले नाही. इ.स.१९३७-३९ च्या काळात स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या आमदारांनी मंबई कायदेमंडळात चांगली कामगिरी पार पाडली होती.

डॉ. आंबेडकरांनी या पक्षाची स्थापनाच सर्व जातींच्या

कष्टकऱ्यांचे जीवनमान उंचावणे, त्यांना त्यांच्या हक्काची जाणीव करून देणे, त्यांना पुरेसे प्रतिनोधीत्व मिळण्यासाठी प्रयत्न करणे या हेतुने केलेली होती. पुढे १९४२ मध्ये डॉ. आंबेडकरांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाचे विसर्जन करून 'अखिल भारतीय शेड्युल्ड कास्ट फेडरेशनची' स्थापना केली.

३. भारताची एकता निर्माण करणे :

डॉ. आंबेडकरांनी सायमन कमिशनपुढे प्रामुख्याने भारताच्या एकात्मतेची आणि राष्ट्रीय भावनेच्या जोपासनेची वाजू मांडली. त्यांनी काही गोष्टींना विरोध केला. कायदेमंडळात मागासवर्गीयांसाठी राखीव जागा ठेवणे, कर्नाटकच्या कानडी भाषिकांचा स्वतंत्र प्रांत बनविणे, स्वतंत्र सिंध प्रांत करणे, बहुसंख्य मुसलमान संख्या असलेले प्रांत बनविणे, इ.

आंबेडकरांनी भारतासाठी एकात्मता निर्माण करण्यासाठी व सर्व जातींच्या वर्गांना समान व कायदेशीर राज्यघटनेच्या माध्यमातून त्यांना हक्क प्राप्त करून देण्यासाठी त्यांनी राज्यघटनेचा इतर देशातील राज्यघटनेचा अभ्यास करून भारतीय जनतेस एक चांगल्या प्रकारे घटना देण्याचा प्रयत्न केलेला दिसून येतो. म्हणूनच भारताने संघराज्यात्मक शासन पद्धतीचा स्वीकार केलेला आहे.

सारांश :

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या एकदरीत राजकीय विचारांच्या अभ्यासातून असे दिसून येते की, त्यांनी भारतीय जनतेस संविधानाच्या माध्यमातून महत्त्वाचे स्थान दिलेले आहे. त्यांचे राजकीय विचार आजच्या २१ व्या शतकात माणसाच्या व समाजाच्या उन्नतीसाठी व जगातील लोकशाही राष्ट्र निर्माण करण्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहेत. आज जगात भारताच्या लोकशाही प्रणालीचा अभ्यास इतर राष्ट्रांसाठी प्रेरणादायी ठरल्याचे अभ्यासातून दिसून येते.

संदर्भ ग्रंथ :

१. कांबळे विजया (२०१३), 'बहिष्कृत भारतातील विचारविश्व' गोदा प्रकाशन, औरंगाबाद.

२. कठारे अनिल, पाटोल गौतम, वाघमारे महादेव (२००९), महाराष्ट्रातील आंबेडकर चळवळीचा इतिहास' प्रथमावृत्ती, चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद.

३. आंबेडकर बाबासाहेब, माझी आत्मकथा, योगेश प्रकाशन, वर्धा.

४. Kamble B.K.(२०१०), Mook Nayak (A News paper in Marathi) Published Dr. B.A. Research Institute in Social Growth, Kolhapur.

□□□

MAH/MUL/03051/2012

ISSN :2319 9318



शंकरराव पाटील महाविद्यालय, भूम
व

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद
यांच्या संयुक्त विद्यमाने

एक दिवसीय आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषद
२७/०२/२०२०

राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान

समन्वयक

प्रा. तानाजी बोराडे

डॉ. दयानंद शिंदे

डॉ. किशोरकुमार गव्हाणे

प्राचार्य

डॉ. श्रीकृष्ण चंदनशिव



Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com



- 28) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी आणि काले माक्स
प्रा.डॉ. पुरुषोत्तम शेषराव जुने, जि. जालना ||109
- 29) राजर्षी शाहू महाराज आरक्षण विषयक विचार
प्रा. डी. सी. जी. कडेकर, जी. उस्मानाबाद ||113
- 30) डॉ. भीमराव अम्बेडकर दलितों के मसीहा
प्रा. चालिका रामराव कांबळे, जि.लातूर ||116
- 31) फुले, शाहू, आंबेडकर यांचे शैक्षणिक विचार
श्रीमती रंजना जनार्दन गवळी (कांजुणे), दौलताबाद ||117
- 32) दलितोद्धार आंदोलन में महात्मा फुले जी का योगदान
डॉ.सौ. कटारे मंगला श्रीराम, जि.लातूर ||120
- 33) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या राजकीय चिंतनाची प्रासंगिकता
प्रा. किर्तीकर वाल्मीक भीमराव, सोलापूर ||122
- 34) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांची राज्य-समाजावादाबाबतचे विचार
प्रा. लांबड पंडित महादेव, वार्शी ||124
- 35) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे आर्थिक विचार : एक अभ्यास
प्रा. माळगे सविता शंकरराव, जि.उस्मानाबाद ||127
- 36) महात्मा जोतिबा फुले यांचे स्त्री विषयक विचार आणि कार्ये
प्रा. मनोज व. देवकर, ता.जि.औरंगाबाद ||130
- 37) शाहू महाराजांच्या आर्थिक धोरणांची सर्वसमावेशकता
प्रा. शेळके सी. एस., ता.जि. बीड ||132
- 38) महात्मा फुले : भाषा आणि साहित्य
डॉ. गोवर्धन काशीनाथ मुळक, जि. जालना ||135
- 39) महात्मा जोतिबा फुले यांचे आर्थिक विचार
डॉ. मुळे पी. एम., जि. बीड ||138
- 40) राजर्षी शाहू महाराज, म.फुले, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक विचार
पांडरकर श्रीधर मुरलीधरराव, परभणी ||141

आयोग नेमला जातो. डॉ. आंबेडकरांचे या संबंदातील विचार पायाभूत मानावे लागतील.

४. शेतजमीन आणि अवजड उद्योगधंद्यावर सामुदायिक मालकी असावे, उत्पादनाचे लोकशाही पद्धतीने भेदभाव न करता वाटप व्हावे अशी त्यांची भूमिका होती.

५. अर्थव्यवस्थेच्या व प्रामुख्याने शेती विकासासाठी डॉ. आंबेडकरांनी जलसंधारण विकासासाठी नवीन व्यवस्था निर्माण करून दिली व हे करत अशांना त्याचा फायदा सर्वांना होईल याची काळजी घेतली.

संदर्भ ग्रंथ सुची :-

१. जाधव नरेंद्र, डॉ. आंबेडकरांचे अर्थशास्त्रीय लेख (अर्थशास्त्रीय लेख)

२. पाटील जे. एफ., आर्थिक विचारांचा इतिहास.

३. डॉ. कुलकर्णी वी.डी., आर्थिक विचार व विचारवंत

४. डॉ. आंबेडकरांचे आर्थिक विचार, पान : ६- डॉ. डी. आर. जाटव.

५. पवार दया, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ - १९९३.

६. मृणालकर भालचंद्र, नवीन आर्थिक धोरण - आंबेडकर प्रणित दृष्टीकोन, सत्राय प्रकाशन, पुणे.

७. गवळी पी. ए., डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर गौरव ग्रंथ प्रचार प्रकाशन, कोल्हापूर, प्रथम आवृत्ती १९९१

८. धुमाळ व्ही. एन., डॉ. बाबासाहेबांचे आर्थिक विचार, २०१३

□□□

महात्मा जोतिबा फुले यांचे स्त्री विषयक विचार आणि कार्ये

प्रा. मनोज व. देवकर

इतिहास विभाग प्रमुख,

राजीव गांधी कला, वाणिज्य व विज्ञान महाविद्यालय करगाड,
ता.जि.औरंगाबाद

प्रस्तावना :

महात्मा फुले हे भारतीय इतिहासातील आद्य समाज सुधारक, आपले विचार प्रत्यक्ष आचरणात आणणारे बंडखोर युगपुरुष होते. महाराष्ट्रातील अस्मृश्यता निवारण व स्त्रीमुक्ती चळवळीचे आग्रणी म्हणून ओळखले जातात. तत्कालीन समाजातील विषमता, जातीभेद, अज्ञान, स्त्रीदास्य यासारख्या अनिष्ट प्रथा या सर्वांच्या निर्मुलनाकरिता कार्य करत असतांना त्यांनी शिक्षण हे अत्यावश्यक असल्याची जाणीव तत्कालीन समाजाला करून दिली. त्यांनी महिलांसाठी कार्ये करतांना स्त्री शिक्षण, बालविवाह, विजोड विवाह, केशवपन या सारख्या प्रथांवर लक्ष केंद्रीत करून स्त्रीयांची या अनिष्ट प्रथामुळे होणारी अवहेलना व छळ थांबवण्यासाठी महत्वपूर्ण कार्ये केल्याचे दिसून येते. समाजातील शोषित वर्गाचा केवळ होऊन त्यांना त्यांचे नैसर्गिक अधिकार मिळवून देण्यासाठी महात्मा जोतिबा फुले जन्मभर झगडले. त्यावेळच्या समाजात विषमता, जातीभेद, अज्ञान, स्त्रीदास्य यासारख्या अनिष्ट समस्या केवळ धर्मांमुळे वाढल्या होत्या हे ओळखून स्वातंत्र्य, समता, बंधुता व न्याय या तत्वांचा पुरस्कार करून महात्मा फुले यांनी धर्म व समाजाच्या परंपरेने जखडलेल्या स्त्रियांना मुक्त करून त्यांच्यात आत्मभान निर्माण करण्याचा प्रयत्न त्यांनी केला.त्यांनी आपल्या लेखनीतून स्त्रियांचे प्रश्न समाजापुढे मांडले. स्त्रियांना समाजप्रबोधनाच्या चळवळीत सहभागी करून घेतले. महात्मा फुले यांनी स्त्रियांच्या उन्नतीसाठी कार्ये करतांना स्त्री शिक्षणाला प्राधान्य देऊन पुढील बाबतीत स्त्रियांसाठी कार्ये केले.

स्त्री - शिक्षण :



या काळात सनातनी लोकांच्या मते स्त्रियांना शिक्षणाचा अधिकार नाही. त्यांना शिक्षण देणे म्हणजे धर्म बुडविण्यासारखे आहे. स्त्रीला शिक्षण दिले तर ती कुमार्गाला लागेल आणि घरातील सुख शांती नष्ट होईल. तसेच मुलींनी शिक्षण घेतले तर अकाली वैधव्य येईल. अशा खूळचट कल्पना होत्या. महात्मा फुले यांनी या खूळचट कल्पनांना तडा देण्याचे काम केले. सनातन्यांना प्रत्युत्तर देण्यासाठी तसेच त्यांच्या मते स्त्रियांवर अन्याय, अत्याचार हे केवळ त्या अज्ञानी असल्यामुळे होतात म्हणून त्यांनी स्त्रीशिक्षणाचे कार्य हाती घेतले. स्त्री शिक्षण म्हणजे तींच्या मुलांचे शिक्षण, आपण जर एका पुरुषाला शिक्षण दिले तर ते त्याच्या एकट्यापुरते राहते. मात्र एका स्त्रीला जर शिक्षण दिले तर ते संपुर्ण कुटुंबाला शिक्षण दिल्यासारखे आहे. शिक्षण घेऊन स्त्री आदर्श माता, पत्नी, भगिनी, कन्या बनायी असा त्यांचा हेतू होता. म्हणून त्यांनी स्त्री शिक्षणाला प्रारंभ केला. स्त्रियांना मिळणारी सामाजिक उपेक्षा थांबवण्यासाठी १८४८ साली त्यांनी देशातील मुलींची पहिली शाळा पुण्यातील भिडे वाड्यात सुरू केली. जीच्या हाती पाळण्याची दोरी ती जगाले उद्धारी असे स्त्रीचे महत्त्व त्यांनी विशद केले. मुलींसाठी स्वतंत्र शाळा काढणारे जोतिबा हे पहिले भारतीय होते. सामाजिक रोषाच्या भितीने मुलींना शिकवण्यासाठी कोणीही शिक्षक मिळत नव्हता म्हणून त्यांनी आपली पत्नी सावित्रीबाई यांना शिकवून शाळेत शिक्षक म्हणून नियुक्त केले. सनातन्यांना ही घटना देशद्रोहासारखी वाटली. त्यांच्यात संतापाची लाट आली. त्यांनी शाळेत जाता येतांना सावित्रीबाईंना त्यांच्या अंगावर चिखल फेकणे, घाण टाकणे, दगड मारणे, अपशब्द उच्चारणे अशा प्रकारे त्रास देण्यास सुरुवात केली. परंतु या त्रासामुळे सावित्रीबाई आणि जोतिबा दोघेही डगमगले नाहीत. त्यांनी इ.स.१८५१ मध्ये बुधवार पेठेत दुसरी शाळा सुरू केली. याच वर्षी रास्ता पेठेत तिसरी शाळा सुरू केली. १८५२ मध्ये येताळ पेठेत चौथी शाळा सुरू केली. या कार्याला व्यवस्थित स्वरूप प्राप्त होण्यासाठी त्यांनी आपल्या मित्रांच्या मदतीने एक कार्यकारी समिती स्थापन केली. अशा प्रकारे महात्मा जोतिबा फुले यांनी स्त्री शिक्षणाला एक वेगळी दिशा देण्याचे कार्य केले. बालविवाह बंदी :

बाल विवाहाच्या रुढ झालेल्या प्रथेमुळे समाजात बाल विधवांचे प्रमाण झपाट्याने वाढत होते. अल्पवयात विवाह केल्यामुळे मुलींना भावी आयुष्यात अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत असे. बालविवाहातूनच बिजोड विवाह प्रथा वाढीस लागत होती. या सगळ्यांना महात्मा फुले यांनी विरोध केला व बालविवाह होऊ नये यासाठी सामाजिक जागृती घडवून आणण्याचे कार्य

महात्मा फुले यांनी केले.

केशवपन प्रथेला विरोध :

सतीच्या अनिष्ट प्रथेला १८२९ साली सरकारी पायबंद बसला असला तरी विधवांना अत्यंत कष्टमय जीवन जगावे लागत होते. पती निधनानंतर स्त्रीने आपले चारित्र्य जपले पाहिजे यासाठी तीचे केशवपन करून तीला विद्रुप करण्याची अनिष्ट प्रथा प्रचलीत होती. यातून स्त्रीची होणारी कुचंबना थांबवण्यासाठी व तीला सन्मानाने समाजात जगता यावे यासाठी केशवपन विरोधी चळवळ त्यांनी सुरू केली. धर्म कल्पनेतील फोलपणा सिद्ध करून अनिष्ट प्रथा स्त्रियांच्या व्यक्ती स्वातंत्र्याची कशी गळचेपी करतात हे ज्योतिबांनी लोकांना सांगण्याचा प्रयत्न केला.

विधवा पुनर्विवाह :

तत्कालीन सनातनी समाजाने स्त्री मग कोणत्याही वर्गातली असली तरी तीची शूद्रात गणना केली होती. बाल विवाहामुळे विधवांचे प्रमाण जास्त होते. पती निधनानंतर नंतरचे आयुष्य स्त्रीला अतिशय क्लेशदायक परिस्थितीत अपमानित होऊन मानसिक गुलामगिरीत व्यतीत करावे लागत असे. त्यांचे राहणीमान, आहार या सर्व गोष्टींवर मर्यादा घातलेल्या होत्या. तीला चांगले कपडे परिधान करता येत नव्हते., गोडघोड खाणे, दागदागिने वापरणे यावर देखील निर्बंध होते. त्यांना लग्न समारंभ, उत्सवांमध्ये सहभागी होता येत नव्हते.

अशा प्रकारे स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय, अत्याचाराच्या विरोधात महात्मा फुले यांनी विधवा पुनर्विवाहाची चळवळ सुरू केली. त्यांच्या या चळवळीचा परिणाम म्हणून २५ जुलै १८५६ रोजी विधवा पुनर्विवाहाचा कायदा सरकारने समत केला. त्यांनी १८६४ मध्ये शेणयी जांतीतील रघुनाथ जनार्दन या विधुराचा नर्मदा या विधवेशी पुनर्विवाह घडवून आणला.

बालहत्या प्रतिबंधक गृह :

बालपणीच स्त्रियांचे विवाह होत असल्यामुळे तत्कालीन समाजात बालविधवांचे प्रमाण जास्त होते. त्यामुळे अशा विधवेचे चुकून वाकडे पाऊल पडले तर संतती निर्माण होत असे. अशावेळी समाजापासून स्वतःला वाचविण्यासाठी गरोदर विधवा व जन्माला येणा-या बाळाची हत्या करत असत. अशा स्त्रियांची समाजात विटंबना होऊन छळ होत असे. त्यामुळे या विधवांची या आपत्तीतून सुटका व्हावी म्हणून जोतिबांनी विधवांना गुप्त येऊन बाळंत होण्यासाठी १८६३ मध्ये आपल्या घराजवळ बालहत्या प्रतिबंधक गृह उभारले. त्याचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी भितीपत्रके वाटण्यात आली. त्यात 'विधवांनो इधे येएफन गुप्तपणे व सुरक्षितपणे बाळंत

हा. तुम्ही आपले मूल बरोबर न्याचे किंवा इथेच ठेवावे त्या मुलाची काळजी ह अनाथाश्रम घेईल'. जोतिबांनी सुरु केलेले बालहत्या प्रतिबंधक गृह हे भारतातील पहीलेच होते. अशा मुलांची सर्व सेवा करण्याचे काम महात्मा फुले व सावित्रीबाईंनी केले. आपल्याला संतती नाही म्हणून दुसरा विवाह न करता बाल हत्या प्रतिबंधक गृहातीलच मुलगा यशवंत याला जोतिबांनी दत्तक घेतले.

या बरोबरच महात्मा फुले यांनी तत्कालीन बहुपत्नीत्या च्या प्रथेला देखील विरोध केला. पहिली पत्नी जीवंत असतांना दुसरी पत्नी करणे हा निंदनिय प्रकार आहे असे ते मानत होते. ते या संदर्भात म्हणतान, पुरुषांना जास्त वायका करण्याचा अधिकार आहे तर मम स्त्रियांनी मुकापेक्षा जास्त नवरे केल्यास चकीचे होणार नाही. ही गोष्ट जर पुरुषांना सहन होणार नसेल तर ती स्त्रियांनी तरी का सहन करावी.

समारोप :

महात्मा फुले यांनी तत्कालीन समाजात स्त्रियांच्या प्रश्नांना वाचा फोडली. त्यांच्यावर होणारा अन्याय, त्यांची होणारी कुचंबना थांबवण्यासाठी स्त्रियांसाठी शिक्षणाची दारे खुली केली. मुर्तीसाठी तत्कालीन सनातनी समाजाचा विरोध सहन करीत शाळा सुरु केली. वाचबरोबर थालविवाह, जरठ विवाह, केशवपन, वाघ्या-मुरळी यासारख्या अनेक प्रथा तत्कालीन समाजात होत्या. या विरोधात महात्मा फुले यांनी चळवळ सुरु केली. म्हणून महात्मा जोतिबा फुले यांना स्त्रियांचे कैवारी समजले जाते.

संदर्भग्रंथ :

- 1) अनुराधा गट्टे, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाई फुले (चरित्र)
- 2) तानाजी ठोंबरे, महात्मा फुले यांचे शैक्षणिक कार्य.
- 3) महात्मा फुले जीवन आणि कार्य (संपादीत) प्रकाशक, भारतीय विचार साधना प्रकाशन, पुणे.
- 4) महात्मा ज्योतिबा फुले यांचा सार्वजनिक सत्यधर्म (संपादीत) प्रकाशक श्री. गजानन बुक डेपो.
- 5) दत्ता जी. कुलकर्णी, महात्मा फुले सामाजिक क्रांतीचे अग्रदूत

□□□


PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TG. & DIST. AURANGABAD.

शाहू महाराजांच्या आर्थिक धोरणांची सर्वसमावेशकता

प्रा. शंळके सी. एस.

सहयोगी प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग,
कला व विज्ञान महाविद्यालय चौसाळा, ता. जि. बीड

प्रस्तावना :-

शाहू छत्रपतींची कोल्हापूरत राजवट सुरु झाली तेव्हा राज्यकारभारात इंग्रज, पारशी व ब्राम्हण यांचे प्रभुत्व होते. त्यामुळे तत्कालीन प्रस्थापिताकडून शाहू महाराजांच्या राजवटीचा मत्सर व द्वेष केला जात होता. बरीच वर्षे स्वतः कोल्हापूरच्या राजाच्या हाती सुत्रे नसल्यामुळे तेथील ब्रिटिश सत्ताधारी जुलमी हुकूमशा बनले होते. ब्रिटिश वरिष्ठ अधिकारी उद्धटपणे वागत होते. तेथील ब्रिटिश सत्ताधारी आणि अधिकारी स्वतःला छत्रपती शाहू महाराज समकक्ष मानत होते.

राजर्षी शाहू महाराज हे स्वतःचे राजे होते. मानवतेच्या मानवतेवर प्रेम करणारा राजा म्हणून शाहू महाराजांची संपूर्ण समाजाला ओळख आहे. शाहू महाराज हे केवळ राजे नव्हते तर सामाजिक क्रांतीचे एक दीपस्तंभ होते. त्यांनी आपल्या विचार व क्रांतीच्या माध्यमातून सामाजिक कार्य केलेले आढळून येते. त्यांना सामाजिक अन्याय आणि विषमतेविरुद्ध चीड होती. समाजातील तळागाळातील माणसाच्या उन्नतीविषयी आस होती. त्यांनी हाती आलेल्या सत्तेचा वापर सामाजिक न्यायाच्या भूमिकेतून केलेला दिसून येतो. अस्पृश्य, मागासलेल्या आणि बहुजन समाजावरील अन्याय दूर करण्यासाठी मानवतावादी दृष्टिकोनातून इटणारा राजा म्हणून शाहू महाराजांचे कार्य उल्लेखनिय आहे.

जनतेची उत्क्रांती, भरभराट आणि प्रगती यांच्या मार्गात तिच्या अनिष्ट सामाजिक चालीरिती व अंधश्रद्धा यांचा अडथळा होता. अनिष्ट रुढी व सामाजिक चालीरितीतील दोष दूर करून मानवाचा विकास साधण्यासाठी परिस्थिती निर्माण करणे हा त्यांचा उद्देश होता. त्यासाठी लोकांना वास्तवतेची जाणीव करून देवून त्यांची मने जिंकून घेण्याने विकासाची पावले त्यांना टाकावयाची

MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318

Vidyawarta[®]
Peer-Reviewed International Publication

February 2020
Special Issue-09

01

MAH/MUL/03051/2012

ISSN :2319 9318



शंकरराव पाटील महाविद्यालय, भूम
व

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद
यांच्या संयुक्त विद्यमाने

एक दिवसीय आंतरविद्याशाखीय राष्ट्रीय परिषद
२७/०२/२०२०

राजर्षी शाहू महाराज, महात्मा फुले, डॉ.
बाबासाहेब आंबेडकर यांचे योगदान

समन्वयक

प्रा. तानाजी वोरडे

डॉ. दयानंद शिंदे

डॉ. किशोरकुमार गव्हाणे

प्राचार्य

डॉ. श्रीकृष्ण चंदनशिव



Reg.No.U74120 MH2013 PTC 251205
Harshwardhan Publication Pvt.Ltd.

At.Post.Limbaganesh,Tq.Dist.Beed
Pin-431126 (Maharashtra) Cell:07588057695,09850203295
harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com

vidyawarta International Multilingual Research Journal

Date of Publication
27 Feb. 2020



Vidyawarta is peer reviewed research journal. The review committee & editorial board formed/appointed by Harshwardhan Publication scrutinizes the received research papers and articles. Then the recommended papers and articles are published. The editor or publisher doesn't claim that this is UGC CARE approved journal or recommended by any university. We publish this journal for creating awareness and aptitude regarding educational research and literary criticism.

The Views expressed in the published articles, Research Papers etc. are their writers own. This Journal dose not take any libility regarding appoval/disapproval by any university, institute, academic body and others. The agreement of the Editor, Editorial Board or Publicaton is not necessary.

If any judicial matter occurs, the jurisdiction is limited up to Beed (Maharashtra) court only.



Govt. of India,
Trade Marks Registry
Regd. No. 2611690

<http://www.printingarea.blogspot.com>

विद्यार्ता: Interdisciplinary Multilingual Refereed Journal | Impact Factor 7.041 (IJIF)

INDEX

01)	Rajarshi Shahu Maharaj Social Reformist and Visionary King Dr. Vaishali E. Aher, kaj	17
02)	ज्योतिबा फुले तथा शूद्र-अतिशूद्र एकता डॉ. सुब्राव नामदेव' जाधव, बाशी	19
03)	सामाजिक क्रांतीचे शिल्पकार : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर डॉ. शिवाजी हरी चौगुले, शिंदेवस्ती-बोंडले	22
04)	महात्मा ज्योतिराव फुले यांचे सामाजिक विचार प्रा.डॉ. चंद्रसेन सावळाराम आवारे, बीड	25
05)	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे जलविषयक धोरण प्रा.डॉ. देशमुख आर. के., बीड	28
06)	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे विचार डॉ. दास डी. के., बीड	30
07)	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे अर्थशास्त्रविषयक विचार डॉ. खरोसे भिमाशंकर, डॉ. सोलंकर आर. आर., उस्मानाबाद	34
08)	महात्मा जोतीराव फुले यांचे सामाजिक विचार डॉ. अशोक गौरीशंकर माळगे, अक्कलकोट	37
09)	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे धम्म कार्य डॉ. संजय तुकाराम वाघमारे, अकलूज	40
10)	राजर्षी शाहू महाराजांचे शैलीविषयक विचार व कार्य डॉ. अत्तार अमजद हारूण, उस्मानाबाद	43
11)	राजर्षी शाहू महाराज आणि महिला मुक्ती प्रा.डॉ. बी. एल. म्हस्के, प्रा. के. आर. गहिलोद, जालना	45

12) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे सामाजिक व आर्थिक विचार डॉ. गायकवाड आर. डी, डॉ. चारवकर पी. आर., मुस्म	47
13) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे आर्थिक विचार व सद्यस्थिती डॉ. जाधव जालु कन्हैयालाल, बीड	50
14) डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची प्रसंगिकता डॉ. एन. आर. लावंड, श्रीमती. सी. डी. वाघ, औरंगाबाद	52
15) जाणता राजा छत्रपती राजर्षी शाहू यांचे सामाजिक योगदान प्रा. गायकवाड डी. डी., उस्मानाबाद	54
16) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे राजकीय विचार प्रशांत मलकप्पा माठे, औरंगाबाद	56
17) मा. ज्योतिबा फुले यांचे शेतीविषयक विचार - काल, आज आणि उदया..... डॉ. देविदास नागरगोजे, डॉ. सावळे एकनाथ ग्यानोबा, बीड	58
18) राजर्षी शाहू महाराज आणि स्त्री मुक्ती विषयक कार्य प्रा. भागभिडे निल, उस्मानाबाद	62
19) कृषी अर्थशास्त्रज्ञ डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आश्रु पांडुरंग मोरे, निलेश शशिकांत खिल्लारे, औरंगाबाद	64
20) डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे सामाजिक योगदान प्रा. रसाळ मंजुषा मुरलिधर, चौसाळा	66
21) आंबेडकरी स्त्रीवाद डॉ. सारिका अशोकराव दुरगे, बीड	69
22) छत्रपती राजर्षी शाहू महाराजांचे आरक्षण विषयक विचार प्रा. राठोड बी. जे., बीड	71
23) राजर्षी शाहू महाराज : सामाजिक लोकशाहीचा पुरस्कर्ता डॉ. मुंडे सविता गंगाधरराव, जालना	74



डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची प्रासंगिकता

डॉ. एन. आर. लावंड

संशोधक विद्यार्थी, डॉ. बा.आं.म.विद्यापीठ, औरंगाबाद

श्रीमती. सी. डी. वाघ

संशोधक विद्यार्थीनी, डॉ. बा.आं.म.विद्यापीठ, औरंगाबाद

गोपवारा :

प्रस्तुत शोधपत्रिका ही डॉ. बी.आर.आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांशी संबंधित असून ते भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात कसे उपयुक्त आहेत यावर प्रकाश टाकण्यात आला आहे. यामध्ये रुपयाचा प्रश्न, राजस्वासंबंधीचे विचार, शेती, उद्योग, पाणी व विज इत्यादी आर्थिक विचारांचा उहापोह केला आहे.

बीजशब्द : स्वर्ण परिमाण, राजस्व, कृषी, उद्योग, पाणी व विज.

प्रस्तावना :

डॉ. बी.आर. आंबेडकर हे भारतीय इतिहासातील गतिशील व्यक्तीमत्व होते. ते अर्थशास्त्राचे प्राध्यापक होते. ते केवळ अर्थतज्ञच नव्हे तर समाजशास्त्रज्ञ, शिक्षणतज्ञ, वृत्तपत्रकार, संसदपटू, संपादक असे विविधांगी अष्टपैलू व्यक्तीमत्व होते. त्यांनी केवळ सामाजिक समतेसाठीच नव्हे तर आर्थिक समतेसाठी संघर्ष केला. म्हणून त्यांचे अर्थशास्त्रातील योगदान अतुलनीय वाटते.

आंबेडकरांचा जन्म ब्रिटीशांनी निर्माण केलेल्या सैनिकी छावणीमध्ये १४ एप्रिल १८९१ मध्ये झाला. ते गरीब कुटुंबातील होते. त्यांनी त्यांचे पदव्युत्तर पदवी अर्थशास्त्राचे शिक्षण १९१३ साली कोलंबीया विद्यापीठातून पूर्ण केले तर पीएच.डी. चे शिक्षण १९२२ मध्ये लंडन स्कुल ऑफ इकॉनॉमिक्स अँड पॉलिटीकल सायन्समधून केले. आंबेडकरांनी अर्थशास्त्रावर अनेक ग्रंथांच्या माध्यमातून लिखान केले. त्यातूनच त्यांचा आर्थिक दृष्टिकोण स्पष्ट होतो. त्यांनी त्यांच्या आर्थिक विचारांमध्ये रुपयाची समस्या, वित्तासंबंधीचे, कृषी, उद्योग, सार्वजनिक खर्च, नविन पाणी आणि उर्जा धोरण, कामगार

कायद्याबाबतचे विचार या नी इत्यादी विचारांचा समावेश होतो. या सर्व आर्थिक विचारांची भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात काय उपयुक्तता आहे त्यांचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न यातून केला आहे.

विषय निवडीचे महत्व :

डॉ. बी. आर. आंबेडकर हे बहुआयामी व्यक्तीमत्व होते. जात, अस्पृश्यता निर्मूलन कार्याबरोबरच त्यांचे अर्थशास्त्रातील योगदान देखील मोलाचे वाटते. त्यांनी रुपयांची समस्या सार्वजनिक वित्त व खर्च, भारतीय शेती, उद्योग, विज, पाणी, कामगार कायदे या विषयावर आपले विचार निसंकोचपणे मांडले. आज त्यांच्या या आर्थिक विचाराला शंभरहून अधिक वर्षे झाले तरी ते आजच्या भारतीय अर्थव्यवस्थेला तंतोतंत प्रासंगिक ठरतात. म्हणून "डॉ. बी.आर.आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची प्रासंगिकता" हा विषय अभ्यासासाठी निवडण्यात आला.

अभ्यासाची उद्दिष्टे :

१. डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या विविध आर्थिक विचारांचा अभ्यास करणे.
२. डॉ. बी. आर. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांची सद्यःस्थितीतील भारतीय अर्थव्यवस्थेसंदर्भात प्रासंगिकता (उपयुक्तता) अभ्यासणे.

संशोधन पद्धती :

संशोधकाने प्रस्तुत शोधपत्रिका किंवा लेख लिहित असतांना दुय्यम साधन सामुग्रीचा आधार घेतला आहे. हे एक विश्लेषणात्मक संशोधन असून तथ्य संकलनासाठी संबंधीत संदर्भग्रंथ, शोधपत्रिका इ.पी.डब्ल्यू. इत्यादी दुय्यम स्त्रोतांचा वापर करण्यात आला आहे. यासाठी निरीक्षण पद्धतीचा देखील वापर करण्यात आला आहे. आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांचे विश्लेषण आणि त्याची प्रासंगिकता :

१. भारतीय रुपयांचा प्रश्न :

आंबेडकरांनी आपले आर्थिक विचार मांडत असतांना भारताचा रुपया आणि इंग्लंडचा पौंड यातील संबंधाचा अभ्यास केला आणि सांगितले रुपयाची जडणघडण स्वर्ण विनिमयाऐवजी स्वर्ण परिमाणात (Gold Standard) असावी अशी भूमिका मांडली. कारण स्वर्ण विनिमयामुळे भाववाढीला चालना मिळते. परिणामी रुपयाची किंमत कमी होवून रुपया अस्थिर होईल असे सांगितले. सद्यःस्थितीत चलन निर्मिती मोठ्या प्रमाणात होते. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात भाववाढ (७.८%) होते. म्हणून १९२५ ला चलननिर्मितीबाबत जी भूमिका आंबेडकरांनी मांडली ती भूमिका आज खरी ठरते.



२. राजस्वासंबंधीचे विचार :

आंबेडकरांनी १८३३-१९२१ या काळातील इंग्रज सरकार आणि घटकराज्यातील संबंध यावर प्रकाश टाकला. त्यातून त्यांना या काळात राजस्वाचे संपुर्ण केंद्रीकरण झाल्याचे दिसून आले. तेंव्हा बदलत्या परिस्थितीत केंद्र- राज्य संबंध सुधारण्यासंदर्भात वित्त आयोग स्थापन्याचा विचार हा आंबेडकरांच्या संशोधनातून पुढे आल्याचे दिसते. तसेच केंद्राकडून राज्याला दिला जाणारा १५ व्व वित्त आयोगाचा हिस्सा ३४ टक्क्यावरून ३२ टक्के करण्यात आला आहे. तेंव्हा येथे आंबेडकरांचा मुलगामी विकेंद्रीकरणाचा विचार उपयुक्त ठरतो.

३. भारतीय शेतीसंबंधी विचार :

आंबेडकरांनी भारतीय शेती व्यवस्था व तिची अवस्था यासंबंधी विचार मांडले. आंबेडकरांच्या मते भारतातील ५८ टक्के लोक शेतीवर अवलंबून असल्याने शेती हा महान राष्ट्रीय उद्योग आहे. म्हणून शेतीला अनन्यसाधारण महत्त्व आहे. आंबेडकरांच्या मते भारतातील शेतजमिनीचा आकार लहान असल्याने व ती विखुरलेली असल्याने त्याचा उत्पादकतेवर परिणाम होतो. या समस्येवर उपाय म्हणून रशियाच्या धर्तीवर सामुहिक एकत्रित शेती करणे तसेच कृषी क्षेत्रातील खाजगी गुंतवणूक वाढीवर भर देणे हे त्यांचे विचार सद्यस्थितीत प्रासंगिक वाटतात.

४. उद्योगासंबंधी विचार :

आंबेडकरांनी आधुनिक औद्योगिककरणाचा पुरस्कार केला, परंतु यातून आर्थिक विषमता, संपत्तीचे केंद्रीकरण व मक्तेदारीत वाढ होईल असे सांगितले. सद्यस्थितीत Oxfom चा अहवाल पाहिल्यास असे दिसून येते कि, भारतातील ३ टक्के लोकांकडे ९७ % संपत्ती तर ९७ टक्के लोकांकडे ३% संपत्ती असल्याचे दिसून येते. तेंव्हा आंबेडकरांचे विचार आज प्रासंगिक वाटतात.

५. पाणी व विजेसंदर्भात विचार :

आंबेडकरांनी या दोन महत्त्वाच्या मुलभूत गरजा ओळखून नवीन पाणी धोरण योजना १९४२-४६ साठी लागू केली. आणि त्यातून USA च्या धर्तीवर पुरनियंत्रण, दुष्काळ, सिंचन व विजनिर्मितीसाठी बहुउद्देशिय प्रकल्प उभारणीचा संदेश दिला तो सद्यस्थितीत प्रासंगिक ठरतो.

निष्कर्ष :

१. आंबेडकरांच्या रुपयाचा प्रश्नासंदर्भात अभ्यास केला असता सद्यस्थितीत भारतीय अर्थव्यवस्थेत रुपयाचे मुल्य दिवसेंदिवस कमी होताना दिसते.

२. राजस्वासंबंधी विचारावरून भारतीय अर्थव्यवस्थेतील केंद्र- राज्य संबंध हे तानल्याचे दिसते. उदा. G.S.T. हस्तांतरण.

३. शेतीसंबंधी विचारावरून सामुहिक शेतीची

असल्याचे दिसते.

४. औद्योगिकरणामुळे उत्पन्न व संपत्ती विषमतेत प्रचंड वाढ झाल्याचे दिसते.

५. पाणी व विजेसंदर्भातील भारतीय अर्थव्यवस्थेतील धोरण नियोजनशून्य असल्याचे दिसते.

उपाय :

१. रुपयाचे मुल्य बळकट करण्यासाठी निर्यात वाढीला प्रोत्साहन देण्यात यावे.

२. वित्तआयोगाच्या माध्यमातून केंद्राकडून राज्याला दिला जाणारा हिस्सा वाढविण्यात यावा. जेणेकरून दोघातील संबंध सुदृढ होतील.

३. रशियाच्या धर्तीवर सामुहिक शेती करण्याला प्राधान्य द्यावे तसेच शेतीमध्ये खाजगी गुंतवणूक वाढीसाठी सरकारने प्रयत्न करावेत.

४. संपत्ती आणि उत्पन्नातील विषमता दूर करण्यासाठी प्रगतीशील करावरोबरच खर्च कर धोरण अवलंबण्यात यावे.

५. पाणी आणि विजेसंदर्भात नदीजोड प्रकल्प व इजरायलच्या धर्तीवर पाण्याचे व्यवस्थापन करण्यात यावे.

समारोप:

थोडक्यात आंबेडकरांच्या आर्थिक विचारांच्या विश्लेषणावरून असे दिसून येते की, त्यांचे विचार शंभर वर्षांनंतर ही भारतीय अर्थव्यवस्थेला तारक ठरतात.

संदर्भग्रंथ :

१. Sonone Omprakash (२०१६), "Economic thought of Dr. B.R.Ambedkar for Indian economy", Gurukul International Multidisciplinary research Journal, Allapalli.

२. Jadhav N, Neglected Economic thought of Babasaheb Ambedkar, Economical and Political weekly, dated. १३th Apr.१९९९

३. Kumar Sunil (२०१९), " Ambedkar's Economic Idead & Contributions," IOSR Journal of Humanities and Social Science.

४. रावखेलकर व दामजी (२०११), 'आर्थिक विचारांचा इतिहास' विद्या बुक्स पब्लिशर्स, औरंगाबाद.



PRINCIPAL

RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE, KARMAD, AURANGABAD.



58

Volume 15, Special Issue 1, October 2019, Impact Factor 4.13, ISSN 2454-6503



CHRONICLE OF HUMANITIES AND CULTURAL STUDIES

A Peer Reviewed Bimonthly International Journal

Special Issue on the Occasion of
UGC Sponsored Interdisciplinary National Conference on

Gandhian Thought: Past, Present and Future

1 October, 2019

Organized by
Shri. Yogeshwar Education Society's

Swami Ramanand Teerth Mahavidyalaya

Ambajogal, Dist. Beed - 431517



Chief Organizer

Mr. Ramesh Sonwalkar

UGC Principal, S.R.T.M. Ambajogal

Chief Editor

Dr. Shailaja Barure

Director, Gandhian Studies Center

Associate Editor

Mr. Dhanaji Arya

Director, IQAC

अनुक्रमणिका

१. महात्मा गांधी आणि ग्रामीण विकास | डॉ. सुनिल शिंदे | १२
२. सर्वोदय हेच महात्मा गांधीजींचे अंतीम ध्येय | प्राचार्य डॉ. शरद कुलकर्णी / सुरेश दिवाळे | १८
३. सत्याग्रही कस्तुरबा गांधी | डॉ. शैलजा भा. बरुरे | २१
४. महात्मा गांधी आणि शाश्वत विकास | डॉ. आरडले.एस.डी. | २७
५. महात्मा गांधीचे ऐच्छिक साधेपणा याविषयीचे विचार | डॉ. सुधीर आ. येवले | ३१
६. महात्मा गांधी यांचे शैक्षणिक विचार | प्रा. गडदे भारती बा. | ३३
७. महात्मा गांधीजींचे स्वदेशी विषयक विचार | डॉ. सुरेश टी. सामले | ३९
८. आधुनिक जगात महात्मा गांधीजींचे स्थान | डॉ. ज्ञानेश्वर सोनवणे | ४२
९. आजच्या जगात गांधी विचारांची आवश्यकता | माने रागिणी सु. | ४६
१०. महात्मा गांधीजींचा चंपारण्य सत्याग्रह व ... | रामेश्वर सि. झोडगे | ५०
११. महात्मा गांधी एक समाज सुधारक | बसन्दास हि. नोळे | ५३
१२. गांधीजींच्या विचारांची आजच्या स्थितीत उपयुक्तता | डॉ. विठ्ठल शं. देशमुख | ६०
१३. गांधीजी, चळवळ आणि स्त्रीसक्षमकरण | डॉ. गायत्री गाडेकर | ६४
१४. महात्मा गांधीजींचे समतेसंबंधी विचार | डॉ. सौ. मनिषा देशमुख | ७३
१५. महात्मा गांधीजींचे समतेचे तत्त्व : एक अभ्यास | डॉ. भाऊराव धोंडिबा मुंडे | ७६
१६. महात्मा गांधीजींचा ग्रामस्वराज्याची संकल्पना | डॉ. अरुण दळवे | ८१
१७. महात्मा गांधीजींचे आर्थिक विकासा बाबतचे विचार | गादेकर पी. सी. | ८५
१८. महात्मा गांधी एक महान संत | डॉ. संपदा कुलकर्णी-गिरगावकर | ८८
१९. गांधीजींचे शिक्षण विषयक विचार | गिरिश अ. पुजारी | ९१
२०. महात्मा गांधीजींचा साहित्य विषयक दृष्टीकोण | डॉ. संजय खाडप | ९६
२१. महात्मा गांधीजींच्या सत्य व अहिंसेसंबंधी विचारांचे चिंतन | विलास किर्दत | १८
२२. व्यसनमुक्त समाजासाठी म. गांधीजींचे मार्मिक विचार ... | किसन शिन्गारे | १०२
२३. महात्मा गांधीजींचे शैक्षणिक विचार | कातळे संगिता गुलाबराव | १०७
२४. महात्मा गांधी व सत्याग्रह : एक अभ्यास | डॉ. शिबे अनंत ना. | १११
२५. महात्मा गांधी आणि मराठी साहित्य | डॉ. डिगोळे बालाजी वि. | ११७
२६. गांधीजींना अपिप्रेत असणारी जीवनमूल्ये | मकरंद जोगदंड / डॉ. अर्जुन मोरे | १२५
२७. म. गांधी यांच्या सविनय कायदेभंग चळवळीतोल... | राजकुमार शा. चाटे | १२९
२८. मा. गांधीजींचे सामाजिक विचार वास्तवता | डॉ. प्रमोद चव्हाण | १३४
२९. खादी - आर्थिक स्वावलंबनाचे साधन | डॉ. अनंत नरवडे | १३८
३०. आर्यसमाजी चळवळीत महात्मा गांधीजींच्या ... | डॉ. रामभाऊ काशीद | १४३
३१. बदलत्या परिवेशात महात्मा गांधींच्या आर्थिक... | सागर कुलकर्णी | १४९



३२. भारतीय लोकशाहीला प्रबळ करणारा-गांधी विचार | डॉ. भास्कर गायकवाड | १५५
३३. रामोद्योग - काल, आज, उद्या | प्रा. पाटील अनुराधा ल. | १५९
३४. महात्मा गांधी : एक सत्याची प्रयोगशाळा | डॉ. रुद्रवाड जी. पी. | १६३
३५. महात्मा गांधींचे सर्वोदय तत्त्वज्ञान एक दृष्टिक्षेप | गौतम गायकवाड | १६५
३६. महात्मा गांधीजींचा शैक्षणिक ध्येय एक अवलोकन | डॉ. कालिदास दि. फड | १६८
३७. गांधीवादी विचारांची प्रासंगिकता | डॉ. संतोष कोल्हे | १७१
३८. महात्मा गांधीजींचे भारतीय राष्ट्रीय ... | जयश्री पं. पोटेपल्लेवार | १७९
३९. सत्य आणि अहिंसेचा वर्तमान काळात ही उपयोगिता ... | पवार बी. टी. | १८३
४०. म. गांधीजींची ग्रामस्वराज्याची कल्पना आणि ... | डॉ. कुंभारकर के. जी. | १८८
४१. मराठी साहित्याची प्रेरणा : महात्मा गांधी | डॉ. लहू दि. वाघमारे | १९१
४२. गांधीजींचे अहिंसावादी विचार | संजय मोहाडे | १९७
४३. महात्मा गांधीजींचे सत्य आणि अहिंसे संबंधी विचार | नवनाथ झा. पवळे | २०३
४४. महात्मा गांधी यांचे राष्ट्रीय एकात्मताविषयक विचार .. | सोनवणे जी. एन. | २०५
४५. गांधीजींचे विचार - स्त्रियांसाठी वर्तमान... | सय्यद अफरोज अहमद | २०९
४६. म. गांधींचे राजकीय विचार | नितीन शिंदे | २१२
४७. महात्मा गांधी व अस्पृश्यता निर्मूलन | श्रीमती. धुमळ सीमा का. | २१५
४८. महात्मा गांधीजींचे पंचावर्ण विषयक विचार : ... | डॉ. पिसाळ हरिदास जी. | २१८
४९. राष्ट्रपिता म. गांधीचे भारतीय स्वातंत्र्य चळवळीत ... | डॉ. आचार्य आर. डी. | २२०
५०. महात्मा गांधींचे आर्थिक विचार :- एक दृष्टिक्षेप | मनिषा धनराज केंद्रे | २२३
५१. महात्मा गांधीजींचे समाजसुधारणा विषयक विचार | अंबुरे ऋषिकेश स. | २२७
५२. परकीयांच्या नरजेतून गांधी मिमासा | डॉ. सदाशिव बा. दंडे | २३२
५३. म. गांधी आणि सत्याग्रह | डॉ. जगदिश देशमुख | २३५
५४. महात्मा गांधी ग्रामस्वराज्य | डॉ. सो. ममता म. देशमुख | २४२
५५. महात्मा गांधीजींचे आरोग्य व आहार विषयक विचार | डॉ. अरविंद व. कर्तस | २४५
५६. गांधी विचार हि काळाची गरज | डॉ. गंगणे आर. व्ही. | २४९
५७. महात्मा गांधीजींच्या 'ग्रामस्वराज्य' संकल्पनेची ... | डॉ. जे. के. भालेराव | २५३
५८. गांधी : काल, आज आणि उद्या | डॉ. शामराव म. लेंडवे | २५७
५९. महात्मा गांधी यांच्या आर्थिक विचारांची... | डॉ. निलेश व्ही. होदलुकर | २६०
६०. महात्मा गांधींचे शैक्षणिक विचार | डॉ. एस. एम. कोनाळे | २६६
६१. महात्मा गांधी यांच्या विचारांची ... | चिकटे जं. राहु / डॉ. विगाडे ओ. व्ही. | २६९

महात्मा गांधीजींची शैक्षणिक ध्येय एक अवलोकन

प्रा. डॉ. कालिदास दिनकर फड

लोकप्रशासन विभाग, राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड, ता.जि.औरंगाबाद

प्रस्तावना : महात्मा गांधीजींनी आपल्या आत्मसाक्षात्कारातून, आत्मसाक्षात्काराच्या प्रेरणेतून शैक्षणिक विचार मांडलेले आहेत. आदर्शवाद, स्वभाववाद व कार्यवादाचा उत्कृष्ट समन्वय गांधीजींच्या शैक्षणिक विचारात आहे.

गांधीजींनी औपचारिक शिक्षणापेक्षा अनौपचारिक, अनुभवाधिष्ठित शिक्षणावर भर दिला. तोंडी काम, संवाद, संभाषण, चर्चा, शंका समाधान यांना लेखन वाचनापेक्षा अधिक प्राधान्य दिले. जीवनमूल्यांचा संस्कार हा गांधीजींनी शिक्षणाचा गाभा मानला. आत्मसन्मान, स्वातंत्र्य, सेवाभाव, साधेपणा, स्वावलंबन, स्वयंशुद्धी, संयम, सहकार्य यासारखी शैक्षणिक मूल्ये विद्यार्थ्यांच्या मनावर विंबवली पाहिजेत. हे विंबवण्याचे कार्य आदर्श चारित्र्यशील शिक्षक आपल्या उक्तीतून कृतीतून करेल. गांधीजींनी चारित्र्य शिक्षणाला सामान्य शिक्षणाचे अविभाज्य अंग मानलेले होते. गांधीजींनी जीवनासाठी, जीवनाद्वारा, जीवनभर अशी 'जीवन शिक्षण' संकल्पना आपल्या विचार आचरणातून आणलेली होती. जीवन हाच खरा अभ्यासक्रम असून त्याच्या प्रत्येक कसोटीवर आपण कसे उतरतो यावर त्याचे महत्त्व अवलंबून आहे. हीच खरी आपल्या शैक्षणिक ध्येयाची कसोटी आहे.

आपण शिक्षण हे स्वावलंबी केले पाहिजे. प्राथमिक शिक्षण म्हणजे स्वावलंबनासाठी शिक्षण व पुढील शिक्षण म्हणजे स्वावलंबनाद्वारा शिक्षण, शिक्षणाचा आरंभ कुठल्यातरी हस्तव्यवसायाने करावा. त्यामुळे प्रत्येक शाळा स्वावलंबी बनू शकेल. एकंदरीत शिक्षण हे स्वाश्रयी झाले पाहिजे. स्वाश्रयिता हीच खऱ्या शिक्षणाची कसोटी आहे. व्यक्तिमत्त्वाच्या विकासासाठी प्रत्येक विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक दृष्ट्या स्वावलंबी झाला पाहिजे. त्याचे स्वातंत्र्य व्यक्तिमत्त्व विकसित होऊन तो आत्मनिर्भर झाला पाहिजे.

शिक्षण म्हणजे उत्कृष्टाकडे वाटचाल. मनूच्या आणि बालक यांचे शारी, मन व आत्मा यांच्यामध्ये सुप्त असलेल्या उत्तमत्वाचे प्रकटीकरण स्वातंत्र्य रीतीने होणे म्हणजे शिक्षण. गांधीजींनी सुप्त असलेल्या उत्कृष्ट गुणांचा अविष्कार व्हावा यावर भर दिला. शिक्षण हे एकांगी असू नये असे त्यांचे स्पष्ट मत होते. शारीरिक, मानसिक व आत्मिक अशा तिन्ही अंगांनी उत्तमोत्तम गुणांचा अविष्कार घडविण्यास शिक्षणाने सहाय्य करावे. हेच शिक्षणाचे खरे कार्य आहे. एका अंगाची उपेक्षा करून, अधिकची किंमत देऊन, दुसऱ्या अंगाचा विकास गांधीजींनी अभिप्रेत

नकता ही दृष्टी स्वभाववादी आहे. कोणत्या गुणास उत्तम गुण म्हणायचे असे उत्तमत्व व उत्कृष्टत्व यांचा निकष काय या दृष्टीने विचार केला तर उत्कृष्टत्व पुरस्कार करणारे आदर्शवादी ठरतात. म्हणजे या ध्येयाद्वारे आदर्श व स्वाभाववाद यांचा समन्वय होतो. गांधीजी आपल्या शिक्षण प्रणालीस व्यवसाय केंद्रित न म्हणता जीवन केंद्रित म्हणत.

आपले हित हे सर्वांच्या हितात सामावलेले आहे असे वर्तन प्रत्येकाने करावे. चरितार्थाचे साधन म्हणून शारीरिक अथवा बौद्धिक व्यवसायांना किंमत देणे व शारीश्रमाच्या, अंगमेहनतीच्या कामाद्वारेच निर्वाह चालविणे ह्या तीन चारित्र्य कसोट्या आहेत. सर्वोदायाचे हे तीन मूलभूत सद्गुण आहेत. आचरणाद्वारे चारित्र्य सिद्ध होते. या तीन सद्गुणांचे आचरण म्हणजे चारित्र्य संपादन. न्हदयाचे शिक्षण हेच खरे शिक्षण आहे. विद्यार्थ्यांची नैतिक बुद्धि दृढ करणे, चारित्र्य संवर्धन करणे हे शिक्षणाचे मुख्य ध्येय आहे. न्हदयवृत्तीचे शिक्षण म्हणजेच आध्यत्मिक शिक्षण. हे शिक्षण पाठ्यपुस्तकांच्या बरोबरच शिक्षकांच्या जिवंत संपर्कातून, गुरुनांच्या प्रेरक सहवासातूनच देता येईल. नीतिमान शिक्षक हाच चारित्र्याच्या घडणीचा खरा आधार आहे.

गांधीजींना समाजात राहून व सामाजिक जीवनाद्वारे आत्मसाक्षात्कार अपेक्षित होता. त्यामुळे त्यांच्या ध्येय मांडणीत व्यक्तिनिष्ठा व समाजनिष्ठा यांचा समन्वय झालेला दिसतो. या दोन निष्ठा त्यांच्या दृष्टिने अविराभी आहेत. शिक्षण हे व्यक्तिजीवनाच्या सार्थकतेचे साधन बनले पाहिजे, तसे ते समष्टीजीवनाच्या नवनिर्मितीची वाहन बनले पाहिजे. सामाजिक परिवर्तनासाठी शिक्षण, न्याय समाजव्यवस्था निर्माण करण्यासाठी शिक्षण, सत्याग्रही समाज किंवा सर्वोदयी समाज यासारखा आदर्श समाज निर्माण करण्यास शिक्षणाने हातभार लावला पाहिजे. गांधीजींना अभिप्रेत असलेला नवा समाज न्याय असेल, शासनमुक्त व शोषणमुक्त असेल. श्रीमंत व गरीब असा या समाजात भेदभाव नसेल. सत्याने व अहिंसेने वागणारा असा तो समाज असेल. विषमता नसलेली नवी समाजव्यवस्था निर्माण करण्याचे, त्यासाठी अहिंसक सामाजिक क्रांती करण्याचे एक हत्यार म्हणजे शिक्षण होय. बळाचा वापर न करता अहिंसक मार्गाने समाजरचना करण्याचा मार्ग म्हणजे शिक्षणाचा मार्ग होय. न्हदय परिवर्तनाची प्रक्रिया एक प्रकारची शिक्षणाची प्रक्रिया आहे. पाठपुरावा करणे, पटविणे, मतपरिवर्तन करणे या साऱ्या प्रक्रिया शिक्षणाच्या अनौपचारिक प्रक्रिया आहेत. समाजाच्या चाकोरीबाह्य शांलाबाह्य शिक्षणाचा तो भाग आहे.

'सा विद्या सा विमुक्तये' या वचनानुसार गांधीजींनी मुक्ती हे शिक्षणाचे ध्येय मानलेले आहे. विद्येचा अर्थ लोकोपयोगी पडणारे सर्व प्रकारचे ज्ञान व मुक्तीचा अर्थ या जीवनातील सर्व प्रकारच्या गुलामगिरीतून सुटका करून घेणे,



गुलामगिरी म्हणजे दुसऱ्याच्या स्वाधीन असणे किंवा आपणच-निर्माण केलेल्या कृत्रिम गरजांचे गुलाम बनणे. या दोन्ही प्रकारची मुक्ती ज्यायोगे मिळेल तेच खरे शिक्षण.

आत्मसाक्षात्कार या सर्वसमावेशक व व्यापक शैक्षणिक ध्येयावर गांधीजींनी अधिक भर दिलेला आहे. आत्मसाक्षात्कारामध्येच आत्मत्याग होतो व आत्मत्यागानेच आत्मसाक्षात्कार घडतो. म्हणून आत्मसाक्षात्कार हे ध्येयअतिशय व्यापक आहे. आत्मसाक्षात्कार, मोक्ष, इश्वरदर्शन, हे गांधीजींना समानार्थी शब्द वाटतात. म्हणूनच व्यक्तीचा आत्मसाक्षात्कार हा सर्वांच्या अधिकतम कल्याणातून होतो. ही त्यांची अद्वैती भूमिका आहे. उत्तमत्वाचा अविष्कार म्हणजे स्वतःतील दैवी गुणांचे प्रकटीकरण. याच प्रगटीकरणातून देवत्वाची अनुभूती येते, हेच आत्मदर्शन होय. उत्तमत्वाच्या प्रगटीकरणाने माणूस हळूहळू दिव्यत्व अनुभवतो व दिव्यत्वाची अशी प्रचिती जेथे येईल तेथेच त्याच माध्यमातून आत्मसाक्षात्कार घडेल. म्हणून दोन्ही ध्येयामध्ये सुसंवाद दिसतो. आत्मसाक्षात्कार या सर्वोच्च ध्येयामध्ये इतर सर्व उपरनिर्दिष्ट ध्येयांचा समावेश होतो. म्हणूनच गांधीजींनी आत्मसाक्षात्कार हेच शिक्षणाचे सर्वोत्तम ध्येय मानले.

सारांश :

महात्मा गांधीजींची शैक्षणिक ध्येय उदात्त आहेत. सद्यस्थितीतही ती अतिशय उपयुक्त आहेत. स्वावलंबन सर्वोत्तमतेचा, उत्कृष्टतेचा अविष्कार, व्यक्तीगत हितापेक्षा सार्वजनिक हिताला प्राधान्य, चारित्र्य संवर्धन, सामाजिक परिवर्तन सर्व प्रकारच्या बंधनातून गुलामगिरीतून मुक्ती आणि स्वयंशुद्धी, आत्मसाक्षात्कार ही उदात्त ध्येय साध्य करण्याची जबाबदारी शिक्षकावर अवलंबून आहे. आदर्श चारित्र्यसंपन्न, नीतिनाम शिक्षकाशिवाय हे ध्येय साध्य होणे दुरापास्त आहे. ही शैक्षणिक ध्येय साध्य होऊ शकली तरच खऱ्या अर्थाने भारत विकसीत राष्ट्र होऊ शकेल. त्याशिवाय विकास म्हणजे आत्म्याशिवाय शरीर होय.

संदर्भसूची :

- १) Gandhi M.K., My Experiement with Truth, 1958
- २) Prabhu R.K. & Rao W.R., The mind of Mahatma Gandhi, Oxford University, Press, 1945
- ३) भारदे बाळासाहेब, गांधी विचार दर्शन, जीवनसाधना, महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधी प्रकाशन, पुणे, १९९४
- ४) पटेल रावजीभाई, गांधीजींची साधना
- ५) वाशीकर शं. श्री., चार शिक्षणतज्ञ, नूतन प्रकाशन, पुणे, १९९१

□□□


PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.



ISSN 2349-638x
Impact Factor 5.707



ICSSR, New Delhi Sponsored

National Level Seminar in Interdisciplinary subject

FINANCIAL LITERACY AND DIGITAL PAYMENT SYSTEM IN INDIA

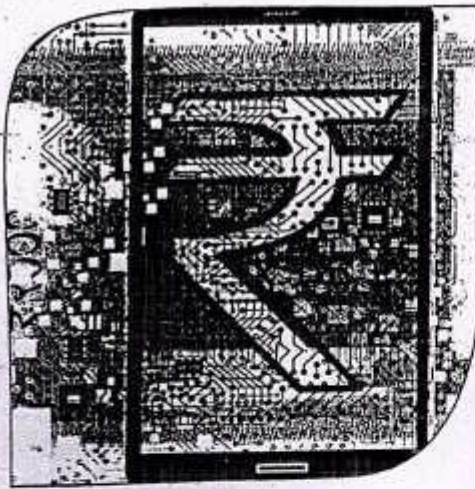
Kisan Shikshan Prasarak Mandal, Borgaon (Kale), Tq. & Dist. Latur

Affiliated to Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad

VASANTRAO KALE MAHAVIDYALAYA,

DHOKI, TQ. & DIST. OSMANABAD. (MS)

Saturday, 28th December 2019



Pri. Dr. Haridas Fere
Chief Editor

Dr. Balasaheb Maind
Editor

Organized By

Department of Economics

Vasant Rao Kale Mahavidyalaya, Dhoki

Tq. & Dist. Osmanabad (MS).

Vol.
II



Sr. No.	Name of Author	Title Of Paper	
76.	आर. डी. गणापुरे डी. पी. बिराजदार	आर्थिक साक्षरता आणि भारतीयांची गुंतवणूक प्रवृत्ती	232
77.	ज्योती ललित अधाने	डिजिटल इंडिया व वित्तीय समावेशन	236
78.	डॉ. ज्ञानेश्वर जिगे	रोकड विरहित अर्थव्यवस्था : भारताच्या संदर्भात संधी आणि आव्हाने	240
79.	डॉ. सुनिल अण्णा गोरडे	राष्ट्रीय कृषी बाजार (ई-नाम) प्रणालीचे एक अर्थशास्त्रीय विश्लेषण	242
80.	डॉ. प्रमोद बालाजीराव वेरळीकर	कॅशलेस व्यवहार व ग्रामीण अर्थव्यवस्था	244
81.	प्रा. डॉ. अनंत नरवडे	रोकडविरहित अर्थव्यवस्था- समस्या आणि उपाय	246
82.	गोविंद रामराव काळे डॉ. दीपक एम. भारती	भारतातील रोकडविरहीत व्यवहार : एक आव्हान	249
83.	प्रा. डॉ. ए. टी. शेवाळे	भारतातील ई-कॉमर्स - आर्थिक व्यवहार व विनिमय	251
84.	प्राचार्य डॉ. हरिदास फेरे डॉ. वी.व्ही. मैद	भारतातील डिजिटलायझेशन आणि डिजिटल पेमेंट सिस्टिम एक अभ्यास	254
85.	डॉ. माधवराव नरसिंगराव बिरादार	रोकडरहित अर्थव्यवस्था व रोकडरहित व्यवहाराचे विविध पर्याय	256
86.	श्यामराव लक्ष्मण वासनीकर प्रा डॉ. विजय भोपाळे	कॅशलेस अर्थव्यवस्था आव्हाने आणि उपाय	259
87.	डॉ. एस.एस. देवनाळकर	डिजिटल पेमेंट सिस्टिमचा भारतीय अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम	261
88.	एम. एस. बिडवे	डिजिटल प्रथालय साहित्य सादरकरण व शोधप्रक्रिया : एक अभ्यास	263
89.	डॉ. मिनाश्री भास्कर जाधव	डिजिटल साक्षरता आणि भारतीय अर्थव्यवस्था	266
90.	राहुल शिवाजी तिगोटे डॉ. दीपक भुसारे	काळ्या पैशाला लगाम : रोखरहित अर्थव्यवस्था	269
91.	आकाशनाथ दत्तात्रय बोरकर, डॉ. एन.के.मुळे	निश्चलनीकरण आणि रोकडविरहित अर्थव्यवस्था	271
92.	डॉ. कार्तिक पोळ प्रा. प्रमोद मुळे	रोकड विरहित व्यवहारात सरकारने केलेले प्रयत्न	276
93.	प्रा. आचार्य बालाजी वैजनाथराव	रोख विरहीत व्यवहार : आव्हाने व उपाय	278
94.	डॉ. ए. एच. अत्तार	डिजिटल इंडिया मोहीम : एक आर्थिक क्रांती	281



116.	प्रा.डॉ.नानासाहेब पंडितराव मनाळे	डिजिटल तंत्रज्ञान : काळाची गरज — एक अभ्यास	
117.	डॉ. अर्जून मोहनराव मोरे	शेती उद्योग आणि सेवा क्षेत्रातील डिजिटल पध्दती	339
118.	डॉ. महेशकुमार मोटे	कॅशलेस प्रणाली आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था	342
119.	अनुराधा रामभाऊ पाऊलबुध्दे प्रा. डॉ. अशोक कोरडे	भारतातील वित्तीय व्यवहारांच्या संदर्भात डिजिटल पेमेंट सिस्टम - एक दृष्टिक्षेप	344
120.	प्रा.डॉ.एल.एच.पाटील महेश शिवाजीराव नेलवाडे	कॅशलेस अर्थव्यवस्था आणि नवे पर्याय	346
121.	प्रा. नानासाहेब श्रीरंग पटनुरे प्रा. डॉ.मनोजकुमार यादवराव सोमवंशी	रोकडविरहित व्यवहारासाठी सरकारी उपाय-योजना	350
122.	प्रा.डॉ.कालिदास दिनकर फड	कॅशलेस व्यवहार आणि बदलती माध्यमे	353
123.	प्रा.डॉ. दैवशाला चैत्रभुज रसाळ	रोकडविरहित व्यवहाराचे फायदे — तोटे	355
124.	प्रा.डॉ. एस.ए. सुगळे	पेसा मुक्त बाजार व्यवहारासमोरील आव्हाने व संधी	358
125.	प्रा. डी. एन. सरडे	पारंपारिक ग्रंथालयाचा डिजिटल प्रवास : एक अभ्यास	362
126.	डॉ.नामानंद गीतम साठे	कॅशलेस व्यवहार आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्था	364
127.	डॉ. एम.एल. शेळके	कॅशलेस व्यवहार : लाभ आणि आव्हाने	366
128.	प्रा. अलका विठ्ठल शिंदे	डिजिटल प्रशासन पारदर्शकता आणि जनसहभाग	368
129.	प्रा.डॉ. महेशबुध्देपोशा बाबूमीर्षी शिरमाळे	आंतरराष्ट्रीय व्यापारावर परिणाम करणाऱ्या घटकांचा अभ्यास	370
130.	प्रा. बाबासाहेब ग्यानदेव सोनवणे प्रा. डॉ. एस. एस. मुळे	डिजिटल पेमेंट पद्धतीचा पंचायतराज संस्थांवरील परिणामांचा अभ्यास	372
131.	सुमित शिवाजी सातपुते	रोकड विरहित व्यवहार व शासकीय योजना - एक अभ्यास	374
132.	डॉ. दीपक व्ही भुसारे, जयश्री आसाराम तळेकर	डिजिटल पेमेंट व्यवस्था :- फायदे आणि अडचणी	377
133.	प्रा.जगन्नाथ टोंपे प्रा.डॉ.प्रभाकर किर्तनकार	रोकड विरहित अर्थव्यवस्था	379
134.	प्रा.डॉ.अनिल दि.वाडकर	डिजिटल देयक प्रणाली वस्तुस्थिती आणि विपर्वास	381
135.	प्रा. सुकुमार दत्तापाटील प्रा.डॉ. एल.एच. पाटील	चिरंतन शेती आणि अन्नसुरक्षा यामध्ये डिजिटल देयकाची भूमिका	384

कॅशलेस व्यवहार आणि बदलती माध्यमे

प्रा.डॉ. कालिदास खिनकर
लोकप्रशासन विभागप्रमुख,
राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड
ता. नि. औरंगाबाद

मागील काही दिवसांपासून भारताची अर्थव्यवस्था चलनातून कॅसलेसकडे मार्गक्रमण करत असल्याचे दिसून येत आहे. पाचशे व एक हजारच्या जुन्या नोटा चलनातून रह झाल्यामुळे बिना रोखीचे व्यवहार वाढण्यास मोठ्या प्रमाणावर सुरुवात झालेली आहे. लहान लहान व्यावसायिकांनी आर्थिक व्यवहारासाठी पिकओएस मशीन, पी.टी.एम., बडी, इंटरनेट बँकींग या अद्ययावत बँकींगशी संबंधित प्रणालीचा वापर सुरु करून आपल्या व्यवसायाला गतिमान करण्याबरोबरच कॅशलेस अर्थव्यवस्था संकल्पनेचा पाया अधिक मजबूत करण्यास हातभार लावलेला आहे.

माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात ग्राहकांना सुलभ, जलद, कार्यक्षम आणि सुरक्षित आर्थिक सेवा देण्यासाठी प्रत्येक बँक प्रयत्न करीत आहे. या बदलत्या व्यावसायिककरणामुळे ग्राहकाला उपलब्ध सेवामधून त्याला हवी असलेली सेवा निवडण्याचे स्वातंत्र्य मिळाले आहे. कोणताही उद्योग, व्यवसाय असो त्याची केवळ माहिती देऊन संबंधित मंडळात त्या उद्योगाची, संस्थेची प्रतिमा आणि विश्वासाहता निर्माण करता येत नाही. त्यासाठी शास्त्रशुद्ध पद्धतीचा वापर व माध्यमांची मदत घेऊन केलेल्या कामाची माहिती जनसंपर्काद्वारे देण्यासाठी विविध माध्यमांचा वापर करून उद्योग व्यवसाय वाढीस लावता येतो.

आजच्या जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या बदलत्या काळाच्या प्रवाहाबरोबरच परिवर्तनासाठी सहकार उद्योगक्षेत्रात जनसंपर्काची जोड दिली तर सहकार उद्योगक्षेत्रात अधिक गतीने परिणामकारक यश मिळविता येईल. वित्तीय संस्थांची स्पर्धेच्या युगात जनसंपर्काच्या प्रभावी माध्यमांचा उपयोग करून बदलत्या सामाजिक माध्यमांच्या युगात प्रगतीसाठी नवी दिशा देणारा ठरू शकतो.

कॅशलेस अर्थव्यवस्था :

एखाद्या वस्तुचे मूल्य अथवा सेवांचा मोबदला, देयकांचा भरणा डेबिट/ क्रेडिट कार्डद्वारे अथवा इंटरनेटच्या आधारे बँकींग प्रणालीचा वापर करून अथवा मोबाईलवरील विविध ॲप्सच्या माध्यमातून करणे. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारे रोख कागदी चलन वापरले नाही तर तो व्यवहार रोकडरहीत म्हणता येईल. संपूर्णपणे रोकडरहीत अर्थव्यवस्था असणारा एकही देश आज जगामध्ये नाही. कॅसलेस व्यवहाराचा अधिकाधिक वापर करणाऱ्यांमध्ये प्रगत राष्ट्रांचा समावेश असला तरी मुख्यतः डेन्मार्क, नार्वे, स्वीडन हे देश वेगाने रोकडरहीत अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल करीत आहेत. अमेरिकेत आजदेखील सुमारे ४५ टक्के व्यवहार रोख रकमेतून केले जातात.

भारतात रोकडरहीत व्यवहारामध्ये फारशी प्रगती नाही. क्रेडिट अथवा डेबिट कार्डचा वापर करून वस्तु किंवा सेवा खरेदी, देयकांचा भरणा यांचा रोकडरहीत व्यवहाराला मुख्यतः समावेश करावा लागेल. कार्डच्या आधारे व्यवहार करण्यासाठी पीओएस यंत्राची (कार्ड स्वाईप यंत्र) गरज असते. कॅसलेस व्यवहार काळा पेसा आणि भ्रष्टाचाराविरुद्ध हा उद्देश डोळ्यासमोर ठेवून पंतप्रधानांनी ५०० आणि १००० च्या नोटा बंदीचा निर्णय घेतला. देशात कॅसलेस अर्थव्यवस्था आणण्याचे स्वप्न त्यांनी पाहिले. महाराष्ट्रही याकडे वाटचाल करीत आहे. येत्या तीन महिन्यात संपूर्ण कॅसलेस व्यवहारासाठी प्रयत्न करण्यात येत असून नागरिकांना आर्थिक व्यवहार मोबाईलच्या माध्यमातून करता यावा यासाठी महावॅलेट सुविधा सुरु करण्यात येणार असून अस ई-वॅलेट सुरु करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरणार आहे. व्यवहारासाठी जनधन योजना, आधार क्रमांक आणि मोबाईल या त्रिसुत्रीचा वापर करण्यात येऊन भविष्यात व्यवहार कॅसलेस केले जाणार आहेत. कॅसलेस अर्थव्यवस्थेचा सर्वाधिक फायदा हा गोरगरीबांना होणार असून मजूर, शेतमजूर, शेतकरी यांच्या जीवनात यामुळे परिवर्तन येईल असा विश्वास अर्थतज्ञांनी व्यक्तिला आहे.

अद्ययावत तंत्रज्ञान :

आजच्या स्पर्धेच्या युगात देशातील तसेच महाराष्ट्रातील वित्तीय संस्थांचे स्वरूप बदललेले असून 'विकासबँक' ही संकल्पना कालबाह्य झाली असून 'ई-बँकींग' ही संकल्पना पुढे आली आहे. इंटरनेट बँकींगमध्ये ग्राहक केंद्रस्थानी मानून बँकांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केले आहेत. आपला ग्राहकवर्ग कोणत्या स्वरूपाचा आहे त्याप्रमाणे त्याला कोणत्या सेवा सुविधा दिल्या पाहिजेत याचा अभ्यास करून बँकांनी समाजाभिमुख कार्यपद्धतीचा अवलंब करून आपल्या व्यवसायात पारदर्शकता आणून बदल केले आहेत.

माध्यमांचे बदलते स्वरूप :

जनसंपर्काचे स्वरूप हे फार व्यापक आहे. काळानुसार जनसंपर्काचे स्वरूप बदलत गेले आहे. जनसंपर्काची सुरुवात गावातील चावडीवरील सभा दबंडी देण्यापासून सुरु होऊन ती आज ई-जनसंपर्कापर्यंत येऊन पाहोचली आहे. आजच्या स्पर्धेच्या युगात आपल्या संस्थेचा किंवा उद्योगाचा व्यवसाय चांगला वृद्धिंगत होण्यासाठी संस्थांनी किंवा उद्योगांनी जनसंपर्काच्या सकारात्मक बाबींचा अवलंब करून संस्थेची प्रतिमा उंचावण्याच्या दृष्टिने कार्य केले पाहिजे. वित्तीय जनसंपर्कासाठी विविध प्रगत माध्यमांचा वापर करून संस्थेची ग्राहकांच्या मनातील विश्वासाहता जपण्याचा प्रयत्न प्रत्येक संस्था, उद्योग करीत आहे. वित्तीय संस्थांनी स्पर्धेच्या युगात आधुनिकतेची कास धरली आहे. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात बँकांनी आपल्या कार्यपद्धतीत बदल केले असून ग्राहकांनी सुद्धा हे बदल स्वीकारले आहेत. बदललेल्या वित्तीय व्यवहाराची माहिती ग्राहकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी बँकांनी नवमाध्यमांचा वापर सुरु केला आहे.

नेट बँकींग :

बँकेत जाऊन कागदपत्राच्या आधारे व्यवहार करण्याची पद्धत डिजिटल या माध्यमातून करणे म्हणजेच नेट बँकींग. साक्षरता आलेल्या ग्राहकांमध्ये ही पद्धत सर्रास वापरली जाते. याला सिटीजन असा दुसरा शब्द आहे. त्या माध्यमातून पैशासंदर्भातील सर्व व्यवहार करता येतात. काही सहकारी आणि सरकारी बँकांमध्ये तसेच खाजगी बँकांमध्ये नेट बँकींगद्वारे म्हणजेच ऑनलाईन व्यवहार केले जातात. मोबाईल बँकींग, सोशल मिडीयामध्ये स्मार्ट फोन मोबाईलद्वारे बँकेतील आपल्या खात्यासंदर्भातील सर्व व्यवहारांची अद्ययावत स्वरूपात माहिती ग्राहकाला मिळते. यासाठी बँकेत मोबाईल नंबरची नोंद करणे आवश्यक असते. आज ई जनसंपर्काचे युग आले आहे. या युगात जगातील कोणत्याही ठिकाणावरून जनसंपर्क साधला जातो.

सारांश :

एकविसाव्या शतकात पदार्पण करीत असतांना संवाद क्रांतीमुळे संवाद वहनाचे चित्र झपाट्याने बदलत आहे. जनसंपर्क व्यवसाय सुद्धा याला अपवाद नाही. माहिती तंत्रज्ञानाच्या युगात एका नविन क्रांतीमुळे माध्यमांची गुणवत्ता वाढली आहे. बदलत्या युगात माध्यमे प्रगती करीत आहेत. वृत्तपत्रे, दूरदर्शन, आकाशवाणी, सोशल मिडीया या माध्यमांद्वारे जनसंपर्क साधला जात आहे. माध्यम कोणतेही असो दूरदर्शन, आकाशवाणी, वृत्तपत्र असो किंवा इंटरनेट सुविधा या सर्व प्रसार माध्यमांचे मुलभूत कार्य हे माहिती व शिक्षण देणे हे होय. एका ठिकाणावरून दुसऱ्या ठिकाणी माहितीचा प्रसार करण्याचे काम ही माध्यमे सक्षमपणे करतात. सर्व माध्यमांशी संबंधीत नव्यानव्या सुधारणामुळे माध्यमांच्या कार्यात एक गती निर्माण झाली आहे. सर्वच क्षेत्रात माध्यमांच्या प्रगतीचा फायदा होताना दिसतो.

जनसंपर्काच्या विविध माध्यमांमध्ये खार बदल झाला तो १९९० च्या दशकांतर या बदलाची दोन कारणे आहेत. एक आर्थिक व दुसरे तंत्रज्ञानविषयक हे येथे विशेष नमूद करावे लागेल. भारतामध्ये उदारीकरण, खाजगीकरण आणि जागतिकीकरणाचे आव्हान तर दुसऱ्या बाजूला बदलत्या तंत्रज्ञानाचे आव्हान होते. यातून माहिती तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती होत गेली. पुढे याचा फायदा सर्वच क्षेत्रांना झाला. माध्यमे सुद्धा यात प्रगत झाली व आज माध्यमांचे युग सर्वांना अनुभवण्यास मिळत आहे.

संदर्भ :

- १) योजना मासिक, 'रोकेडविरहीत अर्थव्यवस्था', फेब्रुवारी २०१६.
- २) योजना मासिक, 'भारताची आभासक वाटचाल' मे २०१६.
- ३) Understanding Digital Wallets Audited wallet, August 2018.
- ४) Dial M for Money- The Economist, 30 June 2007.
- ५) Devid Murphy, 'Dunhill Wallet uses Biometrics' PC Magazine, Retrieved 23 March 2013.



[Signature]

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.

60



ISSN : 2456-9658

Bi-Annual refereed Journal

Global Researcher View

An International Peer Reviewed Journal of Social
Sciences and Humanities

RNI No. RAJBIL/2016/71973

Special Issue : 02 October 2019

महात्मा गांधी : विचार, तत्त्वज्ञान आणि प्रेरणा

Editor

Chandra Shekhar Kachhawa

globalreasearcherview2015@gmail.com



अनुक्रमणिका

अ.क्र.	शोधनिबंध का शीर्षक	लेखक	पृ.क्र.
1	महिला सक्षमीकरण आणि महात्मा गांधीची भूमिका	डॉ. गोपालसिंह बछिरे, दिपिका हिम्मत पवार	7
2	महात्मा गांधीजीची ग्रामीण स्वराज्याची संकल्पना : एक अभ्यास	डॉ. गोपालसिंह बछिरे, मच्छिंद्र रूपचंद चौधरी	10
3	गांधीजी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यातील मतभिन्नता : एक चिकित्सक अभ्यास	विजय साहेबराव साळवे, प्रा.डॉ. गोपालसिंह बी. बछिरे	13
4	जागतिकीकरणाच्या प्रवाहातील पर्यावरण संरक्षण आणि महात्मा गांधी	डॉ. देवराज कोंडीबा दराडे	18
5	महात्मा गांधी आणि ग्रामस्वराज्य	प्रा.डॉ. जे.एस. ढवळे	22
6	महात्मा गांधीचे शाश्वत विकासाचे विचार	डॉ. रामकिशन वसंतराव लोमटे	25
7	महात्मा गांधीचे आदर्श विचार	प्रा.डॉ. संजय मगर	28
8	महात्मा गांधीची शिक्षण व्यवस्था काळाची गरज	प्रा.डॉ. सय्यद मुजीब मुसा	30
9	महात्मा गांधी यांचे स्वच्छतेसंबंधी विचार आणि सद्यस्थिती	डॉ. मंजुषा मोतीराम नळगीरकर	32
10	महात्मा गांधीजीची ग्रामस्वराज संकल्पना	प्रा.डॉ. कालिदास दिनकर फड	36
11	महात्मा गांधीजीचे सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक विचार	प्रा.डॉ. संजीवकुमार सूर्यकांत पांचाळ	38
12	महात्मा गांधी : पर्यावरण संबंधी दृष्टिकोन	प्रा.डॉ. गजानन देवराव चिट्टेवाड	41
13	महात्मा गांधी यांची ग्राम स्वराज्याची संकल्पना : एक ऐतिहासिक दृष्टिक्षेप	प्रा.धनंजय जवळेकर, प्रा.डॉ. जी.व्ही. गट्टी	45
14	महात्मा गांधीच्या सत्याग्रहाची आजची प्रासंगिकता	डॉ. रमाकांत तिडके	48
15	महात्मा गांधीची सामाजिक विकासाबाबतची भूमिका	प्रा.डॉ. गायके एस.के., डॉ.एम.एस. कांबळे	51
16	महात्मा गांधी सत्य-अहिंसा प्रासंगिकता	मंगल गोपालराव गौरे	53
17	महात्मा गांधीजीची विचारधारा, तत्त्वज्ञान आणि प्रेरणा याबद्दलचे विचार	प्रा.डॉ. दिनेश रा. हंगे	55
18	महात्मा गांधीजी यांचे स्वयंपूर्ण ग्राम स्वराज्य : वैचारिक भूमिका	प्रा.डॉ. एच.एन. जमाले, प्रा.एस.एन. मिरे	57
19	उपेक्षितांविषयी गांधी विचार	प्रा.राजेश अनंतराव कांबळे	59
20	महात्मा गांधीचे आर्थिक व सामाजिक विचार	प्रा.डी.के. कटके	62
21	महात्मा गांधीजी : व्यक्तिमत्त्व व ग्राम स्वराज्य संकल्पना	प्रा. कोल्हे टि.टि.	64
22	महात्मा गांधीचे आर्थिक सामाजिक विचार	डॉ. कोरडे ए.एम., पुजा सोपान धनवटे	67
23	महात्मा गांधी आणि पर्यावरण	स्मिता विजय मामीलवाड	70

महात्मा गांधीजींची ग्रामस्वराज्य संकल्पना

प्रा.डॉ. कालिदास दिनकर फड

लोकप्रशासन विभाग, रत्नाची गांधी महाविद्यालय, कसबाड
ता.वि. औरंगाबाद

मार्टिन लूथर किंग यांनी भारताचा गांधीजी असा उल्लेख केला आहे. यावरून भारताची आळख घ्यावी गांधीजी, महान गांधी हे एक नाव नाही तर ते भारताचा अस्मिताचा परिचय आहे. गांधीजींचे विचार हे पाक भारतापुरतेच मर्यादित नसून गांधी तत्त्वज्ञान हे संपूर्ण विश्वाला गुह्या स्वराज्यत मार्गदर्शक आहे. देशातील नव्हे तर जगातील पराभेदींचे विघ्ननाश, जागतिक समस्या सोडविण्यासाठी गांधीजींच्या सत्य, अहिंसा, नैतिकतेचे प्रेम या तत्त्वज्ञानाचा निरिच्छाच उपाय हाईल गांधीजींच्या तत्त्वज्ञानाची, विचारधारेची, कार्याची प्रेरणा घेऊन अनेक महान जागतिक नेते जागतिक घटनांचे आदर्श ठरवून घ्यावीसक्य पाहण्यापेक्षा गांधीजी अस्तित्वाचे व्यापणं सांगतात. यावरून गांधी विचार, तत्त्वज्ञानाची त्यांचा कायची महत्ता लक्षात घेते.

सत्य, अहिंसा आणि प्रेमाचा पाठपुरावा करून महान गांधीजींनी जगाला दुःख करी करवण्यासाठी आपले आयुष्य सामान्यसाठी खर्च घालून, सदाशिवीत देशातील राष्ट्रीय एकता, अखंडता टिकवून ठेवण्यासाठीच नव्हे तर जागतिक शांततेसाठी गांधी विचार तत्त्वज्ञान निरिच्छाच उपयुक्त ठरेल. गांधीजींचे ग्रामविकासचे तत्त्वज्ञान भारताच्या सर्वांगीण विकासासाठी विशेषतः शहरी व ग्रामीण विषयतेची दरी कमी करण्यासाठी अतिशय उपयुक्त आहेत. ग्रामस्वराज्य म्हणजे मुठभर लोकसभे स्वराज्य नाही तर सर्व लोकांचे राज्य होय. असा प्रकारच ग्रामस्वराज्य गांधीजींना अभिप्रेत होते.

गांधीजींना विकासाची प्रक्रिया ही खालून वर जगात ओढात होती. गांधीजींनी खरा भारत खंड्यात पाहिला होता. खंडे हे सभ्य, स्वयंपूर्ण करे होते हे यावर भर दिला. खंडे सभ्य, सामूहिक तर देश संघर्ष, सामूहिक, खंडे ही भारताचा पाया आहे. खऱ्या भारताचे दर्शन खंड्यामध्येच होईल. खंडे हा राष्ट्राचा मुख्य आधार आहे. खरा भारत हा शहरांमध्ये राहत नसून तो खंड्यामध्ये राहतो. ग्रामस्वराज्यत गांधीजींनी प्रत्येकाच्या गरजा

यावाताच पूर्ण काज्यात, तेथील सभ्यता हा स्वातंत्र्य, आपल्या उपनिवेशा परस्परांच्या सहकार्यातून पूर्ण होतील, सहकार्य हा स्वातंत्र्याची गांधीजींच्या मूळ आधार असेल. गांधीजींनी लोक शांततेने सहकार्याने गौरव्याची जीवन व्यतीत करावीत. प्रत्येक गांधीत एक पंचायत असेल व अहिंसात्मक समाजाची स्थापना ही ग्रामस्वराज्यत होईल. ग्रामस्वराज्य हे स्वतंत्र असेल तेथे उच्च विद्या, श्रम, अस्पृश्य, जातिभेद, वर्णभेद असावा नाही. तेथे कोणत्याही शोषण होणार नाही. सर्वांनी सर्वांच्याच श्रमोत्पादने संतुष्ट असतील सर्वांना राष्ट्रीयत्व असेल.

गांधीजींना ग्रामस्वराज्यात सत्तेच्या विकेंद्रिकरणामुळे विशेष आस्था होती. राजकीय सत्तेचे विकेंद्रिकरण जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत गांधीजींच्या सत्तेची विकास होणार नाही. ग्रामस्वराज्यात सर्व प्रकारच्या सत्तेचे विकेंद्रिकरण होऊन स्थानिक पातळीवरच्या विकासात सर्वांचा सहभाग व्हाईल. सत्ता ही लोकसभेमध्येच असेल, सर्व लोकांचा सर्वांगीण असेल. ग्रामस्वराज्य अर्थव्यवस्था ही स्वयंपूर्ण असेल, ग्रामोद्योग, लघुउद्योग, कुटीरुद्योग, हस्तोद्योग स्थापून प्रत्येकांच्या हाताला काम मिळेल. प्रत्येकांची उपजीविका भागविली जाईल. जोपर्यंत श्रमाला प्रतिष्ठा मिळणार नाही तोपर्यंत गांधीजींच्या पंचायते देशाचा विकास होणार नाही. प्रत्येक कामाचे महत्त्व हे सादरेच आहे. कोणतेही काम खंडे वा मांडे नाही. गांधीजींनी ग्रामस्वराज्यात श्रमोत्पादने महत्त्व दिले होते.

खंडे हे शहरी लोकांच्या गरजा भागविताना परंतु खंड्यांचेच शोषण मोठ्या प्रमाणात होत आहे. गांधीजींच्या ग्रामस्वराज्यात उद्योगांना विशेष नक्ता, परंतु लघुउद्योग, कुटीरुद्योग, खंड्यात उभारले जावेत. हस्तोद्योगातून, सत्तेपातळीतून, खंड्यातील लोकांच्या हाताला काम मिळेल. ग्रामस्वराज्यात सामूहिक शहरी वा स्वीकृत केला जाईल. परंतु गांधीजींच्या स्वतंत्रताचा पाया घेऊ नये यावर गांधीजींचा कडाड होत. ग्रामस्वराज्यात गांधीजींच्या सत्तेची गांधीजींचा असली. खंड्यातील लोकांनी आपआपल्या

वस्तुची खरीदी किंवा ... करणे वचकारितेनेच वाचण्यात आली. यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था सक्षम होईल.

गांधीजींनी आपल्या ग्रामस्वराज्यात अन्न, अक्षर, आरोग्य, वायू यावर भर देऊन गांधीजींनी प्रत्येकांच्या हाताला काम मिळाले. प्रत्येकांना सत्तेची आहार, प्रसादा कपडा, राहण्यासाठी घर, वैयक्तिक महत्त्व उभारून घ्यावी. ग्रामविकासावरच ग्रामसफाईच भर दिला. आंगण सभा, सफाईच वाढी सफाई महत्त्वाची मानून रस्ते सफाई, सामूहिक शौचगृह, नैला, सांडपाण्याची व्यवस्था करावी यामुळे ग्रामीण आरोग्याचा प्रश्न सुटेल. गांधीजींनी औपचारिक शिक्षणापेक्षा अनौपचारिक मुलेशोषणी, बुनियादी, हस्तोद्युक्त शिक्षणावर भर दिला. यामुळे गांधीजींनी लोकांना कुतूबुक्त ज्ञान मिळेल. शिक्षण हे राजगारोपिमुक्त असावे. शिक्षणाद्वारे विद्यार्थ्यांच्या शारीरिक, मानसिक, अर्थव्यवस्था शहरी विकसीत कराव्यात. याचा फायदा विद्यार्थ्यांवरच ग्रामस्थाना होईल व ग्रामस्वराज्य प्रस्थापित होईल.

सारांश : गांधीजींनी ग्रामस्वराज्याची संकल्पना ही स्वातंत्र्य, स्वयंपूर्ण सहकार्यावर भर देणारी आहे. ग्रामस्वराज्यात श्रमाला विशेष महत्त्व देऊन प्रत्येकाने आपले कार्य प्रामाणिकपणे करावे. यामुळे गांधीजींच्या लोकांच्या उपजीविका गांधीजींच्या पूर्ण होतील. ग्रामस्वराज्यात विकेंद्रिकरणामुळे सर्वांचा सहभाग होईल व त्यांच्या राष्ट्रीयता निर्माण होईल. गांधीजींची ग्रामस्वराज्याची संकल्पना ही वास्तव्याची व आदर्शपूर्ण सदाशिवीत गांधीजींच्या विद्या देण्यासाठी उपयुक्त आहे.

संदर्भ

- 1) गांधी महात्मा, ग्रामस्वराज्य, पुण्यात प्रकाशन, पृ. ११९५
- 2) गांधी महात्मा, माझा स्वप्नदाल गांधी परंपराचा प्रकाशन, पंचवटी.
- 3) चिंतन नवनिनी, गांधी ग्रंथाली प्रकाशन, मुंबई.
- 4) स्वप्नदाल रमेश, गांधी एक अथवा, विचारधारेची विकासातली किस्ती.
- 5) पारसल अंतन गांधी (अनु. गोडबोले मुळात), गांधीजींचे आत्मचरित्र (अनु. गोडबोले मुळात), गांधीजींचे आत्मचरित्र (अनु. गोडबोले मुळात), गांधीजींचे आत्मचरित्र (अनु. गोडबोले मुळात).
- 6) आर्. विकासा, राष्ट्रीय एकात्मता आणि महत्त्व गांधी, पी. सी. पब्लिशिंग हाऊस, मुंबई.

PRINCIPAL
RAJAW GANDHI ARTS, COMMERCE
AND DIST. AURANGABAD

Impact Factor-7.675 (SJIF)

ISSN-2278-9308

B.Aadhar

Peer-Reviewed Indexed

Multidisciplinary International Research Journal

February-2020

SPECIAL ISSUE-CCVI

*Progressive Thoughts in Maharashtra and
Need of Social Enlightenment of OBCs*



Chief Editor

Prof. Virag S. Gawande

Director

Aadhar Social

Research & Development

Training Institute Amravati

Editor:

Dr. Dinesh W. Nichit

Principal

Sant Gadge Maharaj

Art's Comm. Sci Collage,

Walgaoon. Dist. Amravati.

Guest Editor:

Dr. Balaji P. Munde

Associate Professor

Jalna College of

social work, Jalna

Dist-Jalna



This Journal is indexed in :

- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmos Impact Factor (CIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)

For Details Visit To : www.aadhar-social.com

Aadhar PUBLICATIONS



21	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांची सामाजिक योगदानातील महत्वपूर्ण भूमिका प्रा. डॉ. नरसिंग अ. पवार	81
22	डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्त्री विषयक कार्य प्रा. डा.मीना बोर्डे- सूर्यवंशी	84
23	ओ. बी. सी. समाजासाठी डॉ. बाबासाहेबांचे योगदान व मंडल आयोगाची गरजी प्रा. कळसकर मनिषा पद्माकर	87
24	मंडल आयोगाच्या शिफारशी संदर्भात गोपीनाथराव मुंडे यांची भूमिका प्रा.डॉ. कालिदास दिनकर फड	91
25	जातीअंताचा लढा आणि आरक्षण प्रा.डॉ. जे.टी. कांबळे	93
26	डॉ. नरेंद्र दामोदरकरांची अंधश्रध्दा निर्मूलनाची चळवळ प्रा. डॉ. फरिदा शफीक खान	96
27	सावित्रीबाई फुले एक आदर्श शिक्षिका प्रा. ज्ञानेश्वर श्रीनिवास आघव	100
28	राजर्षी शाहु महाराज: बहुआयामी विचार प्रा.डॉ.डी.के.खोकले	104
29	स्त्री मुक्ती चळवळ प्रा.डॉ.गांधी बानायत	108
30	इतर मागास प्रवर्गांच्या समस्या व उपाय प्रा. डॉ. ए.टी. शिंदे	110
31	अस्पृश्यांच्या सामाजिक न्यायासाठी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी महाराष्ट्रात केलेल्या सामाजिक आंदोलनाचे परिणाम एक अभ्यास प्रा. सुकेशिनी संजय जोगदंड	113
32	महात्मा फुले ह्यांचे अस्पृश्यता निवारणाचे कार्य आणि सामाजिक न्याय प्रा. वनंजे प्रशांतकुमार विठ्ठलराव	118
33	महाराष्ट्रातील ओबीसीतील सामाजिक विषमता आणि सामाजिक अन्याय प्रतिक वसंतराव दांडडे	120
34	Social Reformation through Vachan Sahitya: A Reading Dr. Somnath Barure	123
35	Progressive Thoughts In Maharashtra And Need Of Social Enlightenment Of Obc's Rajesh B. Tandekar	130
36	Ambedkarite Ideology and OBC Dr. Bharat A. Pagare	135
37	Social representation and social support-base of Political parties in Nagpur zp (2012-2019) Dr. Rahul v. Bavage\ Prof. Mohan s. Kashikar	142
38	Dynamics Behind Challenges: Case Of Korku's In Melghat Tiger Reserve Of Maharashtra Nitin Vasantrao Ganorkar	149
39	Progressive Thoughts in Maharashtra and need of social Enlightenment of OBC's. Ghuge Vijaymala Tanaji	153
40	National Scientific Temper Day -Challenges Ahead Pramod Namdeo Muneshwar	157
41	Social Enlightenment And Social Justice Movement in India Dr.Deepak.M.Buktare / Dikshita Shesherao sarpate	160
42	Historical review of Social Reform Movements in India with special reference to Maharashtra. Dr. Madhu Prabhakar Khobragade	164



मंडल आयोगाच्या शिफारशी संदर्भात गोपीनाथराव मुंडे यांची भूमिका

प्रा.डॉ. कालिदास दिनकर फड

लोकप्रशासन विभाग, राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड ता.जि.औरंगाबाद

मागासवर्गीयांच्या संदर्भात नेमण्यात आलेल्या मंडल आयोगाच्या शिफारशी संदर्भात गोपीनाथराव मुंडे, लक्ष्मणराव ढोबळे, मनोहर जोशी, अण्णासाहेब मस्के, संभाजी पवार, आनंदराव देवकाते, गणपतराव देशमुख, तुकाराम दिघाळे, के.एल.मालवदे, नंदकुमार झांबरे, उपेंद्र शेंडे, प्रकाश यलगुलवार, रावधान पवार, भीमराव धोंडे, श्रीपतराव बोंदे, आर.आर.पाटील इत्यादींनी १९ डिसेंबर १९९० विधानसभेत प्रस्ताव मांडले.

तत्कालीन पंतप्रधान व्ही.पी.सिंग यांनी दि.०७/०८/१९९० रोजी मंडल आयोगाची घोषणा केली. त्यामुळे देशात मंडल आयोगाच्या बाजूने व विरोधात गोपीनाथराव मुंडे या आयोगाला भारतीय जनता पक्षाचे समर्थन होते आणि राहणार आहे अशा प्रकारचे मत व्यक्त केले.

मंडल आयोगाच्या घोषणेनंतर काही प्रश्न समाजामध्ये निर्माण झाले. त्याचा आपल्याला निश्चितपणे विचार करावा लागेल. कारण ज्यावेळी आपण घटना स्वीकारली, त्या घटनेमध्ये आपण समता, बंधुत्व आणि कायद्यातील प्रियंबलमध्ये एकात्मतेचा स्वीकार केलेलो आहे. आपल्याला या ४२ वर्षांच्या समाजामध्ये सामाजिक विषमता मोठ्या प्रमाणात आहे. समाजात भेदभाव मोठ्या प्रमाणात आहे असे स्पष्ट होते.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्याचा निर्णय केला परंतु जो झोपडीत बसलेला दलित होता, त्याला ही माहितीसुद्धा नव्हती की, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांचे नाव मराठवाडा विद्यापीठाला देण्याचा निर्णय विधान मंडळाने घेतलेला आहे. पण सर्वांनी रस्त्यावर घेऊन दलितांची झोपडी जाळली आणि त्यांनाही उभे जाळण्याचा प्रयत्न केला आहे. अजून समाजातील सामाजिक विषमता संपलेली नाही हेच सर्वांच्या त्या कृत्यावरून प्रत्ययाला येते. मंडल आयोगाच्या शिफारसी लागू करण्याचा ज्यावेळी निर्णय घेतला त्यावेळी अशाच प्रकारच्या भावना व्यक्त झाल्या.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, लोकमान्य टिळक, आगरकर, छत्रपती शाहू महाराज यांनी जे सामाजिक काम महाराष्ट्रामध्ये केले. त्यामुळे सामाजिक मनाची जडणघडण आमच्यामध्ये झालेली आहे. म्हणून मंडल आयोगाच्या बाजूने वा विरोधात काही स्वाभाविक प्रतिक्रिया या ठिकाणी रस्त्यावर येऊन झालेली नाही. ही तुमच्या आमच्या दृष्टीने सुदैवाची बाब आहे. परंतु हा जरी प्रश्न असला तरी शेवटी आरक्षणाचा उद्देश काय आहे? घटनेमध्ये आरक्षणाची तरतुद कशासाठी करण्यात आली याचे कारण आम्ही सर्व समान पातळीवर नाहीत म्हणून हजारो वर्षे अन्याय झालेला आहे. हजारो वर्षे जे मानवी हक्कापासून वंचित राहिले आहेत अशांना सामाजिक न्याय मिळवून देण्यासाठी आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.

मंडल आयोगासंबंधी निर्णय करतांना आरक्षण विरोधात दोन तीन महत्त्वाची कारणे आहेत. याबाबत शोध घेतला पाहिजे. मंडल आयोग लागू केला तर समाजात असलेली गुणवत्ता संपुष्टात येईल अशा प्रकारचा विरोध आहे, तो हांगीपणा आहे. गुणवत्तेचा ठेका घेतलेला नाही. मला सांगायचे आहे की, गेल्या १० वर्षांमध्ये ३ वेळा एस.एस.सी. मध्ये इतर मागासवर्गीय समाजाचा मुलगा राज्यात पहिला आलेला आहे हे सिद्ध करून दाखविलेले आहे की गुणवत्ता ही कोणा एका समाजाची किंवा एका वर्गाची मालमत्ता नाही.

महाराष्ट्राच्या संदर्भात बोलायचे झाले तर सन १९६१ मध्ये देशमुख समितीने जो अहवाल दिला तो म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये ९८ टक्के आरक्षण असावे. त्यामध्ये १३ टक्के मागासलेल्या जाती म्हणून अनुसूचित जाती आणि ७ टक्के अनुसूचित जमाती, ४ टक्के विमुक्त जाती आणि भटक्या जमातीकरिता आणि १० टक्के मागासवर्गीयांकरिता आहे आणि म्हणून ही गोष्ट खरी आहे की, माझ्या पक्षाचे धोरण सांगतो मागासलेल्या जाती आणि इतर मागासलेल्या संदर्भात बोलायचे झाले तर महाराष्ट्रामध्ये या सवलती प्रत्यक्षात १० टक्के आहेत, त्या १० टक्के सवलती आणि मंडल आयोगाच्या २७ टक्के सवलती महाराष्ट्रामध्ये लागू करावयास पाहिजे. आणि म्हणून या महाराष्ट्रामध्ये ४ टक्के आरक्षण ज्या भटक्या जातीकरिता आहे त्याचा अर्थ फक्त १३ टक्के सवलती महाराष्ट्रात वाढवाव्या लागतील आणि निर्णय करावा लागणार आहे. मागासलेल्या ५२ टक्के साठी २६ टक्के सवलती. या सवलती महाराष्ट्रामध्ये लागू करावयास पाहिजेत. या संबंदाने मी महत्त्वाचा विचार मांडणार आहे. त्याचा विचार शासनाने करावयास पाहिजे. माझे म्हणणे असे आहे की सवलती दिल्या पाहिजेत. पण मागासवर्गीयांना सवलती

देताना गरिबांचाही विचार झाला पाहिजेत. २७ टक्के सोनार, लोहार यांना सवलती दिल्या पाहिजेत. त्या २७ टक्के मध्ये जर इन्कमटॅक्स भरणारा असेल तर त्यामधील केवळ जो गरीब आहे त्यामधील केवळ जो गरीब आहे त्याला दिल्या पाहिजे. केवळ सोनार म्हणून सवलती देता कामा नये. मग त्या सवलती शिक्षणाच्या क्षेत्रात असोत वा नोकरीच्या क्षेत्रात असो त्या करिता ती सवलत देतांना भारतीय जनता पक्षाचे तसेच इतर पक्षाचे सुद्धा हेच मत आहे की, ती सवलत देताना त्या समाजातील गरिबांना सवलत द्या. समाजामध्ये विरोध होत आहे. कारण जे शिकलेले आहेत, जे पुढारलेले आहेत, जे श्रीमंत आहेत ते या गोष्टीचा अधिक फायदा घेत आहेत. परंतु जो खराखरच गरीब आहे त्याला या सवलती आवश्यक आहेत. ते मात्र या सवलतीपासून वंचित राहतात. तेंव्हा मागासलेला आहे म्हणून त्याला सरसकट सवलती देऊ नये. शंबटी समाजातून विरोध होतो. सगळ्यात महत्त्वाचा प्रश्न जो आहे तो म्हणजे कोणत्या जातीचा यामध्ये समावेश होतो, आर्थिक व सामाजिकदृष्ट्या जे मागासलेले आहेत त्यांच्यासाठी प्राधान्य द्यावयास पाहिजे. ज्यांचा आरक्षणामध्ये समावेश नाही, त्यामध्ये सुद्धा मागासलेपणा आहे. अशा दुर्बल घटकांना आरक्षण द्यावयास पाहिजे.

श्री. व्ही.पी. सिंग यांनी मंडल आयोगाच्या सवलती देताना मागासलेल्यासाठी १० टक्के सवलतीची घोषणा केली असती तर समाजामध्ये यास विरोध झाला नसता आणि ४३ वर्षांनंतर सुद्धा समाज समान पातळीवर आला नाही. सामाजिक न्याय मिळाला नाही, आर्थिक न्याय मिळाला नाही. हा न्याय जोपर्यंत मिळत नाही तोपर्यंत समाजातील दुर्बल घटकाला आपल्या पायावर उभे राहण्यासाठी आर्थिक आरक्षण ठेवले पाहिजे आणि त्यासाठी महाराष्ट्रात मंडल आयोग लागू केला पाहिजे आणि त्यानुसार या महाराष्ट्रात २७ टक्के सवलती लागू केल्या पाहिजेत. यावर्षी आपण महात्मा ज्योतिबा फेले यांची स्मृती शताब्दी आणि डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची जन्मशताब्दी साजरी करीत आहोत. तेंव्हा या वर्षी महाराष्ट्र शासनाने मंडल आयोग लागू करण्याच्या बाबतीत निर्णय घ्यावा. त्याला माझा व भारतीय जनता पक्षाचा पूर्ण पाठोपाठ आणि सहकार्य राहील.

अशा प्रकारे मंडल आयोगाच्या संदर्भात गोपीनाथराव मुंडे यांनी पुर्णपणे पाठिंबा दिलेला आहे. समाजामधील सामाजिक व आर्थिक विषमता नष्ट झाली पाहिजे असे त्यांचे प्रखर मत होते व आहे. मागासवर्गीय जाती जमातीमधील सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेपणाचा त्यांनी अभ्यास करून या जातींना आरक्षण मिळावे अशी त्यांची स्पष्ट भूमिका होती. या समाजाला सवलती देताना कसल्याही प्रकारची त्यांची कुचंबणा होऊ नये, जो गरीब आहे, त्याच्याकडे गुणवत्ता आहे. त्यांना न्याय मिळायलाच पाहिजे अशी त्यांची प्रखर भूमिका दिसते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा फुले, लोकमान्य टिळक, गोपाळ गणेश आगरकर, छत्रपती शाहू महाराज यांनी सामाजिक, शैक्षणिक कार्य केले. त्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेत क्रांती घडून आली. या सर्व महापुरुषांच्या विचारांचा प्रभाव गोपीनाथराव मुंडे यांच्यावर पडलेला दिसतो. म्हणून त्यांनी स्वातंत्र्य, समता आणि बंधुत्व या तीन बाबीला महत्त्व दिले.

समारोप :

मुंडे यांनी शेतीतील उत्पादीत मालाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे. यासाठी संघटनात्मक कार्य केले. शेतमालाला रास्त भाव मिळवून देण्यासाठी शेतकऱ्यांना उद्युक्त करून त्यांना न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला. इथेनॉल निर्मितीचे तंत्रज्ञान महाराष्ट्रात आणण्याचे काम कोणी केले असेल तर ते मुंडे यांनी होय. इथेनॉल निर्मितीच्या तंत्रज्ञानाच्या धांपराप्रमाणे खासगी साखर कारखान्यांची संकल्पना आणून स्वावलंबी करण्याचे कार्य त्यांनी केलेले आहे. अतिवृष्टिमुळे गोदाकाठच्या लोकांना महापुराच्या विळख्यात अडकण्याची पाळी आली. त्यांचे दुःख कमी करण्यासाठी त्यांचे अश्रु पुसण्यासाठी, मानसिक आधार देण्यासाठी इतकेच नव्हे तर त्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी मुंडे यांनी गोदा परिक्रमा काढली. गोदा परिक्रमाप्रमाणेच सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी आपल्या हयातीत त्यांनी अनेक संघर्ष यात्रा काढलेल्या आहेत. महागाई, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या, दहशतवाद, उसतोड कामगारांचा प्रश्न यासारख्या समस्या कमी झाल्या पाहिजेत. यासाठी गोपीनाथराव मुंडे अहोरात्र प्रयत्न करीत होते. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रमाणे भटक्या विमुक्तांच्या विकासासाठी त्यांनी अधिक प्रयत्न केले. सामाजिक बांधीलकीची भूमिका घेऊन कार्य करणाऱ्या मुंडे यांच्यावर स्वातंत्र्य, बंधुता या मूल्यप्रणालीचा प्रभाव असल्याचा प्रत्यय येतो.

संदर्भसूची :

- १) शंभू बाबासाहेब के. (२०१८), लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे (जीवन आणि कार्य), चिन्मय प्रकाशन, औरंगाबाद.
- २) रघुनाथ कुलकर्णी, शेतकरी चळवळीची तीन दशके
- ३) महाराष्ट्र शासन (०१ जानेवारी १९९९ शिवराज्य)
- ४) दै. खरी वार्ता (डिसेंबर २००२) गोपीनाथराव मुंडे
- ५) दै. धाडसी नेता (साप्ताहिक) मा.आ. गोपीनाथराव मुंडे गौरव विशेषांक, डिसेंबर २००३

Maharashtra Political Science and Public Administration Conference

Reg.No. MAH/12-83/Aurangabad F-985



Volume - 7 No - 3 Issue - 21 Oct. 2019 ISSN- 2347-9639

37Years

VICHAR MANTHAN

National Research Journal of Political Science and Public Administration
(Peer Reviewed Journal)

IJIF
Impact Factor
2.283

Article 370 of The Indian Constitution
भारतीय संविधान - कलम 360

Article



महाराष्ट्र राज्यशास्त्र व लोकप्रशासन परिषदेची संशोधन पत्रिका

विचार मंथन



मुख्य संपादक - प्राचार्य डॉ. पी.डी. देवरे
संपादक - डॉ. प्रमोद पवार । डॉ. मनोहर पाटील
डॉ. बाळ कांबळे । डॉ. विलास आवारी । डॉ. विठ्ठल दहिफळे



- 62
- कलम ३७० आणि काश्मीर
- प्रा. डॉ. सुनील भा. चकवे
 - कलम ३७० आणि भारतीय राजकीय व्यवस्था
- प्रा. विलास एस. टाले
 - कलम ३७० आणि जम्मू-काश्मीरचे राजकारण ६७
- डॉ. विमल विनोद राठोड
- डॉ. सुशांत चिमणकर
 - काश्मीर विवाद कारणमीमांसा : विश्लेषणात्मक अध्ययन ७३
- प्रा. नितीन माणिकराव बिहाडे
 - जम्मू-काश्मीर समस्यांची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ७६
- सुरेंद्र हरिभाऊ किन्हीकर
 - काश्मीर प्रश्न ऐतिहासिक अवलोकन ८०
- डॉ. गोविंद मा. तिरमानवार
 - जम्मू काश्मीर - कलम ३७० : वास्तविकता आणि भवितव्य ८४
- प्रा. डॉ. संदीप बी. काळे
- प्रा. डॉ. रतन व्ही. राठोड
 - ३७० कलम आणि काश्मीर समस्या ८८
- प्रा. डॉ. बबिता पी. येवले
 - कलम ३७० निरस्त : कारणे आणि परिणाम ९२
- डॉ. गजानन जी. हिवराळे
 - जम्मू-काश्मीर समस्येची ऐतिहासिक पार्श्वभूमी ९७
- प्रा. डॉ. नरेंद्र कृ. राईकवार
 - भारतीय संविधान आणि कलम ३७० १०१
- प्रा. डॉ. संध्या चर्जन
 - ✓ जम्मू-काश्मीर व ३७० वे कलम १०४
- प्रा. डॉ. कालिदास दिनकर फड
 - जम्मू-काश्मीर आणि ३७० वे कलम १०७
- सहायक प्रा. लक्ष्मण बाबाराव यादव
 - नव्या जम्मू-काश्मीरपुढील आव्हाने ११०
- डॉ. प्रशांत विधे
 - ३७० कलम आणि जम्मू-काश्मीर पुनर्रचना कायदा २०१९ यामधील फरक ११७
- प्राचार्य डॉ. धर्मेन्द्र तेलगोटे

* अनुक्रमणिका *

• संपादकीय	3
- प्राचार्य डॉ. पी. डी. देवरे	
• Article 370 of The Indian Constitution	10
- Dr. Jyoti D. Thakare	
• Historical Background And Problem of Jammu & Kashmir	13
- Capt. Dr. Sunil S. Ingale	
• Indian Constitution & Article 35A	15
- Aniket V. Deshmukh	
• Consequences of article 370 of the Constitution of India	19
- Dr. Ashish Kale	
• India China Relations & Jammu Kashmir	22
- Dr. Vidya Raut	
• Indian Constitution and Constitution of Jammu and Kashmir - An Analytical Approach	25
- Dr. Vinod Bhivaji Khaire	
• Merits and Demerits of Abrogation of Article-370	27
- Ku. Aditee Prashant Thakare, - Major Dr. Prashant Thakare	
• Indian and Pakistan Relation	29
- Prof. Rajendra Korde	
• Scraping of Art. 370 - A Constitutional Perspective	33
- Dr. Deepak K. Raut	
• सतराव्या अमन और शांति की बढ़ती आशाएँ औचित्य : अनुच्छेद ३७० निर्वलीकरण	३७
- डॉ. सचिन एस. वेरुळकर	
• जम्मू-काश्मीरची सामाजिक-आर्थिक विषयाची प्रासंगिकता	४१
- डॉ. सचिन एस. जयस्वाल	
• भारतीय संविधान आणि कलम ३७०	४४
- प्रा. डॉ. अनिता ज. तिडके	
• भारतीय संविधानातील अनुच्छेद ३७०	४७
- डॉ. वासुदेव वा. भगत	
• जम्मू- काश्मीर दहशतवाद एक जटिल समस्या	४९
- प्रा डॉ. अरुण मुकुंदराव शेळके	
• कलम ३७० : इतिहास आणि वास्तव	५३
- डॉ. माया एस. वाटाणे	
• कलम ३७० : वास्तव आणि भविष्य	५७
- प्रा. डॉ. प्रदिप टी. वाकोडे	

जम्मू-काश्मिर व ३७० वे कलम

- प्रा. डॉ. कालिदास दिनकर फड

लोकप्रशासन विभागप्रमुख,
राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड ता. जि. औरंगाबाद

गोपवारा :

भारत हा विविध राज्यांचा मिळून बनलेला संघ आहे. या संघात विविध घटकराज्ये आहेत. परंतु त्या सर्वांपेक्षा एक वेगळे असे जम्मू काश्मिर हे घटक राज्य आहे. आपल्या निसर्ग सौंदर्यांनी संपूर्ण विश्वाला भुरळ घालणारे पृथ्वीतलावरील स्वर्ग, नंदनवन आहे. पण हे नंदनवन सतत अशांत, अस्थिर, जाळपोळ, दंगे, घुसखोरी, हल्ल्यांनी कायम घेरलेले आहे. त्यामुळे नंदनवन हा स्वर्ग शापित तर नाही ना? हा प्रश्न नेहमी मनाला सतावत असतो. जागतिक पटलावर जे विविध प्रश्न नेहमी चर्चिते जातात त्या काश्मिरचा प्रश्न नेहमी चर्चिते जातो. असे असले तरी काश्मिरला एक स्वतंत्र वेगळी सांस्कृतिक ओळख आहे.

स्वातंत्र्यापूर्वी भारतात पाचशेपेक्षा अधिक संस्थाने होती. त्यातील जम्मू काश्मिर हे एक संस्थान होते. स्वातंत्र्यानंतर संस्थाने आपल्या स्वखुशीने भारतात व पाकिस्तानात विलीन झाले. त्यातील जम्मू काश्मिर संस्थान येथील राजा हरिसिंग यांनी भारत व पाकिस्तान दोन्हीपासून स्वायत्त, सार्वभौम वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. स्वतंत्र, स्वायत्त राहण्याच्या निर्णयापासून जम्मू काश्मिर राज्याच्या प्रश्नाची सुरुवात झाली आणि हा प्रश्न राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर चर्चितेला जात आहे. या प्रश्नाने जागतिक स्वरूप धारण केलेले आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व भारतात ५६० पेक्षा अधिक संस्थाने होती. सर्व संस्थाने ब्रिटीश साम्राज्याच्या अधिपत्याखाली आपआपल्या संस्थानात कारभार करत होते. प्रत्येक संस्थानावर तेथील राजाचे वर्चस्व/नियंत्रण होते. स्वातंत्र्यानंतर देशातील सर्व संस्थानांना पुर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले की, त्यांनी भारतात राहायचे की पाकिस्तानात. यावर काही संस्थाने वगळता जवळपास सर्वच संस्थाने स्वेच्छेने भारतात समाविष्ट, विलीन झाले, परंतु काश्मिर संस्थानाचे राजे महाराजा हरिसिंग यांनी मात्र भारत व पाकिस्तान या दोन्ही देशांपासून समान अंतर ठेवून स्वतंत्र,

सार्वभौम, वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. काश्मिरने स्वतंत्र, सार्वभौम वेगळे राहण्याचा निर्णय घेतला. काश्मिर हे स्वतंत्र सार्वभौम राज्य निर्माण झाले. याच परिस्थितीचा गैरफायदा कबालियांनी व पाकिस्तानी सैनिकांनी घेतला. त्यांनी २२ ऑक्टोबर १९४७ रोजी काश्मिरवर पूर्ण ताकतिनिशी हल्ला केला. या हल्ल्यास जम्मू काश्मिर राज्यातील मुस्लिम सैनिकांचाही पाठिंबा होता. कबालियांनी व पाक सैनिकांनी काश्मिरचा अध्यपेक्षा अधिक भाग गिळंकृत केला होता. या अचानक झालेल्या हल्ल्यामुळे काश्मिरचे राजे महाराजा हरिसिंग हतबल झाले. त्यांनी याच स्थितीत २४ ऑक्टोबर १९४७ रोजी भारत सरकारकडे मदतीची मागणी केली.

२३ ऑक्टोबर १९४७ रोजी व्ही. पी. मेनन संरक्षण सचिव व जम्मू काश्मिरचे पंतप्रधान मेहरचंद महाजन यांच्यात सविस्तर चर्चा होऊन भारत सरकारच्या बतीने काश्मिरने भारतात समाविष्ट व्हावे या अटीवर काश्मिरला मदत देऊ केली. लॉर्ड माऊंटबॅटन यांनी जम्मू काश्मिरने भारतात समाविष्ट व्हावे तेव्हाच भारत सरकार जम्मू काश्मिरला मदत करू शकतो असे सांगितले. जम्मू काश्मिर स्वतंत्र प्रदेश असून तो भारताचा व पाकिस्तानचाही भाग नसल्याचा पवित्रा माऊंटबॅटन यांनी घेतला होता.

२६ ऑक्टोबर १९४७ रोजी व्ही. पी. मेनन व मेहरचंद महाजन यांनी महाराजा हरिसिंग यांची जम्मू येथील अमर पॅलेस येथे भेट घेतली व तेथेच काश्मिरचे राजे महाराजा हरिसिंग यांनी भारत सरकारच्या 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्शन' करारावर स्वाक्षरी केली. त्याचवेळी जम्मू काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग बनला. त्यामुळे काश्मिरचे रक्षण करणे ही भारत सरकारची जबाबदारी बनलेली होती. परंतु ज्याप्रमाणे इतर अन्य संस्थानांनी भारत सरकारच्या मर्जर अॅग्रीमेंटवर स्वाक्षर्या करून भारतात समाविष्ट झाले. दशा प्रकारची परिस्थिती मात्र काश्मिरबाबत नव्हती. 'इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्शन' वरील स्वाक्षर्या नंतर भारतीय सैन्य कबालियांना हुसकावून लावण्यासाठी सज्ज झाले



होते.

२७ ऑक्टोबर १९४७ रोजी लेफ्टनंट दिवाण रंजित राय यांच्या नेतृत्वाखाली भारतीय सेना काश्मिरच्या मदतीला पोहोचली. या परिस्थितीत नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते शेख अब्दुल्ला यांनीदेखील भारतीय सेनेला साथ दिली व काश्मिरी जनतेला विश्वास दिला की, काश्मिरी जनता एकटी नसून त्यांच्यासोबत पुर्ण देश आहे. भारतीय सैन्याने घैयाने आपल्या शौर्याने कबालियांना, पाकिस्तानी सेनेला हुसकावून लावले. परंतु कबालियांनी व पाकिस्तानच्या सैन्याने अध्यक्ष अधिक काश्मिरचा भाग आपल्या ताब्यात घेतला होता. भारतीय सेना तीव्रतेने आगेकूच करत होती. परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून पाकिस्तानने आर्मी चिफ जनरल ग्रेसी यांना भारतीय सेनेसोबत युद्धासाठी सैनिकांची मदत मागीतली. परंतु जनरल ग्रेसी यांनी काश्मिर हा भारताचा भाग असून आपण कोणत्याही परिस्थितीत सेनेची मदत देऊ शकत नाही. युद्धासाठी सेनेची मदत देणे म्हणजे भारताबरोबर खुले युद्ध करणे होय. म्हणून त्यांनी सेनेच्या मदतीस नकार दिला. भारतीय सेनेची आगेकूच पाहून पाकिस्तान प्रमुख बॅरिस्टर जीना यांनी पंडित नेहरू, माऊंटबॅटन यांना लाहोर भेटीचे निमंत्रण पाठविले. परंतु लाहोर भेटीस जाण्यास गृहमंत्री सरदार वल्लभभाई पटेलानी विरोध केला होता. बॅ. जीनांच्या मते काश्मिरचे भारतात झालेले विलीनीकरण हे हिंसेतून झालेले आहे, तरीही ०१ नोव्हेंबर १९४७ रोजी बॅ. जीना व माऊंटबॅटन यांच्यात लाहोर येथे भेट झाली.

लाहोर भेटीच्या दुसऱ्याच दिवशी ०२ नोव्हेंबर १९४७ रोजी पंडित नेहरू यांनी आकाशवाणीवरून भाषण देऊन युद्धबंदीची घोषणा केली व काश्मिरात शांतता प्रस्थापित झाल्यानंतर संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या देखरेखीखाली जनमत घेऊन त्याद्वारे काश्मिरी नागरिकांनी स्वतंत्र निर्णय घ्यावा अशी आकाशवाणीवरून घोषणा केली. नेहरूंच्या एकाकी युद्धबंदीच्या घोषणेमुळे भारतीय सेनेला आहे त्या स्थितीत थांबावे लागले व काश्मिर प्रश्न संयुक्त राष्ट्रात गेला. तो प्रश्न अधिकाधिक गुंतागुंतीचा बनत गेला. काश्मिर प्रश्नाला भारत-पाकिस्तान प्रश्नाचे स्वरूप प्राप्त होत गेले. पुढे फेब्रुवारी १९४८ मध्ये शेख अब्दुल्ला जम्मू काश्मिरचे पंतप्रधान बनले. १ जानेवारी १९४९ रोजीच्या संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या ठरावान्वये भारत-पाकिस्तान दोन्ही देशात 'सीझ फायर' घोषित करण्यात आली. व दोन्ही

देशांत 'लाईन ऑफ कंट्रोल' (एलओसी) निश्चित करण्यात आली. जो भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात पाकिस्तानकडे आहे त्यास भारत पाकव्याप्त (पीओके) म्हणतो तर जो भाग भारताच्या अधिपत्याखाली आहे त्यास पाकिस्तान भारत व्याप्त (आयओके) काश्मिर म्हणतो. या ऐतिहासिक घटनानंतर काश्मिर प्रश्न हा सतत चर्चिला जात आहे.

नेहरूंच्या एकाकी युद्धबंदीमुळे भारतीय सेनेला आहे त्या स्थितीतून माघार घ्यावी लागली. त्यामुळे पाकव्याप्त (पीओके) काश्मिर हा भाग पाकिस्तानच्या ताब्यात राहिला आहे. इन्स्ट्रुमेंट ऑफ अॅक्शेशनुसार भारत सरकारला तात्पुरत्या स्वरूपात संरक्षण, परराष्ट्र व दूरसंचार या तीनच विषयांचे अधिकार संसदेला मिळाले होते व उर्वरित अधिकार जम्मू व काश्मिरच्या विधीमंडळाला मिळाले होते. जम्मू काश्मिर विधीमंडळाला जास्तीचे अधिकार प्राप्त झाले.

या कालावधीत भारतीय राज्यघटनेत ३७० वे कलम जम्मू व काश्मिरसाठी विशेष स्वरूपाचा दर्जा देणारे, तात्पुरत्या स्वरूपात समाविष्ट करण्यात आले. 'जम्मू काश्मिरला विशेष दर्जा' या कलमामुळे प्राप्त झाला. जम्मू काश्मिर राज्यासाठी काही विशेष पध्दती करण्यासाठी, निर्णय घेण्यासाठी भारताचे राष्ट्रपती जम्मू काश्मिर विधीमंडळाचा सल्ला घेऊन विशेष आदेश देतील. याद्वारेच आजपर्यंत जम्मू काश्मिरमध्ये कार्यक्रम, पध्दती केल्या जात आहेत. त्यामुळे जम्मू काश्मिरला भारत सरकारचे सर्व कायदे लागू होत नाहीत. जम्मू काश्मिरला विशेष राज्याचा दर्जा प्राप्त झाल्यामुळे जम्मू काश्मिरमध्ये देशातील अनेक महत्वाचे विकासापयोगी कार्यक्रम राबवले जाऊ शकत नाहीत. या कार्यक्रमासाठी विधीमंडळाची परवानगी आवश्यक होती. यामुळे अनेक विकासापयोगी उपक्रम राबविण्यात अडचणी येत होत्या.

सन १९५२ साली पंडित नेहरू व शेख अब्दुल्ला यांच्यात "दिल्ली करार" झाला. या करारान्वये जम्मू काश्मिरसाठी स्वतंत्र विशेष तरतूदी करण्यात आल्या. या करारान्वये जम्मू काश्मिरसाठी स्वतंत्र झेंडा, स्वतंत्र राज्यघटना व काश्मिरी नागरीकत्वाची तरतूद मान्य करण्यात आली. १९५४ साली राष्ट्रपतीच्या आदेशाद्वारे राज्यघटनेमध्ये जम्मू काश्मिरसाठी राज्यघटनेत ३५(१) समाविष्ट करण्यात आले. याद्वारे जम्मू काश्मिर विधीमंडळाला अधिकार देण्यात आले. कायमस्वरूपी जम्मू



काश्मिरचे नागरीकत्व ठरविण्याचा अधिकार विधीमंडळाला देण्यात आला. अन्वये ३५(1) अन्वये जम्मू काश्मिर राज्याबाहेरील व्यक्ती जम्मू काश्मिरमध्ये भूमी किंवा इतर मालमत्ता खरेदी करू शकणार नाही, तसेच काश्मिरी मुलीशी विवाह देखील करू शकणार नाही, अशा तरतुदी समाविष्ट करण्यात आल्या. काश्मिरी मुलीने इतर राज्यातील तरुणाशी विवाह केला तर त्या मुलीचेही काश्मिरी नागरीकत्व रद्द होईल अशा तरतुदी समाविष्ट करण्यात आलेल्या होत्या.

जम्मू काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग असला तरीही त्या राज्यासाठी भारत सरकारच्या अनेक कायदे, तरतुदी कलम ३७० व ३५(1) अन्वये लागू होत नव्हत्या. काश्मिरसाठी ते कायदे, त्या तरतुदी अपवाद ठरत होत्या. या सर्व परिस्थितीत काश्मिरी जनतेची दिशाभूल करून अनेक लोकांनी आपली सत्ता उपभोगली. मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली. पाकिस्तान देखील पाकपुरस्कृत दहशतवाद्यांना पाठवून जम्मू काश्मिरला अस्थिर करित होता. फुटीरवादी स्थानिकांना भडकावून देऊन देशविरोधी कारवाया करत होता. या परिस्थितीमुळे काश्मिरच्या सामान्य जनतेचे जनजीवन विस्कळीत होऊन राज्याच्या सर्वच क्षेत्रात पिछेहाट झाली. तरुणांच्या हाती लेखणी ऐवजी मोठ्या प्रमाणावर हत्यारे आली. काश्मिरी तरुण दिशाहीन, भरकटलेल्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे जम्मू काश्मिर अशांत अस्थिर बनवत आहेत.

सद्यस्थितीत भारत सरकारने राष्ट्रपतींच्या आदेशाद्वारे जम्मू काश्मिर विधीमंडळ बरखास्त करून आणीबाणी लावून संसदेने ३७० व ३५(1) कलम बरखास्त करून जम्मू काश्मिर हा स्वतंत्र केंद्रशासित प्रदेश व कारगिल लडाख हा विधीमंडळविरहीत केंद्रशासित प्रदेश अस्तित्वात आणले. अशाप्रकारे कलम ३७० रद्द करून जम्मू काश्मिरच्या विकासाच्या वाटा खुल्या केल्या आहेत.

सारांश :

जम्मू काश्मिर प्रश्नाचा इतिहास किचकट, गुंतागुंतीचा असला तरी हा प्रश्न अतिशय शांततेने संयमाने स्थानिकांचे मन जिंकून, हृदय जिंकून त्यांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणावे लागेल. जोपर्यंत स्थानिकांचा सहभाग वाढविणे, स्थानिकांची मने देशाविषयी जोडणे आवश्यक असून हेच खरे आव्हान देशापुढे आहे. हे आव्हान पेलायला किती दिवस लागतील हे येणारा काळच ठरवेल व त्यावर ३७० कलमाचे भविष्य अवलंबून असेल.

संदर्भ :

1. अभिहोत्री कुलदीप चंद, जम्मू काश्मिर की अनकही कहानी, प्रभात प्रकाशन.
2. पाण्डे आकाशकुमार, कश्मीरनामा, राजपाल अँड सन्स, २०१८
3. कुमार ईद्रेश, जम्मू काश्मिर से साक्षात्कार
4. अभिहोत्री कुलदीप चंद, जम्मू काश्मिर के जननायक महाराजा हरिसिंह, प्रभात प्रकाशन.
5. नुपानी ए. जी., द काश्मिर डिस्प्यूट (१९४७-२०१२)
6. नुपानी ए. जी., कलम ३७० जम्मू काश्मिरचा संवैधानिक इतिहास.

...

राज्यशास्त्र, लोकप्रशासन, इतिहास, समाजशास्त्र, मानसशास्त्र, संरक्षणशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सामाजिकशास्त्रे विषयांचे विद्यार्थी, संशोधक, अभ्यासक, प्राध्यापक, विचारवंत, पत्रकार, समाजसेवक, मान्यवरांनी आपले लेखन विचारमंथन या राष्ट्रीय स्तर संशोधन पत्रिकेसाठी पुढील ईमेल वर पाठवावे. आपला पेपर Peer Reviewed Committee कडून निवड झाल्याचे कळवल्यानंतर आपला सोधनिबंध प्रकाशित केला जाईल. सहभागी लेखनकर्त्यास विचारमंथनचा अंक पाठवला जाईल. त्यासाठी आपल्या संशोधन पेपर सोबत आपला संपूर्ण पत्ता, पीन कोड, महाविद्यालयाचे नाव आणि ई-मेल व मोबाईल नंबरसह पाठवावा.

आपली वर्गणी पुढील खात्यावर जमा करावी

Account Name : VicharManthan

Bank Name : Bank of Maharashtra, College Campus Branch, Jalgaon Account No : 60269111094

IFSC Code : MAHB0001161 Branch Code : 01161

62-50 62-50



MAH MUL/03051/2012
ISSN: 2319 9318

Vidyawarta[®]
Peer-Reviewed International Publication

September 2019
Special Issue 02

MAH/MUL/ 03051/2012

ISSN :2319 9318



Indian Council of
social science research

Impress

Impactful Policy Research in Social Science



Government of India
Ministry of Human Resource
Development

One Day Interdisciplinary National Level Seminar
on
**SELF HELP GROUPS AND SOCIO-ECONOMIC
EMPOWERMENT OF WOMEN**
Friday, 27th September, 2019



Organized By

Department of Economics

Shri Balaji Sansthan, Deulgaon Raja's

SHRI VYANKATESH ARTS, COMMERCE & SCIENCE COLLEGE

Deulgaon Raja, Dist. Buldhana- 443 204.

NAAC Re-accredited at 'B' Level

Editor

Dr. Dnyaneshwar Gore



Reg. No. U74120 MH2013 PTC 251205

Harshwardhan Publication Pvt. Ltd.

At. Post. Limbaganesh, Tq. Dist. Beed

Pin-431126 (Maharashtra) Cell: 07588057695, 09850203295

harshwardhanpubli@gmail.com, vidyawarta@gmail.com

All Types Educational & Reference Book Publisher & Distributors / www.vidyawarta.com



Index

01) सूक्ष्म वित्त व महिलांचे सबलीकरण डॉ. रामदास यशवंतराव माहारे, नागपूर	14
02) बचत गट आणि महिला सक्षमीकरण डॉ. आर. बी. भांडवलकर, यवतमाळ	19
03) महिला बचत गट :महिला सबलीकरणाचा शाश्वत मार्ग प्रा.डॉ. शिवाजी पाते, परभणी	23
04) महिला बचत गट: महिला आर्थिक सबलीकरणाचे प्रभावी प्रतिमान प्रा. पी. एस. मिसाळ, प्रा. डॉ. डी. बी. खरात, जालना.	26
05) महिला स्वयंसहायता बचतगट एक दृष्टीक्षेप डॉ. विजय हिम्मतराव नागरे, बुलडाणा	30
06) स्वयंसाहाय्यता बचत गट — बुलडाणा जिल्हा एक दृष्टीक्षेप प्रा.डॉ.राजेंद्र निंबा बोरसे, लोणार	35
07) ग्रामीण महिला उद्योजकता विकासात महिला बचत गटाची भूमिका प्रा.डॉ. नरेंद्र हरीभाऊ शेंगोकार, बुलडाणा	38
08) महिला सक्षमीकरणात बचत गटाची भूमिका Dr. Sanjay P. Kale, Walgaon	40
09) हिरकणी—नवउद्योजक महाराष्ट्राची—स्पर्धात्मक नाविन्यपूर्ण उद्योग संकल्पना सादरीकरण ... प्रा. हरिष तुकाराम साखरे, बुलडाणा	43
10) महिला सबलीकरणात स्वयंसहायता बचतगटांची भूमिका डॉ. ढास डी. के., बीड	47
11) भारतातील महिला सक्षमीकरणात स्वयं सहाय्यता गटांची भूमिका प्रा.डॉ. दिलीप पांडुरंग महाजन, बुलडाणा	51

- www.vidyawarta.com/03 - http://www.printingarea.blogspot.com
- 24) ग्रामीण महिला उद्योजकता विकासात वाशिम जिल्ह्यातील महिला बचत गटांची भूमिका
 प्रा. डॉ. विनोद रतिराम बन्सले, देऊळगांवराजा. ||100
- 25) ग्रामीण महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्वयंसहाय्यता बचतगट चळवळ
 डॉ. भालेराव जे. के., बीड ||104
- 26) लातूर जिल्ह्यातील महिलांच्या विकासात बचत गटाची भूमिका
 पाटील सुलक्षणा भारत, नांदेड ||107
- 27) स्वयं-सहाय्यता गट, पर्यटन आणि महिलांचे समाजार्थिक सबलीकरण
 डॉ. जगन्नाथ नायण ढाकणे, लोणार ||109
- 28) स्वयंसहाय्यता बचत गट व महिलांचे सबलीकरण
 प्रा.डॉ. वि. बी. पवार, अकोला ||112
- 29) महिला सक्षमीकरणात स्वयंसहाय्यता गटाची भूमिका
 प्रा. डॉ. अनिल खु. ठाकरे, अकोला ||114
- 30) महिला बचतगट काळाची गरज
 प्रा.डॉ. भिमराव प्र. उबाळे, बुलडाणा ||116
- 31) स्त्री सबलीकरण : सामाजिक, आर्थिक दृष्टिकोणातून मुल्यमापण
 डॉ. प्रा. पी. डी. हुडेकर, बुलडाणा ||120
- 32) स्वयंसहाय्यता बचत गट : महिलांना उद्योजक होण्याची संधी
 प्रा.डॉ. मदन शेळके, लातूर ||124
- 33) महिलांच्या आर्थिक व सामाजिक विकासात स्वयंसहाय्य गटांची भूमिका आणि महत्त्व
 डॉ. मधुकर पिराजी शेळके, जालना. ||127
- 34) महिला बचतगट आणि महिलांचे सबलीकरण
 प्रा.कु. स्वाती रामदास शिंगणे, बुलडाणा ||130
- 35) स्व सहाय्यता गट व महिला सबलीकरण
 प्रा. डॉ. फड कालिदास दिनकर, औरंगाबाद ||134



वरील काही सबलीकरणाच्या बाबतील काही अडचणी येत असल्या तरी बचतगटाची ताकद—त्याचप्रमाणे दबावगट वाढत जात आहेत. त्यामुळे खूपच थोड्या दिवसात या अडचणी देखील दूर होऊन महिलांचे सबलीकरण आशा वाढते.

समारोप :-

महिला बचत गटामुळे समाजातील सर्व महिलांनी स्वावलंबी बनतात व महिलांना एकेची सवय लागते. परिणामी महिला सबलीकरणाला फायदा होतो. यामध्ये महिलांना सक्षम बनवल्या जाते. महिला बचत गटामार्फत सभासदांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांमुळे सभासद सामाजिक व आर्थिक विकासात परिणाम होऊन महिला सक्षम बनतात.

संदर्भसूची :-

१. चौगुले सुमती, "महिला सबलीकरणाची नवी दिशा" इंदुजा प्रकाशन
२. भागवत विद्युत, "स्त्रियांचा विकास, कल्याण की सक्षमीकरण", स्त्री मासिक
३. कुलकर्णी विजय - "बचतनामा"

संकेत स्थळे (Websites)

1. www.maharashtra.gov.in
2. www.economywatch.com

□□□

स्व सहाय्यता गट व महिला सबलीकरण

प्रा. डॉ. फड कालिदास दिनकर
लोकप्रशासन विभागप्रमुख,
राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड ता. जि. औरंगाबाद

महिला सबलीकरण. हा शब्द सद्यस्थितीत अतिशय प्रचलित आहे. भारतातील महिला खरोखरच सक्षम आहेत का हा प्रश्न बुद्धिवंतांना पडणे स्वाभाविक आहे. महिलांची परिस्थिती सर्वत्र सारखी नाही. जन्मापासून मृत्यूपर्यंत महिला या सतत कुटुंबात प्रमुखाच्या वर्चस्वाखाली कार्ये करतात. त्यांच्या कार्याची ना कुटुंब, दखल घेतो, ना समाज. पुरुषप्रधान संस्कृतीत पुरुष हे सतत महिलांवर वर्चस्व गाजवतात, त्यांच्या वर्चस्वाखाली, दबावाखाली महिला जगतात. सद्यस्थितीत महिलांमध्ये शिक्षणामुळे जागृती वाढत आहे. त्या पुरुषांच्या वर्चस्वाला झुगारून स्वाभीमानाने, खंबीरपणे सर्व क्षेत्रात आपले अस्तीत्व सिद्ध करत आहेत. महिला सबलीकरणाचे अनेक साधने, प्रतिमान आहेत. त्यातील स्व-सहाय्यता गट (SHG) हे एक महत्वाचे साधन आहे. या स्व-सहाय्यता गटाच्या (SHG) माध्यमातून महिलांमध्ये बचतीची, गुंतवणुकीची सवय लागत आहे. त्यातून महिलांना रोजगार मिळत असून त्यांची आर्थिक उन्नती होत आहे. स्व सहाय्यता गट हे सुक्ष्म अर्थव्यवस्थेतील एक मैलाचा दगड आहेत.

महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि महिलांना आर्थिक स्थैर्य प्राप्त करून देणे हे एक महिला सक्षमीकरणाचे प्रतिमान आहे. हे प्रतिमान प्राप्त करून देण्याचे कार्य स्व सहाय्यता गट (SHG) करत आहे.

स्व सहाय्यता गट (SHG) म्हणजे अशा महिलांचा गट की, ज्या महिला एकाच ठिकाणी राहणाऱ्या ज्यांची सर्वसाधारण पार्श्वभूमी एकसारखीच असते, ज्या एकाच प्रकारचा व्यवसाय करतात, दररोज वा एका विशिष्ट कालावधीत आपसातील पैशाचा समान वाटा एकत्र करून एकमेकांमध्ये समान वाटप करतात. त्यातून

एखादा व्यवसाय करतात. त्याच माध्यमातून त्यांना बचतीची, गुंतवणुकीची सवय लागते व आपला उदरनिर्वाह करतात. अशा गटास स्व सहाय्यता गट (SHG) म्हणतात. या गटामध्ये प्रत्येक महिलांचा समान वाटा असतो. या माध्यमातून महिला एकत्र येऊन आपल्या व्यवसाय, गुंतवणूक नफ्याची चर्चा करतात. त्यांच्यामध्ये वित्तीय साक्षरता वाढीस लागते.

बँकींग सेवा सर्व स्तरापर्यंत, तळागाळापर्यंत पोहोचविणे सरकारचे उद्दिष्ट आहे. काही तांत्रिक बाबीमुळे, आर्थिक निश्चरतेमुळे, उदासिनतेमुळे काही समुदाय बँकींग सेवेपासून दूर आहेत. अशा दुर्लक्षित, दुर्मिळ समुदायांना (SHG) स्व सहाय्यता गटाच्या माध्यमातून बँकींग सेवा पुरवली जाते. यामुळे महिला बँकिंग प्रणालीशी जोडल्या जातात. महिलांच्या आर्थिक प्रक्रियेत सहभाग वाढतो.

स्व सहाय्यता (SHG) गटामुळे महिला स्वतःचे निर्णय वैयक्तिकरित्या घेतात. व्यवसायाच्या माध्यमातून स्वतःच्या पायावर स्वतः उभे राहून सक्षम होत आहेत. स्व सहाय्यता (SHG)-गटाच्या माध्यमातून महिलांमध्ये संपत्ती, भांडवल निर्माण करण्याची वृत्ती वाढत आहे. भांडवली गुंतवणूक, नफा कमावण्याची वृत्ती वाढते. त्यामुळे महिलांची आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होण्याकडे वाटचाल सुरु आहे. महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम होत असल्यामुळे महिलांच्या समस्यांची तीव्रता कमी होत आहे.

महिला सक्षमीकरण म्हणजे महिलांनी स्वतःचे निर्णय स्वतः घेवून सामाजिक, आर्थिक, राजकीय समानता व मानसिक, आर्थिक, वैचारिक स्वातंत्र्य म्हणजे सक्षमीकरण होय. महिला सक्षमीकरणामुळे महिलांचा कौटुंबिक, सामाजिक निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढतो. स्व सहाय्यता गट हे महिला सक्षमीकरणाचे महत्वाचे साधन आहे. स्व सहाय्यता गटाच्या माध्यमातून महिलांचा आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग वाढत आहे. स्व सहाय्यता गटामुळे आर्थिक समावेशकतेत सहभागी होण्यासाठी महिलांसाठी सद्बद्ध वातावरण तयार होते. यामुळे गरीब, दुर्बल, महिलांना आर्थिक विकासाची दारे खुली होऊन त्यांची आर्थिक स्थैर्य प्राप्तीकडे वाटचाल होत आहे. गटाच्या माध्यमातून गरीब, दुर्बल महिलांना मुख्य बँकींग सेवा प्रकारत आणले जात आहे. बँकींग व्यवस्थेद्वारे त्यांना गटासाठी कर्जपुरवठा करून त्यांच्यातील उद्योगशिलता, उपक्रमशिलता वाढीस लावली जाते.

स्व सहाय्यता गट हे महिलांची आर्थिक दुर्बलता कमी करून दुर्बल, दुर्लक्षित महिलांना विकास प्रक्रियेत आणण्याचे कार्य करते.

स्व सहाय्यता गटामुळे महिलांमधील गरीबी दूर होत आहे. त्यांचा आर्थिक स्तर उंचावत आहे. महिलांमध्ये बचतीची, गुंतवणुकीची सवय वाढते. उपक्रमशिलता उद्यमशिलतेमुळे त्यांचा सामाजिक व आर्थिक स्तर उंचावतो. गटांच्या माध्यमातून शिक्षण सामाजिक आरोग्याबाबत जागृती होते. गटामुळे बँकिंग सेवा ही तळागाळातील लोकांपर्यंत पोहोचते. आपआपसात भांडवल वाटप केले जात असल्यामुळे भांडवलासाठी सुरक्षा व हमीची गरज राहत नाही. पैसा व वेळेची बचत होते. त्यामुळे स्व सहाय्यता गट हे महिलांमध्ये सामाजिक व आर्थिक प्रारूप तयार करण्यास मदत करते.

स्व सहाय्यता गटामुळे महिलांमध्ये आर्थिक बचत, गुंतवणुकीची सवय लागते. महिलांचा कौटुंबिक निर्णय प्रक्रियेतील सहभाग वाढतो. महिला एकत्र येतात. आपआपले प्रश्न समस्या चर्चा-विचारविनिमय करून सोडवतात. एकमेकींना धीर, आधार देतात. महिलांमध्ये सामाजिक, आर्थिक, राजकीय जागृती होते. त्यांची गरीबी दूर होऊन त्यांचा सामाजिक, आर्थिक स्तर उंचावला जातो व महिला आर्थिकदृष्ट्या सक्षमतेकडे वाटचाल करत आहेत. गरीबातील गरीब महिलांचा स्व सहाय्यता गटात सहभाग वाढला तर निश्चित स्व सहाय्यता गट हे महिला सक्षमीकरणाचे प्रभावी साधन ठरेल.

संदर्भ :

1. Sreeramala S. - Empowerment of Women Through Self Help Groups, Kalpa Publication, 2006
2. Das Puspita- Self Help Groups, Problems Opportunities and Challenges, Biotech Books, New Delhi.
3. Saguna B.- Empowerment of Rural Women Through Self Help Group, Discovery Publishing House, New Delhi, 2006
4. Pandey S.P., Singh K.S. - Empowerment of Sheduled Caste Women Through Self Groups, Serials Publication, Delhi, 2007
5. Raheem Abdula. - Women Empowerment Through Self Help Groups (SHG)
6. Journal of Social Welfare



जवाहर शिक्षण संस्थेचे
वैद्यनाथ कॉलेज, परळी-वैजनाथ
जि. बीड, महाराष्ट्र-431515

डॉ. बालासाहेब अमोडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद संलग्नित न वैद्यनाथ कॉलेज परळी वैजनाथ जि. बीड,
इतिहास, समाजशास्त्र व प्राणिशास्त्र विभाग यांच्या संयुक्त विद्यमाने आयोजित

एकदिवसीय राष्ट्रीय ऑनलाइन चर्चासत्र
महाराष्ट्रातील दूरदृष्टी नेतृत्व, लोकनेते गांधीनाथराव मुंडे
03 जून, 2020

Editorial Board

Dr. R.K. Ippar
Principal
Vaidyanath College, Parli-Vaijnath

Dr. B.K. Shep
Convener

Dr. V.B. Gaikwad
Convener
Vaidyanath College, Parli-Vaijnath

Dr. R.D. Rathod
Convener



INDEX

- =====
- 1) Gopinathji Munde Saheb: A Phoenix Who Fought for the Welfare of the Common Masses
Dr. Ramakant Dnyanobarao Mundhe, Parbhani 08
- =====
- 2) GOPINATH MUNDE : A HISTORICAL STEP
Dr. Anju Tiwari, Bilaspur, Chhattisgarh 13
- =====
- 3) Gopinath Munde and His Contribution to the Society
Dr Chandra Kanta Panda, Purulia, West Bengal 16
- =====
- 4) Visionary Leadership in Maharashtra: Loknete Gopinathrao Munde
Dr. P.L. Karad, Dist. Beed (MS) 20
- =====
- 5) A Great Politician: Gopinath Munde
Dr. Kavita S. Biyani, Latur 25
- =====
- 6) Public Leader Gopinathrao Munde's political career: A study
Sameer V. Renukdas, Parli-Vaijnath 27
- =====
- 7) Gopinathrao Munde: The Voice of the Deprived Class
Dr. Jaybhaye Vitthal Khanduji, Sonpeth 33
- =====
- ८) सर्व सामान्यांचे नेतृत्व लाे नेते गोपीनाथराव मुंडे
प्राचार्य, डॉ. आर. . इप्पर, परळी 37
- =====
- 09) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे पुरोगामित्व ओवीसी जनगणने संदर्भातील कार्य
प्राचार्य डॉ विठ्ठल घुले, परभणी 41
- =====
- 10) लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे सामाजिक विकासामाठी योगदान
डॉ. मीना प्रकाश कुटे, मुंबई 45
- =====
- 11) मंडल आयोगाबाबत लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांची भूमिका :- एक चिकित्साक अभ्यास
प्रा. डॉ. बंदना राजेश शिंदे, जि. सिधुदुर्ग 49
- =====



- १२) लोकनेते गोपीनाथ मुंडे आणि ऊसनोड कामगार
डॉ.प्रा.सौ. एस.पी. लाखे, जिल्हा-नागपूर (महाराष्ट्र) 53
- 13) भटक्या विमुक्त जाती- जमाती विकसभीमुख मने : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
मिंधू निवृत्ती लोणकर, औरंगाबाद 57
- 14) ओबीसी/भटके विमुक्त जाती जमातीच्या विकासात लोकनेते गोपीनाथरावजी मुंडे यांचे योगदान
श्री.निल देविदास फड 61
- 15) आदर्श राजकीय नेतृत्व लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
प्रा.डॉ. बापुराव आंधळे, सोनपेठ 67
- 16) महाराष्ट्रराज्यातील द्रष्ट व्यक्तीमत्त्व: गोपीनाथजी मुंडे
डॉ.दत्तात्रय वी.दराडे,नासिक. 70
- 17) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांची राजकीय वाटचाल : एक अभ्यास
डॉ वात्रामाहेय श्रेय, जि. वीड. 72
- 18) गोपीनाथराव मुंडे आणि ओबीसी जनगणना सडा
प्रा. डॉ. बालाजी पाटलोबा मुंडे, जालना. 77
- 19) मंडळ आयोगाच्या शिफारसी संदर्भात लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे विचार
डा. वाळामाहेय मुंडे, अंबाजोगाई 80
- 20) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे ऊसनोड कामगार विषयक कार्य
डॉ. गट्टी गणपत विष्णू, मिरसाळा. 83
- 21) प्रखर राजनीतिज्ञ गोपीनाथ मुंडे का जीवन एवं कार्य एक ऐतिहासिक अध्ययन
Dr. Jitesh A. Sankhat, Rajkot Gujart 87
- 22) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे समाजमान्य नेतृत्वाची जडण-घडण : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास
डॉ.कान्दिदास मारुती भांगे, जि.औरंगाबाद. 89
- 23) लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे यांचे संघर्षात्मक कार्य
डॉ. रमेश श्रॉडीराम राठोड, जिल्हा वीड. 95



- 24) लोकनेते गोपीनाथ राव मुंडे यांचे राजकीय विचार व कार्य
डा.सचिन भा. बोधाने, चंद्रपूर
- 25) " महाराष्ट्रातील विमुक्त भटक्या जाती-जमातींचा विकासात लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे योगदान "
डा.मुनिता हनुमंतराव गिणे, जि. सातारा 103
- 26) ऊर्जेचे अमोघ स्रोत, सामान्यानील असामान्य नेतृत्व : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
प्रा. व्ही.वी.गायकवाड, जिन्हा वीड , महाराष्ट्र 106
- 27) ॥ राजकारणातील धुरंधर नेतृत्व : लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे ॥
डा.विजय एच.नागरे, जि.दुलडाणा 110
- 28) मराठवाऱ्याचा लोकनेता गोपीनाथ मुंडे यांचे मुस्लिम समुदायासाठीचे कार्य
डाॅ झाकीर पठाण, औरंगाबाद . 118
- 29) राजकारणातील धुरंदर नेतृत्व: लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
चुगे अनंत शंकरराव, परभणी. [म.रा.] 121
- 30) देशपातळीवर भटके विमुक्त जाती जमाती अायोग स्थापन करण्यासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान.
प्रा.डा.कालिदास दिनकर फड, जि.औरंगाबाद 125
- 31) बहुजनांचा नेता लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
डाॅ. मिना गीताराम मेहत्रे, परळी वै. 128
- 32) मान्यवरांच्या शोक सदेशानून प्रगट होणारे स्वर्गीय गोपीनाथराव मुंडे साहेबांच्या नेतृत्वाचे पैलू
प्रा.डाॅ. देवर्षी मुकुंद अरविंद, जि.वीड 132
- 33) " महाराष्ट्रातील शेतकरी व गोपीनाथराव मुंडे : एक अभ्यास "
मुंडे दत्तात्रय रामकिशनराव, परळी -वैजनाथ. 136
- 34) लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांची सामाजिक न्यायातील भूमिका
प्रा.डाॅ. मुंडे रामकिशन हरिदास, जि. औरंगाबाद. 142
- 35) आधुनिक महाराष्ट्राच्या इतिहासातील एक तेजस्वी, धुरंधर, रणभुंजार, संघर्षशील नेते कै. गोपीनाथराव मुंडे
डाॅ. पांडुरंग चाटे 146



- 49) मैत्री जगतातील भीष्माचार्य लोकनेते गोपीनाथ राव मुंडे
प्रा. डॉ. रामकृष्ण वदने, जि.नांदेड 198
-
- 50) लोकनेते गोपीनाथ मुंडे यांचे महाराष्ट्रातील विमुक्त भटक्या जाती व जमाती विकासातील योगदान
प्रा.डॉ प्रकाश फड, परळी वै. 202
-
- 51) गोपीनाथ मुंडे यांचा जीवन संघर्ष आणि सामाजिक विकासाच्या सर्वांगीण संकल्पना
प्रा.डॉ गंगाधर कायदे पाटील, नाशिक 205
-
- 52) राजनीति के धुरंधर नेतृत्व ----- लोकनेते गोपीनाथराव मुंडे
अरविन्द कुमार, परली वैजनाथ रेलवे स्टेशन 209
-
- 53) लोकनेता गोपीनाथराव मुंडे का सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक विचार और कार्य
निशा भारती, नवादा, बिहार 213
-
- 54) **ऊमतोड कामगार व गोपीनाथराव मुंडे**
काळूशे किशोर नारायण, परळी वै 217
-
- 55) "महाराष्ट्रातील उपेक्षित भटक्या समाजाच्या विकासात गोपीनाथ मुंडे यांचे योगदान"
प्रा.डॉ.व्ही.बी.लांब. & सौ.अनुराधा पवार (गोरे), जि.सांगली 220
-



देशपातळीवर भटके विमुक्त जाती जमाती अायोग स्थापन करण्यासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान

प्रा.डाॅ.कालिदास दिनकर फड

लोकप्रशासन विभाग,

राजीव गांधी महाविद्यालय,करमाड,ता.व.जि.औरंगाबाद

★ प्रस्तावणा:-

छत्रपती राजश्री शाहु महाराज, महात्मा ज्योतीबा फुले व डाॅ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा लोककल्याणकारी व बहुजनवादी हा खरा वारसा पुढे गोपीनाथ मुंडे यांनीच चालवला, हे करताना त्यांनी प्रस्थापितांना मागे सारून हजारों वर्षांपासून सतत भटकत फिरणा-या व कपाळावर गुन्हेगारीचा ठप्पा बसलेल्या भटक्या जाती जमातींना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी चे अनेक प्रयत्न वास्तविक पणे राबणारा नेता म्हणुन गोपीनाथ मुंडे यांची भूमिका व योगदान फार मोठे आहे.

★संशोधन लेखाचा उद्देश्य-

भटक्या जाती- जमातींच्या कल्याणात व त्यांच्या सर्वांगीण विकासात महत्वपूर्ण ठरलेल्या केंद्रीय भटके विमुक्त जाती जमाती अायोगासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी केलेल्या कार्याचे योगदान नेमके काय आहे हे तपासणे सदर लेखाचा उद्देश्य आहे.

★संशोधन लेखासाठीची संशोधन पध्दती-

सदर संशोधन लेखासाठी ऐतिहासिक, वर्णनात्मक व विस्मृतेणात्मक संशोधन पध्दतीचा उपयोग केला असुन त्यासाठी प्राथमिक व दुय्यम साधनसामग्रीचा वापर करण्यात आला आहे.

★विमुक्त भटक्या जाती-जमाती:-

परिकीय आक्रमणे,ब्रिटीशांच्या विरोधात प्रथम लढा उभारणारा,आद्यक्रांतीकारक असा हा आमचा विमुक्त समाज तर अन्न,वस्त्र,निवारा,रोजगारासाठी सतत भटकंती करणारा,या देशाची परंपरा,लोककृती,लोकपरंपरा,लोकधारा,धर्म,संस्कृती यांना परकिय आक्रमणापासुन रक्षण करणारा,त्याचा प्रचार,प्रसार व संवर्धन करणारा हा समाज आहे.परंतू येथिल सरकार,प्रशासन आणि व्यवस्थेने त्यांना गुन्हेगार आणि भिकारी ठरवले.

★राष्ट्रीय स्तरावर भटके विमुक्त अायोगासाठी योगदान:-

केंद्रात भाजपाचे सरकार असल्यामुळे त्यांनी भटके विमुक्तांचे केंद्र सरकारच्या अखत्यारित्या असलेल्या प्रश्नासाठी लढा व पाठपुरावा चालुच ठेवला होता.त्याच दरम्यान दादा इदाते यांनी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी आणि उपपंतप्रधान लालकृष्ण आडवाणी यांच्याकडे केंद्रीय अायोग स्थापन करण्यासाठी निवेदन दिले होते.गोपीनाथजी मुंडे यांनी वारंवार या नेत्यांची भेट घेऊन या मागणीचा पाठपुरावा चालुच ठेवला होता.याचाच परिणाम म्हणजे

पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांनी १५ ऑगस्ट २००३ रोजी लाल किल्ल्यावरून भाषण करताना भटके विमुक्तांना प्रवाहात आणण्यासाठी त्यांच्या समस्यांच्या अभ्यासाठी राष्ट्रीय अायोगाची घोषणा केली.

★राष्ट्रीय भटके विमुक्त जाती जमाती अायोग:-

श्री.नाईक अायोग(२२ नोव्हेंबर,२००३):-



भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सशमिकरण मंत्रालयाअंतर्गत भटके विमुक्त जाती जमातीच्या अख्यक्षेत्रातील राष्ट्रीय विमुक्त धुमंतू अर्ध धुमंतू जनजाती आयोगाची स्थापना दि.२२ नोव्हेंबर २००३ रोजी करण्यात आली.अध्यक्षपदाची जबाबदारी श्री.नाईक यांच्याकडे देण्यात आली परंतु काही कारणास्तव आयोगाचे कार्यच सुरु झाले नाही.त्यातच त्यांनी राजीनामा दिला आणि आयोगाचे काम काही काळामाठी स्थगित झाले होते.

★भटके विमुक्त महामेळावा,पंढरपूर:-

आयोगाचे कामकाज लवकर चालू व्हावे,अटलजींनी आयोगाची स्थापना केल्यामुळे आणि भटक्या विमुक्तांच्या समास्या त्यांच्यापर्यंत पोहचव्यात यासाठी लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी दि.२२ जानेवारी २००४ रोजी पंढरपूर,जि.सोलापूर येथे भटके विमुक्तांचा महामेळावा आणि अटलजींच्या सत्काराचे नियोजन केले होते.आजवरच्या इतिहासातील हा ऐतिहासिक असा मेळावा झाला होता जो पुन्हा कधीही झाला नाही.या मेळाव्यात गोपीनाथजी मुंडे यांनी या समाजाच्या समस्या अटलजीसमोर मांडल्या आणि यान लक्ष घालण्याची विनंती केली.तसेच आयोगाचे तात्काळ पुर्नघटन करण्याची विनंती केली.अटलजींनी पण तात्काळ आयोगाची रचना करुण या वंचित,उपेक्षित समाजाचे प्रश्न मार्गी लावण्याची घोषणा केली.पण पुढील काही काळातच केंद्रातील भाजपाचे सरकार गेले आणि काँग्रेसचे सरकार सत्तेत आले.

★श्री.बाळकृष्ण रेणके आयोग (२००५-२००८) शिफारसी साठी लढा:-

गोपीनाथजी मुंडे यांनी विविध संस्था आणि संघटनांच्या माध्यमातुन मत्सेवर आलेल्या सरकारकडे राष्ट्रीय आयोग गठित करण्यासाठी पाठपुरावा व दवाव वाढविला होता तसेच काही संस्था व संघटना न्यायालयात पण गेल्या होत्या.त्याचा परिणाम म्हणून डाॅ.मनमोहन सिंग यांच्या सरकारने दि.१६ मार्च,२००५ रोजी जेष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते श्री.बाळकृष्ण रेणके यांच्या अध्यक्षतेखाली आयोगाची स्थापना केली.आयोगाचे प्रत्यक्षात कामकाज ६ फेब्रुवारी २००६ पासून सुरु झाले.३० जून २००८ रोजी आयोगाचा अहवाल सरकारकडे सादर झाला.परंतु सरकारने वेळकाडुपणाचे धोरण स्विकारत आयोगाच्या शिफारसीचा अभ्यास करण्यासाठी एक समिती डाॅ. नरेंद्र जाधवांच्या अध्यक्षतेखाली नेमली. त्या समितीच्या सुचनेप्रमाणे रेणके आयोगाच्या शिफारसी न स्विकारता त्या आणखी एका नविन आयोगाची गरज असल्याचे नमुद केले.गोपीनाथजी मुंडे यांनी रेणके आयोग लागू करण्यासाठी सरकारकडे निवदने दिली.स्वतः पंतप्रधान डाॅ.मनमोहन सिंग यांची भेट घेतली.त्यांनी आंदोलनाचा देखिल पवित्रा घेतला होता.सरकार,विचारसरणी यांचा कसलाही विचार न करता,कुणाला श्रेय मिळेल याचाही विचार न करता भटक्या विमुक्तांसाठी सर्वस्व पनाला लावनारा हा लोकनेता होता.

★ओबीसी जनगणना करण्याची मागणी:-

इ.स.२००९ मध्ये लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांनी बीड लोकसभा निवडणुक लढवली आणि मोठ्या मताधिक्याने ते विजयी झाले आणि राष्ट्रीय राजकारणात त्यांचा प्रवेश झाला.पहिल्याच टप्प्यात त्यांची लोकसभेच्या उपनेते पदी आणि लोकलेखा समितीच्या अध्यक्ष पदी निवड झाली हे त्यांच्या नेतृत्वाचा करिष्मा होता.दिल्लीच्या राजकारणात गेल्यावर सहसा बरिच नेते जुळवुन घेण्याच्या नादात मबाळ होतात पण गोपीनाथजी मुंडे मधला सामाजिक न्यायाच्या प्रतिक्षेत असेलेला ओबीसी जागा झाला.केंद्रिय पातळीवर सर्व भटके विमुक्त जे विविध राज्यात विविध प्रवर्गात आहेत ते एकत्रित ओबीसी या प्रवर्गात येतात आणि जे महाराष्ट्र सोडता प्रचंड मागासलेले आहेत फ्याना कोणतेही राजकीय नेतृत्व नाही तरयाची जाणीव त्यांना होती.दि.६ मे २०१० रोजी गोपीनाथजी मुंडे नियम १९३ अन्वये लोकसभेत ओबीसींच्या स्वतंत्र जनगणनेची मागणी केली.१९३१ नंतर ओबीसींची जनगणना झालेली नाही.या देशात पशुंची,जनावराची,पक्षाची जनगणना होते तर ओबीसींची का नाही असा प्रश्न उपस्थित केला एका ज्वलंत प्रश्नाला हात घातला.संपूर्ण देशात एका प्रस्तापित राजकिय व्यवस्थेत भूकंप आला होता.ओबीसी मधिल अनेक जाती जमाती दलितांपेक्षाही वार्डट आणि हिन जीवन जगतात याची जाणिव त्यांनी सरकारला करुन दिली. आज ओबीसी प्रवर्गाला मिळालेला घटनात्मक दर्जा,कायम स्वरुपी राष्ट्रीय ओबीसी आयोग याचे मुळ गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान आहे.

★राष्ट्रीय भटके विमुक्त जाती जमाती आयोग(९ जानेवारी २०१५ - ८ जानेवारी,२०१८):-

कर्मवीर दादा इवाते यांच्या अध्यक्षतेखाली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी राष्ट्रीय विमुक्त धुमंतू अर्धधुमंतू जनजाती आयोगाची स्थापना केली.खरं तर हा राष्ट्रीय आयोगच मुळ महाराष्ट्रातील इवाते समितीच्या(१९९९) शिफारसीवर आधारित आहे आणि दादा इवाते यांची अध्यक्षपदी निवड झाल्यामुळे गोपीनाथजी मुंडे यांना अपेक्षित कार्य त्यांच्या मृत्युपश्चात दादा

इदाते पुढे चालुच ठेवले. तीन वर्षांच्या कार्यकाळात त्यांनी अतिशय अभ्यासपूर्वक अशा शिफारसी सहित आपला अहवाल ८ जानेवारी रोजी केंद्र सरकारला सादर केला आणि हा आयोग लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांना समर्पित करित असल्याची भावना व्यक्त केली आहे. केंद्र सरकार सकारात्मक प्रतिसाद देत आहे. केंद्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाती कल्याण मंडळाची २०१९ च्या अर्थसंकल्पात घोषणा देखिल करण्यात आली आणि कर्मवीर दादा इदाते यांच्या अध्यक्षतेखाली स्वातंत्र्यानंतर पहिल्या विकास व कल्याण मंडळाची स्थापना सुध्दा करण्यात आली आहे.

★निष्कर्ष-

एकंदरित आपण लोकनेते गोपीनाथजी मुंडे यांचे योगदान किती अविस्मरणीय होते, त्यांची दुरदृष्टी किती श्रेष्ठ होती आणि या समाजाच्या विकासाचा पाया किती भक्कम त्यांनी रचून ठेवला आहे याची जाणीव होत आहे. ओबीसी जनगणना, राष्ट्रीय विमुक्त घुमंतू अर्धघुमंतू जनजाती आयोग, ओबीसी घटनात्मक दर्जा, ओबीसी आयोग, केंद्रीय विमुक्त घुमंतू जनजाती कल्याण मंडळ, ऊसतोड कामगार कल्याण मंडळ ई. निर्माण होत असलेल्या व्यवस्थेचे मुळ गोपीनाथजी मुंडे यांचे या चळवळीतील निस्वार्थ भावनेने दिलेले योगदान आहे याचा विसर आपल्याला पडता कामा नये. खऱ्या अर्थाने भटक्या विमुक्त समाजाला विकासाच्या, सामाजिक, शैक्षणिक, राजकीय प्रवाहात आणण्याचे प्रक्रिचे गोपीनाथजी हे आद्य प्रवर्तक व प्रणेते आहेत.

★संदर्भ-

- 1). विमुक्त जाती व भटक्या जमाती अभ्यास व संशोधन (इदाते समिती) अहवाल, समाज कल्याण विभाग, महाराष्ट्र शासन, जानेवारी १९९९.
- 2). राष्ट्रीय विमुक्त जनजाती आयोग (इदाते आयोग) अहवाल (२०१८), सामाजिक न्याय विभाग, भारत सरकार
- 3). लोकनेता स्मृती विशेषांक, भाजपा मुंबई
- ४). लोकनेते गोपीनाथ मुंडे आणि त्यांचे कार्य, डाॅ. बाबासाहेब शेप.

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.



64

OUR HERITAGE

ISSN (Online) : 0474-9030 Vol-67, Special Issue-11

Impact Factor (2020) - 6.8



161	औरंगाबादमधील नाट्यचळवळीची सद्यस्थिती	डॉ.गणेश मदनराव शंदे	
162	"भारतीय समाज शिक्षण आणि संस्कृतीचा समाजशास्त्रीय अभ्यास"	प्रा. डॉ. गायके संदिपान	
163	"उस्मानाबाद शहरातील निजामकालीन वाड्यांची सामाजिक ऐक्यामधील भूमिका : संक्षिप्त आढावा"	प्रा.डॉ.जयश्री रमेश कुलकर्णी (देशमुख)	
164	हैदराबाद संस्थानातील वंदे मातरम् चळवळीत मराठवाड्यातील विद्यार्थ्यांचा सहभाग	प्रा.डॉ. पी.आर.जुनघरे	
165	औरंगाबाद जिल्ह्याचा समृद्ध ऐतिहासिक वारसा	डॉ.वनिता साबळे-चव्हाण प्रा. कर्ती विकास वर्मा	
166	मराठवाड्यातील संत साहित्य	मानसी सचिन सरदेशपांडे	
167	"मराठवाड्यातील स्त्री जीवन आणि सद्यस्थिती"	डॉ. कांबळे एम.एस.	
168	मराठवाड्यातील नामांतर आंदोलन : एक समाजशास्त्रीय अभ्यास	प्रा. डॉ. सुनीता आत्माराम टेंगसे गांगर्डे गोपाळ मदन	
169	भारतातील पर्यटनाची स्थिती	प्रा.कदम रिता	
170	मराठवाड्याच्या विकासातील आव्हाने	प्रा. डॉ. राजु बनारसे डॉ. सत्यपाल कांबळे	
171	औरंगाबाद जिल्ह्यातील पर्यटन अभ्यास विशेष संदर्भ अजिंठा लेणी	प्रा.डॉ.का लदास दिनकर फड	
172	बीबी का मकबरा एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ	प्रा. घाडगे मिलिंद व्यंकटी	
173	नामांतर चळवळ	प्रा. रघुनाथ व्यंकटी घाडगे	
174	शैलगृह वास्तुशिल्पकला : वेरूळचे कैलास मंदिर	प्रा. सोमनाथ व्यंकटी घाडगे	
175	मराठवाड्याचा पाणी प्रश्न आणि जायकवाडी धरण	सत्यजीत श्रीनिवास मस्के डॉ.उमाकांत राठोड	
176	निजामशाहीतील शाह ताहीरचे शैक्षणिक कार्ये	प्रा. डॉ. सय्यद मुजीब मुसा	

1515-1519

प्रा. डॉ. सुनीता आत्माराम टेंगसे, गांगडोपाळ मदन

PDF



भारतातील

पर्यटनाची

स्थिती

(https://archives.ourheritagejournal.com/index.php/oh/article/view/4104)

1520-1524

प्रा. कदम रिता

PDF

डॉ.

कांबळे

एम.एस.

(https://archives.ourheritagejournal.com/index.php/oh/article/view/4105)

1525-1527

प्रा. डॉ. राजु वनारसे, डॉ. सत्यपाल कांबळे

PDF

औरंगाबाद जिल्हयातील पर्यटन अभ्यास विशेष संदर्भ अजिंठा लेणी

(https://archives.ourheritagejournal.com/index.php/oh/article/view/4106)

1528-1531

प्रा. डॉ. कालिदास दिनकर फड

PDF

बीबी का मकबरा एक ऐतिहासिक पर्यटन स्थळ

(https://archives.ourheritagejournal.com/index.php/oh/article/view/4107)

1532-1535

प्रा. घाडगे मिलिंद व्यंकटी

PDF

नामांतर

चळवळ

(https://archives.ourheritagejournal.com/index.php/oh/article/view/4108)

1536-1540

प्रा. रघुनाथ व्यंकटी घाडगे

PDF

शैलगृह वास्तुशिल्पकला : वेरूळचे कैलास मंदिर

(https://archives.ourheritagejournal.com/index.php/oh/article/view/4109)

1541-1546

प्रा. सोमनाथ व्यंकटी घाडगे

PDF



औरंगाबाद जिल्हयातील पर्यटन अभ्यास विशेष संदर्भ अजिंठा लेणी



प्रा.डॉ.कालिदास दिनकर फड

लोकप्रशासन विभाग,

राजीव गांधी महाविद्यालय, करमाड

ता. जि. औरंगाबाद

मो.नं.७३८७९९८३८८

E-mail : phadkalidas20@gmail.com

पर्यटकांसाठी पर्यटन हा नव्या जगात जाण्याचा अनुभव आहे. स्वप्नाची पुर्तता, विलोभनीय मनमोहक दृष्यापासून मिळणारे सुख आहे. परंतु ज्या देशामध्ये पर्यटक येतात, त्या देशासाठी हा एक नवा अनुभव आहे. पर्यटक पर्यटनाचा मनमुराद आनंद घेतात. पर्यटन स्थळांना पाहून आनंदी होतात. तेथील कलेला दाद देतात. ज्ञान संपादन करतात व पर्यटन स्थळे पाहण्याचा मोबदला देखील देतात. पर्यटकांना पर्यटन स्थळांवर विविध सुविधा उपलब्ध करून देणे देखील आवश्यक आहे. यासाठी केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय व राज्यस्तरीय पर्यटन विभाग विविध सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करतात.

औरंगाबाद हे मराठवाड्याची राजधानी म्हणून प्रसिद्ध आहे. अजिंठा, वेरुळ ही जगप्रसिद्ध पर्यटन स्थळे, पितळखोरा लेणी, पैठण, पैठणी केंद्र, बीबी का मकबरा, पाणचक्की, दौलताबाद किल्ला ही ऐतिहासिक पर्यटन स्थळे मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद जिल्हयात आहेत. औरंगाबाद हे 400 वर्षांचा ऐतिहासिक वारसा असलेले शहर असून या शहराची मलिक अंबरने निर्मिती केली. प्रशासकीय व सुरक्षिततेच्या दृष्टीने एक महत्वपूर्ण शहर केले. औद्योगिक, शैक्षणिक, ऐतिहासिक व पर्यटनासाठी हे शहर जगप्रसिद्ध आहे.

राजतडाग हे औरंगाबादचे मुळ नाव होते. खाम नदीच्या काठावर हे शहर इ.स. 1604 मध्ये वसवले होते. सुरुवातीस या शहराचे नाव खडकी होते. मलिक अंबरचा उत्तराधिकारी फतेहखान याने इ.स.1629 मध्ये या शहराचे नामकरण फतेहपूर असे केले. इ.स.1653 साली औरंगजेबला दक्षिणेची सुभेदारी मिळाली तेव्हा त्याने शहराला त्याची राजधानी केल व औरंगाबाद हे नाव दिले.



पुर्वापार कला व सांस्कृतिक वारसा लाभलेल हे शहर विविध राजवटीच्या अंमलाखाली होत. मौर्य, सातवाहन, राष्ट्रकुट, यादव, चालुक्य, निझाम, मुघल, यांनी आपले अधिपत्य या शहरावर गाजवले होते. ते शहराबाहेरच्या औरंगाबाद लेण्या दुसऱ्या व सहाव्या शतकाची साक्ष देतात. शहरातून एक तटबंदी नजरेस पडते. ठिकठिकाणी तीचे अवशेष दिसतात. या तटबंदीचे दिल्ली गेट, भडकल गेट, मकाई गेट, रोशनगेट इ. 9 गेट आहेत. या शहरातील प्रभागांना पुर्वीची पुरे अशी नावे आहेत व ती प्रसिद्ध आहेत.

औरंगाबाद जिल्हा गोदावरीच्या खोऱ्यात वसलेला आहे. औरंगाबाद जिल्ह्याचे तापमान उष्ण आहे. जून ते सप्टेंबर महिन्यात हवामान पावसाळी असते. हवेत गारवा असते. तर ऑक्टोबर ते फेब्रुवारीत हवा थंड व कोरडी असते. नोव्हेंबर ते जानेवारीत थंडीची लाटही येते. पर्यटकांच्या दृष्टीने हा काळ सर्वात चांगला आहे. याच काळात औरंगाबाद वेरुळ महोत्सव आयोजित केला जातो. औरंगाबाद शहरात विमानतळ, रेल्वेस्टेशन, बसस्थानक, टुरीस्ट सेंटर, पर्यटक कार्यालये इ. सुविधा पर्यटकासाठी आहेत. जिल्ह्याचा प्रमुख उद्योग हा जरी शेती असला तरी औद्योगिक शहर म्हणून शहराची जडणघडण झपाट्याने होत आहे. या बरोबरच शैक्षणिक विकास देखील झपाट्याने होत आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ हे शिक्षणाचे प्रमुख अंग आहे. विद्यापीठाने देखील ऐतिहासिक वस्तुंच्या जतनासाठी इतिहास वस्तुसंग्रहालय निर्माण केलेल असून तेथे अनेक ऐतिहासिक पुराणवस्तुंचे जतन करून ठेवलेल आहे.

अजिंठा लेणी ही मानवी बुद्धि कौशल्याने पाषाणाला पाडलेल एक शाश्वत स्वप्न आहे. बौद्ध संस्कृतीचा व्यापक परिपक्व असलेल्या लेणीच्या जन्माची कथा लेणीसारखीच विलक्षण आहे. दगडाला भाषा नसते, परंतु मानवी बुद्धि कौशल्याचा वापर करून दगडाला बोलके केले. त्यांना भाषा अविष्कार दिला आहे. पाषाणालाही मानवी बुद्धिकौशल्याने स्वप्न पाडलेल आहे.

परकीय आक्रमणाच्या हल्ल्यामुळे भारतातील ऐतिहासिक स्थळांचा होणारा नाश लक्षात घेऊन इ.स. च्या दुसऱ्या व सातव्या शतकात अजिंठा लेण्या लुप्त केल्या गेल्या. एक हजार वर्षांहून अधिक काळ अजानात दडून राहिलेली ही अजिंठा लेणी इ.स.1829 साली शिकारीस निघालेल्या जॉन स्मिथ या लष्करी अधिकाऱ्याच्या नजरेस पडली आणि पुन्हा प्रकाशात आली. वाघरा नदीच्या नालाकार घाळीमध्ये ही लेणी खडकात कोरलेली आहे. बौद्ध धर्माच्या महायान व हिनयान कालखंडामध्ये या लेण्याचे काम केलेल आहे.

बौद्ध स्थापत्य शैलीतील दोन विशिष्ट वस्तुप्रकार अजिंठा लेण्यामध्ये आहेत. हिनयान कालखंडामध्ये चैत्यगृहामध्ये स्तूप आहेत. महायान कालखंडातील चैत्यगृहाची रचना वेगळी आहे.



OUR HERITAGE

ISSN : 0474-9030 Vol-68, Special Issue-11

Impact Factor (2020) - 6.8



या काळातील विहार चौकोनाकृती असून त्यात भगवान बुद्धाची मूर्ती असलेली प्राचीन मंदिरे आहेत. या लेणीचा भौगोलिक नकाशा U आकाराच्या अक्षराप्रमाणे आहे. या गुफात बौद्ध वास्तुकला, शिल्पकला, चित्रकला आहेत. या गुंफा बुद्धाला समर्पित असून त्यात पूजा कक्ष, चैत्य कक्ष, विहार आहेत. जेथे बौद्ध मठवासी ध्यान, उपदेश, मार्गदर्शन करीत आहेत.

वेधक चित्र:

अजिंठा लेण्यातील चित्र-आपल्या अदभुत सौंदर्य, विलक्षण बोलकेपणा, अप्रतिम रंगसंगती, संयमित आकृतिबंध आणि ओघवत्या रेखाटनाने पर्यटकास मंत्रमुग्ध करतात. उच्च दर्जाची कलात्मकता आणि सुडौल शरीर रचना यामुळे लक्ष वेधून घेणाऱ्या चित्रामध्ये लाल, निळा, पिवळा आणि काजळी काळा हे रंग वापरले आहेत. अजिंठ्याच्या चित्रांमधून विभिन्न शैली निदर्शनास येतात. कमीत कमी रंग वापरून आणि अद्वितीय तंत्राचा अवलंब करून काढलेली हिनयान काळातील चित्र प्रामुख्याने आडव्या आकारात आणि सरळ रेषेत काढली आहेत. याउलट संपूर्ण भिती व्यापणारी महायान काळातील चित्र कुशल रेखाटनामुळे अधिक जिवंत आणि वैविध्यपूर्ण वाटतात. लेण्यातील भिंतीवर काढलेल्या चित्रांचे विषय धार्मिक आहेत. ते भगवान बुद्धाशी निगडित आहेत. ही चित्र बोधीसत्त्वाच्या रूपात अवतीर्ण झालेल्या भगवान बुद्धाच्या पुनर्जन्मातील नानाविध घटनांवर आधारित आहेत. या चित्रांमध्ये मानवी जन्मापासून मृत्यूपर्यंतचे मानवी जीवनचक्र आश्रम, गाव, शहर, दरबार तसेच राजमहालातील तत्कालीन लकजीवनाचे प्रतिबिंब आहे. लेण्याच्या छतावर रेखाटलेली चित्र अलंकारीक स्वरूपाची आहेत. उडत्या स्वर्गीय आकृत्या, मानवी आकार, पाने, फुल, फळे तसेच विविध प्राणी आणि पक्षी या साऱ्यांना कलात्मकतेने गुंफण्याच्या असंख्य नयनरम्य रचना येथे आहेत.

सचेतन शिल्पे:

हिनयान कालखंडातील शिल्पापेक्षा महायान कालखंडातील शिल्पे कोरीव कामाने सजवलेली आहेत. सुडौल संयमित आकृतिबंध आणि मोहक सौंदर्य यामुळे ही शिल्पे उल्लेखनीय आहेत. शिल्पाचे विशय प्रामुख्याने भगवान बुद्धाशी संबंधित आहेत. चैत्यगृहामध्ये ध्यान आणि प्रवचन-मुद्रेतील बुद्धाच्या प्रचंड मूर्ती आहेत. त्यांचे विलक्षण सुबक आकार आणि चेहऱ्यावरील सौम्य मृदुभाव मनामध्ये अचंबा आणि भक्तीभाव जागृत करतात.

अजिंठा लेण्या या 56 मीटर उंचीवर असून एकंदरीत 550 मीटर नालीच्या आकारात पसरलेल्या आहेत. लेण्यासाठी चार शतके उत्खनन केल्यानंतर अपेक्षित उद्दिष्ट पूर्णत्वास आले. हे उत्खननाचे काम वाकाटक राजवटीच्या अधिपत्याखाली झाले. पाचव्या शतकातील शेवटचे अर्धशतक आणि सहाव्या शतकातील पहिले अर्धशतक हा काळ शिल्पकलेचा आणि चित्रकलेचा सुसंगम मिलाप आणि भरभराटीचा काळ म्हणून ओळखला जातो. अजिंठा येथे एकूण 30 लेण्या



OUR HERITAGE

ISSN : 0474-9030 Vol-68, Special Issue-11

Impact Factor (2020) - 6.8



आहेत. 5 चैत्य मंदिरे आणि उर्वरीत जनसभा आणि निवासासाठी प्रसिद्ध आहेत. अजिंठा डोंगरातील कोरीव शिल्पामुळे मराठवाडा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने जगप्रसिद्ध आहे. ही शिल्पे म्हणजे भारतीय संस्कृतीचा जगातील अमूल्य ठेवा आहे. तसेच व्यवस्थापनाचे उत्कृष्ट उदाहरणही आहे. युनेस्कोने या शिल्पाना जागतिक वारसा स्थळ म्हणून घोषित केलं आहे.

संदर्भग्रंथ:

- 1) देशपांडे ब्रह्मानंद (2004), अजिंठा मार्गदर्शन, साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद.
- 2) टाकळकर सारंग (2003), वेरुळ -अजिंठा औरंगाबाद पर्यटन, परम प्रकाशन, औरंगाबाद.
- 3) हणमते एस. आर. (2005), वेरुळ आणि औरंगाबाद लेणी, भारतीय बौद्ध ज्ञानालंकार शिक्षण संस्था, मुळावा.
- 4) पर्यटन विभाग भारत सरकार (2005), अजिंथा वेरुळ पाषाण गिऱे.
- 5) टुरिस्ट पब्लिकेशन दिल्ली (2005), अजिंठा वेरुळ.
- 6) दै. लोकसत्ता, 24 जून 2006 मराठवाडा वृत्तांत.
- 7) दै. लोकसत्ता, 08 जुलै 2006
- 8) Dulari Gupte Queresi (1999), Tourisam Potential in Aurangabad, Bhartiya Kala Prakashan, Delhi
- 9) MTDC & Directorate Cultural affairs Govt. of Maharashtra (2005) SOVENER, Ellora Aurangabad Festival, 2005

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.



RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal

ISSN- 2348-7143

Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452, (GIF) - 0.676 Special Issue - 93
Research Need of the Hour (संशोधन काळाची गरज)

June 2019

UGC Approved
No. 40705

Impact Factor - 6.261

ISSN - 2348-7143

INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S

RESEARCH JOURNEY

Multidisciplinary International E-research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

10th June 2019 Special Issue - 93

Research need of the Hour

संशोधन काळाची गरज

Chief Editor -

Dr. Dhanraj T. Dhangar,

Assist. Prof. (Marathi)

MGV'S Arts & Commerce College,

Yeola, Dist - Nashik [M.S.] INDIA

Executive Editor of This Issue

Dr. Ulgade Laxman Kashinath

Asst. Prof. and Head, (PG Teacher)

Dept. of Public Administration

Shri Havagiswami College, Udgir, Dist. Latur

Co-Editor

Mr. Madhav Kashinath Ulgade

Signature

x



18	Study on the preparation of a training of the representative Men's Basketball team of participation in 'B' zone intercollegiate Tournaments in S.R.T.M.U Nanded. Dr.Bhadke D.D.	
19	भारतीय लोकतंत्र और भ्रष्टाचार डॉ.शरद कुलकर्णी, सचिन शेवतेकर	65
20	भाषा अनुसंधान और मानव समाज प्रा.विजयसिंह ठाकुर	70
21	सामाजिक दास्य मुक्ति के आंदोलन : डॉ.आंबेडकर प्रो.डॉ.एम.डी.इंगोले	76
22	राजशा का पालन करने के लिए समर्पित गांधरि डॉ. पुष्पा गोविंदराव गायकवाड	79
23	सामाजिक संशोधन पद्धतीची उपयुक्तता डॉ. एस.एन. आकुलवार	82
24	समस्यासूत्रण व संशोधन प्रक्रिया : एक अभ्यास डॉ. विजय पांडुरंगराव कुलकर्णी	85
25	तापमान वाढीचे दाहक वास्तव डॉ. देशमुख एम.व्ही.	89
26	फ.मुं. शिंदे यांच्या कवितेतील समाजवास्तव डॉ. मथु सावंत	91
27	सामाजिक संशोधनात संगणकाचे महत्व प्रा.डॉ. बब्रुवान केरवाजी मोरे	94
28	भारतातील दलितांच्या आर्थिक चळवळीचे आंबेडकरांच्या दृष्टीकोनातील विश्लेषण प्रा. डॉ.गौतम कांबळे	97
29	शास्त्रीय संगीतात घराणेदार परंपरेची आवश्यकता प्रा.डॉ.दिपाली पांडे	103
30	जलयुक्त शिवार अभियान महाराष्ट्र, मराठवाडा व बीड जिल्ह्याची सद्यस्थिती प्रा. शिंदे नारायण भर्तरीनाथ	105
31	कृषी संशोधन काळाची गरज प्रा.डॉ.जे.बी.कांगणे	109
32	सामाजिक संशोधनात व्यष्टी अध्ययनाचे महत्त्व डॉ.लता कमलापुरे	112
33	महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळ लोकउपयोगी विविध योजना कैलास गो. खेडूळकर, डॉ.व्यंकट विळेगांवे	116
34	मानवी हक्क आणि भारताची राज्यघटना : एक शोध डॉ.दयानंद माधवराव गुडेवार	119

143-
wed
15



भारतीय लोकतंत्र और भ्रष्टाचार

संशोधक : सचिन शेवतेकर

मार्गदर्शक : डॉ. शरद कुलकर्णी
विभागप्रमुख, राज्यशास्त्र, नुतन महाविद्यालय सेलू

भ्रष्टाचार अर्थ :- (Meaning)

भ्रष्टाचार अर्थात् भ्रष्ट आचरण, शिष्टाचाररहित या नैतिकताविहित व्यवहार का परिचायक है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 161 में भ्रष्टाचार को इस प्रकार परिभाषित किया है "जो व्यक्ति शासकीय होते हुए अपने या अन्य व्यक्ति के लिए विधिक परिदृष्टिक से अधिक कोई पुरस् लेता है" या स्वीकार करता है या किसी कार्य को करने या न करने के लिए उपहार स्वरूप या आपने शासकीय कार्य करने में किसी व्यक्ति के प्रती पक्षपात या उपेक्षा या किसी व्यक्ति की कोई सेवा या कुसेवा का प्रयास केंद्र या राज्य सरकार, संसद या विधानमंडल या किसी लोकसेवक के संदर्भ में करता है। तो उसे भ्रष्टाचार कहते हैं।¹ इसी प्रकार संधानाम समिती ने कहा था "सरकारी कर्मचारी द्वारा कार्य निस्सादन के दौरान ऐसा कृत्य जो किसी लाभ की दृष्टी से किया जाए अथवा जान बुझकर किया न जाए भ्रष्टाचार की श्रेणी में सत्ता है।"²

भ्रष्टाचार के कारण (Causes of Crruption) :-³

- 1. राजनीतिक प्रक्षय
- 2. विज्ञान तथा भौतिकतावादका प्रसार
- 3. नैतिक मूल्यों का पतन
- 4. देशभक्ती की कमी
- 5. औद्योगिकी करण तथा नागरीकत्व
- 6. वेतनमानो में विसंगतीया
- 7. नियंत्रण प्रणाली में दोष
- 8. नौकरशाही की धीमी एवं जटील कार्यप्रणाली

भारत में राजनैतिक एवं नौकरशाही का भ्रष्टाचार बहुत ही व्यापक है। किन्तु इसके अलावा न्यायपालिका, मिडिया, सना, पुलिस आदि में भी अकल्पनीय भ्रष्टाचार व्याप्त है। वर्ष 2008 में दी गई ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट ने बताया है कि भारत में लगभग 20 करोड की रकम अलग-अलग लोकसेवको को दी जाती है।⁴ उन्ही का यह निष्कर्ष है कि किसी भी शहर में नगर निगम में पैसा बिना बगैर कोई मकान बनाने की अनुमति नहीं मिलती। इसी प्रकार सामान्य व्यक्ति भी यह मानता चलता है कि किसी भी सरकारी महकमे में पैसा दिए बगैर गाडी नहीं चलती।

भ्रष्टाचार पिछडेपन का घोटक है। भ्रष्टाचार का बोलबाला यह दर्शाता है कि जिसे जो करना है वह कुछ दे-दिवाकर अपना काम चला लेता है, और लोगों को कानों-कान खबर नहीं होती। होती भी है तो हर व्यक्ति खरीदे जाने के लिए तैयार है। गवाहों का उलट जाना, जांचों का अनंतकाल तक चलते रहना, सत्य को सामने न आने देना, ये सब एक पिछडे समाज के अति दुखदायी पहलू हैं। किसी को निर्णय लेने का अधिकार मिलता है तो वह एक या दूसरे पक्ष में निर्णय ले सकता है। यह उसका विवेकाधिकार है और एक सफल लोकतंत्र का लक्षण भी है। परंतु जब यह विवेकाधिकार वस्तुपरक न होकर दूसरे कारणों के आधार पर इस्तेमाल किया जाता है तब यह भ्रष्टाचार की श्रेणी में आ जाता है अथवा इसे करने वाला व्यक्ति भ्रष्ट कहलाता है। किसी निर्णय को जब कोई शासकीय अधिकारी धन पर अथवा अन्य किसी लालच के कारण करता है तो यह भ्रष्टाचार कहलाता है। भ्रष्टाचार के संबंध में हाल ही के वर्षों में जागरुकता बहुत बढ़ी है। भ्रष्टाचार, विरोध अधिनियम 1988, सिटीजन चार्टर, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, आदि।

भ्रष्टाचार की ऐतिहासिक पार्श्वभूमी :-

अंग्रेजों ने भारत के राजा महाराजाओं को भ्रष्ट करके भारत को गुलाम बनाया। उसके बाद उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया और भ्रष्टाचार को गुलाम बनाये रखने के प्रभावी हथियार की तरह इस्तेमाल किया। देश में भ्रष्टाचार भले ही वर्तमान में सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है, लेकिन भ्रष्टाचार ब्रिटिश शासनकाल में ही होने लगा था जो हमारे राजनेताओं को विरासत में दे गए थे।

भारत के प्रमुख अधिक घोटाले :-⁵

1. जी सोब्रूम घोटाला - 1 लाख 67 हजार करोड रुपए
2. कामन्वेल्थ गेम्स घोटाला - 70 हजार करोड रुपए
3. अनाज घोटाला - 2 लाख करोड रुपए (अनुमानित)
4. धोमस घोटाला - 64 करोड रुपए
5. शूरीया घोटाला - 133 करोड रुपए

21/46 401 701 571021 19/12/2019 65



6. चारा घोटाला - 950 करोड़ रुपए
7. शेयर बाजार घोटाला - 4000 करोड़ रुपए
8. सत्यम घोटाला - 7000 करोड़ रुपए
9. स्टैंप पेपर घोटाला - 43 हजार करोड़ रुपए
10. ताज हेरिटेज कॉरिडोर घोटाला 2002.
11. आदर्श घोटाला 2003.

न्यायपालिका में भ्रष्टाचार :-

अंग्रेजी काल से ही न्यायालय शोषण और भ्रष्टाचार के अड़े बन गये थे। उसी समय यह धारणा बन गयी थी कि जो अदालत के चक्कर में पड़ा, वह बर्बाद हो जाता है। भारतीय न्यायपालिका में भ्रष्टाचार अब आम बात हो गयी है। सर्वोच्च न्यायालय के कई न्यायाधीशों पर महाभियोग की कार्यवाही हो चुकी है। न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार में - भाई भतीजावाद, बेहद धीमी और बहुत लंबी न्याय प्रक्रिया, बहुत ही ज्यादा महंगा अदालती खर्च, न्यायालयों की भारी कमी, और पारदर्शिता की कमी, कर्मचारियों का भ्रष्ट आचरण आदि जैसे कारणों को प्रमुख भूमिका है।

वैसे विगत छह दशकों में राज्य के तीन अंगों के परफॉर्मंस पर नजर डाली जाए तो न्यायपालिका को ही बेहतर माना जाएगा। अनेक अवसरों पर उसने पूरी निष्ठा और मुस्तैदी से विधायिका और कार्यपालिका द्वारा संविधान उल्लंघन को रोका है, लेकिन अदालतों में पोंडिंग मुकदमों की तीन करोड़ की संख्या का पिरामिड देशवासियों के लिए चिंता और भय उत्पन्न कर रहा है। अदालती फैसलों में पांच साल लगाना तो सामान्य-सी बात है, लेकिन बीस-तीस साल में भी निपटारा न हो पाना आम लोगों के लिए त्रासदी से कम नहीं है। न्याय का मौलिक सिद्धांत है कि विलंब का मतलब न्याय को नकारना होता है। देश की अदालतों में जब करोड़ों मामलों में न्याय नकारा जा रहा हो तो आम आदमी को न्याय सुलभ हो पाना आकाश के तारे तोड़ना जैसा होगा। वस्तुतः अदालतों में त्वरित निर्णय न हो पाने के लिए यह कार्यप्रणाली ज्यादा दोषी है जो अंग्रेजी शासन की देन है और उसमें व्यापक परिवर्तन नहीं किया गया है। कई मामलों में तो वादी या प्रतिवादी ही प्रपक्ष करते हैं कि फैसले की नौबत ही नहीं आ पाए। समाचार-पत्रों और टीवी के वायजूद नोटिस तामीली के लिए उनका सहारा नहीं लिया जाता और नोटिस तामील होने में वक्त जाया होता रहता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानूनों में सुधार करके जमानत और अपीलों की संख्या में कटौती की जाए और पेशियां बढ़ाने पर बंदिश लगाई जाए। हालांकि देश में भ्रष्टाचार इतना सर्वन्यायी हुआ है कि कोई भी कोना उसके संधंध से बचा नहीं है, लेकिन फिर भी उच्चस्तरीय न्यायपालिका कुछ अपवाद छोड़कर निस्तवन साफ-सुथरी है। 2007 की ट्रांसपैरेंसी इंटरनेशनल की रपट अनुसार नीचे स्तर की अदालतों में लगभग 2630 करोड़ रुपया बतौर रिश्वत दिया गया। अब तो पश्चिम बंगाल के न्यायमूर्ति सेन और कर्नाटक के दिनकरन जैसे मामलों प्रकाश में आने से न्यायपालिका की ध्वल छवि पर कालिख के छींटे पड़े हैं। मुकदमों के निपटारे में विलंब का एक कारण भ्रष्टाचार भी है। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के जजों को हटाने की सांविधानिक प्रक्रिया इतनी जटिल कि कारवाई की जाना बहुत कठिन होता है। न्यायिक आयोग के गठन का मसला सरकारी झूले में वर्षों से झू रहा है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा बच्चों के शिक्षा अधिकार, पर्यावरण की सुरक्षा, चिकित्सा, भ्रष्टाचार, राजनेताओं के उपराधीकरण, मायावती का पुतला प्रेम जैसे अनेक मामलों में दिए गए नुमाया फैसले, रिश्वतखोरी के चंद मामलों और विलंबीकरण के असंख्य मामलों की धुंध में छुपने अधिकार लागू न होने का दावा करते हैं और दिल्ली हाईकोर्ट उनकी राय से असहमत होकर पिटीशन खारिज कर देता है। यह सुप्रीम कोर्ट है, जिसने आंध्रप्रदेश सरकार द्वारा मुसलमानों को शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण पर रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश उन पर सूचना के विधि मंत्री हों या अन्य और लंबित मुकदमों के अंबार को देखकर चिंता में डूब जाते हैं, लेकिन किसी को हल नजर नहीं आता है। सुप्रीम कोर्ट अदालतों के लिए 23000 जजों की आवश्यकता है। अभी की स्थिति यह है कि उच्च न्यायालयों में ही 280 पद रिक्त पड़े हैं, जजों की कार्य कुशलता के संबंध में हाल में सेवानिवृत्ता हुए उड़ीसा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बिलाई नाज ने कहा कि 'मजिस्ट्रेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक के लिए कई जज फौजदारी मामले डील करने में अक्षम हैं। 1998 के फौजदारी अपीलें बंबई उच्च न्यायालय के इसलिए पोंडिंग पड़ी हैं, क्योंकि कोई जज प्रकरण का अध्ययन करने में दिलचस्पी नहीं लेता। वैसे भी पूरी सुविधाएं दिए जाने के बावजूद न्यायपालिका में सार्वजनिक अवकाश भी सर्वाधिक होते हैं। पदों की कमी और रिक्त पदों को भरे जाने में विलंब ऐसी समस्याएं हैं, जिन्हें निराकरण जल्दी हो। हकीकत तो यह है कि वर्ष पूर्व मुंबई में हुए आतंकी कांड के प्रकरणों का निपटारा आज तक पूरा नहीं हुआ है, जिनमें ब्रिटेन में हुई ऐसी घटना के प्रकरण एक-दो साल में निपटारे जा चुके हैं।

सरकार कई वर्षों से न्यायपालिका में सुधार के लिए कानून लाने की बात कर रही है। अब चार मेट्रो नगरों में सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के लिए लाजिमी है। मुकदमों का अंबार निपटाने और सुधार करने के लिए केवल कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका ही नहीं देश के अप्रणी न्यायविदों, समाज शास्त्रियों और आम लोगों को विश्वास में लिए जाने की आवश्यकता है।

सेना में भ्रष्टाचार :- विश्व की कुछ, चुनिंदा सबसे तेज, सबसे चुस्त, बहादुर और देश के प्रति विश्वसनीय सेनाओं में अग्रणी सेना वालों में से एक है। देश का सामरिक इतिहास इस बात का गवाह है कि भारतीय-सेना ने युद्धों में वो लड़ाई सिर्फ अपने जज्बे और बलिदान करण जीत ली जो दुश्मन बड़े आधुनिक अस्त्र-शस्त्र से भी नहीं जीत पाए।

Handwritten signature

लेखि
 यानों के च
 कहीं न का
 | सबसे दुर
 ही रहा है।
 तक में बड़
 दर्शा रही है
 आपूर्ति, सै
 इसमें उनव
 आंतरिक र
 ऐसा नहीं है
 गुंजाइश ख
 संचार माए
 2 उ
 भ्रष्टाचार र
 भीड़िया ने
 वाले दबी
 भीड़िया की
 हाल
 मासिक ता
 जुले आम
 गला फाइ
 लोव
 नाये, यक
 में आते हैं
 वहीं
 में 15 सो
 निकाल दे
 यह चिंतनी
 सुवर की
 पिता ही
 छोटे
 एक हद त
 कीर ने प
 भ्रष्ट काम
 मान
 भ्रष्ट है कि
 भ्रष्ट विर
 के क्रिया
 सकेने है
 जो किनी
 सुने प
 इ
 लक्ष्य को
 लक्ष्य को
 20 रुपए



लेकिन पिछले कुछ वर्षों में जिस तरह से, बड़े शस्त्र आयात निर्यात में, आयुध कारागारों में संदेहास्पद अगिनकांडों की शृंखला, पुराने यानों के चालन से उठे सवाल और जाने ऐसी कितनी ही घटनाएं, दुर्घटनाएं और अपराधिक कृत्य सेना ने अपने नाम लिखवाए हैं और अब भी कहीं न कहीं ये सिलसिला जारी है वो इस बात का इशारा कर रहा है कि अब स्थिति पहले जैसी नहीं है। कहीं कुछ बहुत ही गंभीर चल रहा है। सबसे दुखद और अफसोसजनक बात ये है कि अब तक सेना से संबंधित अधिकांश भ्रष्टाचार और अपराध सेना के उच्चाधिकारियों के नाम ही रहा है। आज सेना के अधिकारियों को तमाम सुख सुविधाएं मौजूद होने के बावजूद भी, सेना में भरती, आयुध, वर्दी एवं राशन की सप्लाई तक में बड़ी घपले और घोटालेबाजी के सबूत, पुरस्कार और प्रोत्साहन के लिए फर्जी मुठभेड़ों की सामने आई घटनाएं आदि यही बता और दर्शा रही हैं कि भारतीय सेना में भी अब वो लोग घुस चुके हैं जिन्होंने वर्दी देश की सुरक्षा के लिए नहीं पहनी है। आज सेना में हथियार आपूर्ति, सैन्य सामग्री आपूर्ति, खाद्य राशन पदार्थों की आपूर्ति और इंधन आपूर्ति आदि सब में बहुत सारे घपले घोटाले किए जा रहे हैं और इसमें उनका भरपूर साथ दे रहे हैं सैन्य एवं रक्षा विभागों से जुड़े हुए सारे भ्रष्ट लोग। इन सबके छुपे ढके रहने का एक बड़ा कारण है देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा होने के कारण इन सूचनाओं का अति संवेदनशील होना और इसलिए ये सूचनाएं पारदर्शी नहीं हो पाती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है की नहीं जा सकती। यदि तमाम ठेकों और शस्त्र वाणिज्य डीलरों को जनसाधारण के लिए रख दिया जाए तो बहुत कुछ छुपाने की गुंजाईश खत्म हो जाएगी।

संचार माध्यमों (मीडिया) का भ्रष्टाचार :-

2 जी स्पेक्ट्रम घोटाला मामला ने देश में भ्रष्टाचार को लेकर एक नई इबादत लिख दी। इस पूरे मामले में जहां राजनीतिक माहौल भ्रष्टाचार की गिरफ्त में दिखा वहीं लोकतंत्र का प्रहरी मीडिया भी राजा के भ्रष्टाचार में फंसा दिखा। राजा व मीडिया के भ्रष्टाचार के खेल को मीडिया ने ही सामने लाया। हालांकि यह पहला मौका नहीं है कि मीडिया में घुसते भ्रष्टाचार पर सवाल उठा हो। मीडिया को मिशन समझने वाले दबी जुवां से स्वीकारते हैं कि नीरा राडिया प्रकरण ने मीडिया के अंदर के उच्च स्तरीय कथित भ्रष्टाचार को सामने ला दिया है और मीडिया की पोल खोल दी है।

हालांकि, अक्सर सवाल उठते रहे हैं, लेकिन छोटे स्तर पर, छोटे बड़े शहरों, जिलों एवं कस्बों में मीडिया की चाकरी बिना किसी अच्छे मासिक तनख्वाह पर करने वाले पत्रकारों पर हमेशा से पैसे लेकर खबर छापने या फिर खबर के नाम पर दलाली के आरोप लगते रहते हैं। खुले आम कहा जाता है कि पत्रकारों को खिलाओ-पिलाओ कुछ धनाओं और खबर छपवाओ। मीडिया की गोष्ठियों में, मीडिया के दिग्गज गला फाड़ कर, मीडिया में दलाली करने वाले या खबर के नाम पर पैसा उगाही करने वाले पत्रकारों पर हल्ला बोलते रहते।

लोकतंत्र पर नजर रखने वाला मीडिया भ्रष्टाचार के जबड़े में है। मीडिया के अंदर भ्रष्टाचार के घुसपैठ पर भले ही आज हो हल्ला हे जाये, थक कोई नयी बात नहीं है। पहले निचले स्तर पर नजर डालना होगा। जिलों / कस्बों में दिन-रात कार्य करने वाले पत्रकार इसकी चपेट में आते हैं, लेकिन सभी नहीं। अभी भी ऐसे पत्रकार हैं, जो संवाददाता सम्मेलनों में खाना क्या, गिफ्ट के लिए हंगामा मचाते नजर आते हैं।

वहीं देखें, तो छोटे स्तर पर पत्रकारों के भ्रष्ट होने के पीछे सबसे बड़ा मुद्दा आर्थिक शोषण का आता है। छोटे और बड़े मीडिया हाउसों में 15 सौ रुपये के मासिक पर पत्रकारों से 10 से 12 घंटे काम लिया जाता है। उपर से प्रबंधन की मर्जी, जब जी चाहे नौकरी पर रखे या निकाल दे। भुगतान दिहाड़ी मजदूरों की तरह है। वेतन के मामले में कलम के सिपाहियों का हाल, सरकारी आदेशपालों से भी बुरा है। ऐसे में यह चिंतनीय विषय है कि एक जिले, कस्बा या ब्लॉक का पत्रकार, अपनी जिंदगी पानी और हवा पी कर तो नहीं गुजारेगा? लाजमी है कि खबर की दलाली करेगा? वहीं पर कई छोटे- मंजोले मीडिया हाउसों में कार्यरत पत्रकारों को तो कभी निश्चित तारीख पर तनख्वाह तक नहीं मिलती है।

छोटे स्तर पर कथित भ्रष्ट मीडिया को तो स्वीकारने के पीछे, पत्रकारों का आर्थिक कारण, सबसे बड़ा कारण समझ में आता है, जिसे एक हद तक मजदूरी का नाम दिया जा सकता है। लेकिन दिन के उजाले में पत्रकारिता के स्तंभ माने जाने वाले तथाकथित पत्रकार, रात के अंधेर में दलाली का जो गुल खिलाले हैं, उससे पत्रकारिता शर्मसार हुई है।

भ्रष्ट कमाई स्विस बैंक में ?

भारतीय गरीब है लेकिन भारत देश कभी गरीब नहीं रहा - ये कहना है स्विस बैंक के डाइरेक्टर का स्विस बैंक के डाइरेक्टर ने यही भी कहा है कि भारत का लगभग 280 लाख करोड़ रुपये उनके स्विस बैंक में जमा है ये रकम इतनी है कि भारत का आने वाले 30 सालों का बजट बिना टेक्स के बनाया जा सकता है। या यूँ कहें कि 60 करोड़ रोजगार के अवसर दिए जा सकते हैं। या यूँ भी कह सकते हैं कि भारत के किसी भी गाँव से दिल्ली तक 4 लेन रोड बनाया जा सकता है। ऐसा भी कह सकते हैं कि 500 से ज्यादा सामाजिक प्रोजेक्ट पूर्ण किये जा सकते हैं। ये रकम इतनी ज्यादा है कि अगर हर भारतीय को 2000 रुपये हर महीने भी दिए जाये तो 60 साल तक खत्म ना हो। यानी भारत को किसी वर्ल्ड बैंक से लोन लेने कि कोई जरूरत नहीं है। जरा सोचिये हमारे भ्रष्ट राजनेताओं और नोकरशाहों ने कैसे देश को लूटा है और ये लूट का सिलसिला अभी तक 2012 तक जारी है।

इस सिलसिले को अब रोकना बहुत ज्यादा जरूरी हो गया है। अग्रेजो ने हमारे भारत पर करीब 200 सालों तक राज करके करीब 1 लाख करोड़ रुपये लूटा। मगर आजादी के केवल 64 सालों में हमारे भ्रष्टाचार ने 280 लाख करोड़ लूटा है। एक तरफ 200 साल में 1 लाख करोड़ है और दूसरी तरफ केवल 64 सालों में 280 लाख करोड़ है। यानि हर साल लगभग 4.37 लाख करोड़, या हर महीने करीब 36 हजार करोड़ भारतीय मुद्रा स्विस बैंक में इन भ्रष्ट लोगों द्वारा जमा करवाई गई है।

Signature



ई बैंक के लोन की कोई दरकार नहीं है। सोचो की कितना पैसा हमारे भ्रष्ट राजनेतों और उच्च अधिकारियों ने ब्लांक

किये जाय और भ्रष्ट तथा अपराधी तत्वों को चुनाव लड़ने पर पावंदी हो।
 तबक (मंत्री, सांसद, विधायक, ब्यूरोक्रेट, अधिकारी, कर्मचारी) अपनी संपत्ति की हर वर्ष घोषणा करे
 गर और विवेकाधिकार कम किये जाय या हटा दिए जाय।
 तब एक लाख से अधिक का नगद (कैश) मिले तो वह अपराध की श्रेणी में आये, भले ही वह बंध कमाई से प्राप्त किया गया

ने बैंक खाते से एक बार में दस हजार तथा एक माह में पचास हजार से अधिक न निकाल पाए। अधिकाधिक लेना-देन
 एक रूप में की जाय।

कर्मचारियों को वेतन आदि नकद न दिया जाय बल्कि यह पैसा उनके बैंक खाते में डाला दिया जाय।
 1000, 500 आदि) का प्रचालन बंद किया जाय।

कर करनेवाले अधिकारी एवं पदाधिकारियों को कड़क सजा होनी चाहिए ताककी व भ्रष्टाचार करने के लिए करत जाए.
 गर विरोधी यंत्रणा मे अधिकाधिक बाढ करनी चाहिए जैसे की लोकपाल, लोकायुक्त, विशेष जांच आयोग इ.

शक्ति बनने मे भ्रष्टाचार बाधा :-

शक्ति के महाशक्ति बनने की सम्भावना का आकलन अमरीका एवं चीन की तुलना से किया जा सकता है। महाशक्ति बनने की पहली
 तकनीकी नेतृत्व है। अठारहवीं सदी में इंग्लैण्ड ने भाप इंजन से चलने वाले जहाज बनाये और विश्व के हर कोने में अपना आधिपत्य
 किया। बीसवीं सदी में अमरीका ने परमाणु बम से जापान को और पेट्रियट मिसाइल से इराक को परास्त किया। यद्यपि अमरीका
 तिलो नेतृत्व जारी है परन्तु अब धीरे-धीरे यह कमजोर पड़ने लगा है। वहां नई तकनीकी का अविष्कार अब कम ही हो रहा है। भारत
 ध्यान का काम भारी मात्रा में 'आऊटसोर्स' हो रहा है जिसके कारण तकनीकी क्षेत्र में भारत का पलड़ा भारी हुआ है। तकनीक के मुद्दे

पीछे है। वह देश मुख्यतः दूसरों के द्वारा ईजाद की गयी तकनीकी पर आश्रित है।
 दूसरी कसौटी श्रम के मूल्य की है। महाशक्ति बनने के लिये श्रम का मूल्य कम रहना चाहिये। तब ही देश माल का सस्ता उत्पादन कर
 और दूसरे देशों में उसका माल प्रवेश पाता है। चीन और भारत इस कसौटी पर अव्वल बैठते हैं जबकि अमरीका पिछड़ा रहा है। अमरीका के

गण उद्योग लगभग पूर्णतया अमरीका से गायब हो चुका है। सेवा उद्योग भी भारत की ओर तेजी से रुख कर रहा है। अमरीका के
 न आर्थिक संकट का मुख्य कारण अमरीका में श्रम के मूल्य का ऊंचा होना है।
 तीसरी कसौटी शासन के खुलेपन की है। वह देश आगे बढ़ता है जिसके नागरिक खुले वातावरण में उद्यम से जुड़े नये उपाय क्रियान्वित
 ने के लिए आजाद होते हैं। बंडियों में जकड़े हुये अथवा पुलिस की तीखी नजर के साथे में शोध, व्यापार अथवा अध्ययन कम ही पनपते हैं
 भारत और अमरीका मे यह खुलापन उपलब्ध है। चीन इस कसौटी पर पीछे पड़ जाता है। वहां नागरिक की रचनात्मक ऊर्जा पर कम्युनिस्ट

का नियंत्रण है।
 चौथी कसौटी भ्रष्टाचार की है। सरकार भ्रष्ट हो तो जनता की ऊर्जा भटक जाती है। देश की पुंजी का रिसाव हो जाता है। भ्रष्ट
 अधिकारी और नेता धन को स्विटजरलैण्ड भेज देते हैं। इस कसौटी पर अमरीका आगे है। ट्रान्सपैरेन्सी इंटरनेशनल द्वारा बनाई गयी रैंकिंग में
 डेन्मार्क पहिले स्थान नावें दसवें स्थान अमरीका को 19 वें स्थान पर रखा गया है हंगेरी पचास जबकि चीन को उन्यासीवें तथा भारत का

चौरासीवां स्थान दिया गया है।
 पांचवीं कसौटी असमानता की है। गरीब और अमीर के अन्तर के बढ़ने से समाज में वैमनस्य पैदा होता है। गरीब की ऊर्जा अमीर के
 साथ मिलकर देश के निर्माण में लगने के स्थान पर अमीर के विरोध में लगती है। इस कसौटी पर अमरीका आगे और भारत व चीन पीछे हैं।
 अन्दर ही अन्दर बढ़ेगा जैसे कैंसर बढ़ता है। भारत की स्थिति तुलना में अच्छी है क्योंकि यहां कम से कम समस्या को प्रकट होने का तो

अवसर उपलब्ध है।
 महाशक्ति बनने की इन पांच कसौटियों का समग्र आकलन करें तो वर्तमान में अमरीका की स्थिति क्रमांक एक पर दिखती है।
 तकनीकी नेतृत्व, समाज में खुलेपन, भ्रष्टाचार नियंत्रण और समानता में यह देश आगे है। अमरीका की मुख्य कमजोरी श्रम के मूल्य का
 अधिक होना है। भारत की स्थिति क्रमांक 2 पर दिखती है। तकनीकी क्षेत्र में भारत आगे बढ़ रहा है, श्रम का मूल्य न्यून है और समाज में
 खुलापन है। हमारी समस्यायें भ्रष्टाचार और असमानता की है। चीन की स्थिति कमजोर दिखती है। तकनीकी विकास में वह देश पीछे है।
 समाज घुट रहा है, भ्रष्टाचार चहुंओर व्याप्त है और असमानता बढ़ रही है।
 यद्यपि आज अमरीका भारत से आगे है परन्तु तमाम समस्यायें उस देश में दस्तक दे रही हैं। शोध भारत से 'आऊटसोर्स' हो रहा है।
 भ्रष्टाचार भी शनैः शनैः बढ़ रहा है। 2002 में ट्रान्सपैरेन्सी इंटरनेशनल ने 7.6 अंक दिये थे जो कि 2009 में 7.5 रह गये हैं। अमरीकी
 नागरिकों में असमानता भी बढ़ रही है। तमाम नागरिक अपने घरों से बाहर निकाले जा चुके हैं और सड़क पर कागज के डिब्बों में रहने को
 मजबूर हैं। आर्थिक संकट के गहराने के साथ-साथ वहां समस्याएं और तेजी से बढ़ेगी। इस तुलना में भारत की स्थिति सुधर रही है। तकनीकी

शोध को बढ़ावा देते रहे हैं।
 अधिकारों ने सरकार के विनमनी पर।
 भारत सरकार की मंशा इन
 इन्होंने युक्ति निकाली है कि गरीब
 के लिए भारी भरकम नौकरशाही
 प्रणाली में 40 प्रतिशत माल का
 दूसरे उत्पादक रोजगार छोड़ने पड़
 बने में रोड़ा है।
 उपाय है कि तमाम कल्याण
 वितरित कर दिया जाये। प्रत्येक
 होगा। उन्हें मनरेगा में बैठकर
 योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार
 सरकारी कर्मचारियों की लॉबी व
 द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों में
 भावदाताओं को वितरित कर दे
 यह सच है कि भारत मह
 जाने फालतू के कामों से फुरस
 भारत को महाशक्ति बनने मे
 कलिये एक महाक्रान्ति की ज
 सत के रशिया जैसे महाशक्ति

- संदर्भ :-
- 1) भारतीय दण्ड संहिता (I)
 - 2) श्री. के संथानम समितो
 - 3) सुरेंद्र कटारिया - भारत
 - 4) ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल
 - 5) यंदकांत मिसाळ - मा
 - 6) दैनिक सकाळ 17 अं
 - 7) ट्रांसपैरेन्सी इंटरनेशनल



RESEARCH JOURNEY International Multidisciplinary E-Research Journal
 Impact Factor - (SJIF) - 6.261, (CIF) - 3.452, (GIF) - 0.676 Special Issue - 93
 Research Need of the Hour (संशोधन काजकी गरज)

ISSN-23497143
 June 2019
 UGC Approved
 No. 40705

शोध में भी हम आगे बढ़ रहे हैं जैसा कि नैनो कार के बनाने से संकेत मिलते हैं। भ्रष्टाचार में भी कमी के संकेत मिल रहे हैं। सूचना के अधिकार ने सरकारी मनमानी पर कुछ न कुछ लगाम अवश्य कसी है। परन्तु अभी बहुत आगे जाना है।
 भारत सरकार की मंशा इन समस्याओं को हल करने की है ही नहीं। राजनीतिक पार्टियों का मूल उद्देश्य सत्ता पर काबिज रहना है। इन्होंने युक्ति निकाली है कि गरीब को राहत देने के नाम पर अपने समर्थकों की टोली खड़ी कर लो। कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए भारी भरकम नौकरशाही स्थापित की जा रही है। सरकारी विद्यालयों एवं अस्पतालों का बेहाल सर्वविधित है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में 40 प्रतिशत माल का रिसाव हो रहा है। मनरेगा के माफेत निकम्मों की टोली खड़ी की जा रही है। 100 रुपये पाने के लिये उन्हें दूसरे उत्पादक रोजगार छोड़ने पड़ रहे हैं। अतः भ्रष्टाचार और अस्मानता की समस्याओं को रोकने में हम असफल हैं। यही हमारी महाशक्ति बनने में रोड़ा है।

उपाय है कि तमाम कल्याणकारी योजनाओं को समाप्त करके बची हुयी रकम को प्रत्येक मतदाता को सीधे रिजर्व बैंक के माध्यम से वितरित कर दिया जाये। प्रत्येक परिवार का कोई 2000 रुपये प्रति माह मिल जायेंगे जो उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति को पर्याप्त होगा। उन्हें मनरेगा में बैठकर फर्जी कार्य का ढोंग नहीं रचना होगा। वे रोजगार करने और धन कमाने को निकल सकेंगे। कल्याणकारी योजनाओं में व्याप्त भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जायेगा। इस फामुर्ले को लागू करने में प्रमुख समस्या राजनीतिक पार्टियों का सत्ता प्रेम है। सरकारी कर्मचारियों की लॉबी का सामना करने का इनमें साहस नहीं है। सारांश है कि भारत महाशक्ति बन सकता है यदि राजनीतिक पार्टियों द्वारा कल्याणकारी कार्यक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारियों की बड़ी फौज को खत्म किया जाये। इन पर खर्च की जा रही रकम को सीधे मतदाताओं को वितरित कर देना चाहिये। इस समस्या को तत्काल हल न करने की स्थिति में हम महाशक्ति बनने के अवसर को गंवा देंगे।
 यह सच है कि भारत महाशक्ति बनने के करीब है परन्तु हम भ्रष्टाचार की वजह से इस से दूर होते जा रहे हैं। भारत के नेताओं को जब अपने फालतू के कामों से फुरसत मिले तब ही तो वो इस सम्बन्ध में सोच सकते हैं उन लोगों को तो फ्री का पैसा मिलता रहे देश जाये भाड में भारत को महाशक्ति बनने में जो रोड़ा है वा है नेता। युवाओं का इस के लिये इनके खिलाफ लड़ना पड़ेगा, आज देश को महाशक्ति बनाने के लिये एक महाक्रान्ति की जरूरत है, क्योंकि बदलाव के लिये क्रान्ति की ही आवश्यकता होती है लेकिन इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा की भारत के रशिया जैसे महाशक्तिशाली देश की तरह टुकड़े न हो जाये, अपने को बचाने के लिये ये नेता कभी भी रुप बदल सकते है।

संदर्भ:

1. भारतीय दण्ड संहिता (I.P.C.) धारा 161.
2. श्री. के संयानम समिती का रिपोर्ट - 1964
3. सुरेंद्र कटारिया - भारतीय लोकप्रशासन
4. ट्रांसपारेंसी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया, डिसेम्बर 2011
5. चंद्रकांत मिस्रा - मानवी हक्क व जवाबदाय्य
6. दैनिक सकाळ 17 ऑगस्ट 2011.
7. ट्रांसपारेंसी इंटरनेशनल ऑफ इंडिया डिसेम्बर 2011

PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.

- 11 -

२५/६/१९

Impact Factor - 6.261

E-ISSN - 2348-



INTERNATIONAL RESEARCH FELLOWS ASSOCIATION'S
RESEARCH JOURNEY

International E-Research Journal

PEER REFREED & INDEXED JOURNAL

July-August-September 2019

Vol. 6 Issue 3

Chief Editor -

Dr. Dhanraj T. Dhangar,
Assist. Prof. (Marathi)
MGV'S Arts & Commerce College,
Yeola, Dist - Nashik [M.S.] INDIA

Executive Editors :

Prof. Tejesh Beldar, Nashikroad (English)
Dr. Gajanan Wankhede, Kinwat (Hindi)
Mrs. Bharati Sonawane-Nile, Bhusawal (Marathi)
Dr. Rajay Pawar, Goa (Konkani)



This Journal is indexed in :

- University Grants Commission (UGC)
- Scientific Journal Impact Factor (SJIF)
- Cosmoc Impact Factor (CIF)
- Global Impact Factor (GIF)
- International Impact Factor Services (IIFS)



55	पूर्व विद्वानातील टसर रेशीम उद्योगाच्या उत्पादनाची बाजारपेठ व व्यापार	हरिश्चंद्र कैताडे	266
56	आपत्ती व्यवस्थापनातील राजकारण	श्री. संदिप वारुळे	275
57	मराठा तितुका मेळवावा - महाराष्ट्र धर्म वाढावावा	डॉ. अलका बडये	280
58	ऊसतोड महिला कामगार आणि शासकिय धोरण	प्रा. महादेव चुंभे	285
59	निरीक्षणगृहातील मुलांच्या ममत्या व शाननाची भूमिका	प्रा. अशोक सातपुते	289
60	मृत्यु आणि अनुरूपतावादी उपपत्ती : एक ममीक्षा	डॉ. राजेसाहेब मारडकर आणि प्रा. मोनालिसा खानोरकर	293
61	महाराष्ट्र पोलीस दलाचा विकास आणि प्रशासकीय रचना-एक अध्ययन	प्रा. एन. लार. हुरगळे व डॉ. आर. एम. भिसे	298
62	उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांच्या भावनिक परिपक्वतेचा त्यांचा शैक्षणिक संपादनावर	प्रीती डांगे	305
63	होणारा परिणाम- एक अभ्यास	डॉ. संजय शिंदे	311
64	अण्णाभाऊ साठे यांच्या साहित्य विचाराची प्रासंगिकता	डॉ. सुषमा प्रधान	314
65	भाषा, साहित्य आणि यशवंतरावजी चव्हाण	डॉ. कल्याण मोरे व प्रा. अरविंद पाटील	318
66	भारतातील कुटुंब नियोजन शस्त्रक्रिया : एक अभ्यास	डॉ. म. सु. पगारे, श्रीमती व्ही. आर. भोकरीकर	322
67	भारतीय स्त्री जीवनाचा चिकित्सक अभ्यास	डॉ. तेजश्री हुंबे	333
68	पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर जलयुक्त शिवार अभियानाचा चिकित्सक अभ्यास	डॉ. बाबाराव ठावरी	340
69	दलित कादंबरीतील जीवनचित्रण	डॉ. राजेंद्र पाटील	345
70	लोकदैवत कथेतील प्रतिकाल्मकता	डॉ. गजानन सोडनर	348
71	पुण्यक्षोक अहिल्याबाई होळकरांचे सामाजिक कार्य	डॉ. राजेंद्र वाटाणे, कु. मनाली राठोड	353
72	बंजारा गोत्रसंघटना, बंजारा गोत्रप्रतिक वाद	डॉ. नामदेव माळी	357
73	प्रवासवर्णन - एक ललित साहित्य प्रकार	डॉ. राष्ट्रपाल मेश्राम	361
74	दलित कवितेची पूर्वपरंपरा	डॉ. सुशांत चिमणकर	370
75	डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा राष्ट्रवाद : राष्ट्रावादापुढील आव्हाने आणि कार्यनीती	डॉ. माधुरी पाटील	383
76	प्राचीन जीवनातील लोककथा	डॉ. गुंफा कोकाटे	387
77	डॉ. कुंडलिक शिंदे लिखित 'समर्पित जीवनाचे आदर्श' मधील व्यक्तिचित्राचे वाङ्मयीन मूल्यमापन	प्रा. मनोज डोगे	402
78	संत तुकाराम व राष्ट्रमंत तुकडोजी महाराज यांच्या साहित्यातील सामाजिक जाणिवांचा तौलनिक अभ्यास	प्रा. विनोद मालेराव	406
79	'अवकाळी पावसाच्या दरम्यानची गोष्ट' : जीवन संघर्षाची कहाणी	डॉ. राजेंद्र पाटील	409
80	'म्हण' निर्मितीप्रक्रिया : अहिराणी बोलीभाषेच्या संदर्भात	डॉ. भाऊसाहेब गमे	412
81	व्रतस्थ शिक्षकाचे आत्मनिवेदन : फुलाफुलात चाललो	डॉ. दिपक बाविस्कर	416
82	वरिष्ठ महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांमधील अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याविषयीच्या जाणीव जागृतीचा अभ्यास	डॉ. दिपक बाविस्कर	421
83	७३ वी घटनादुरुस्ती आणि महिला नेतृत्वाचा विकास	सचिन शेवतेकर, डॉ. शरद कुलकर्णी	427
	اردو افسانہ میں روایتی موضوعات و ترجیحات	Mohd Abrarulhaq Abdul Zaher Amjad	427

या अंकाचे सर्व अधिकार प्रकाशकांनी राखून ठेवलेले आहेत. प्रकाशकांच्या पूर्वपरवानगीशिवाय या अंकातील लेखांचे पुनर्प्रकाशन करता येणार नाही. या अंकात व्यक्त झालेली मते व विचार हे त्या लेखाच्या लेखकांचे वैयक्तिक विचार आहेत त्यांच्याशी संपादक किंवा प्रकाशक सहमत असतीलच असे नाही. लेखांच्या मूळ मालकी हक्कासंदर्भातील संपूर्ण जबाबदारी लेखाच्या लेखकांची असेल.

- मुख्य संपादक, रिसर्च जर्नी



७३वीं घटनादुरूस्ती आणि महिला नेतृत्वाचा विकास

सं: अधक

सचिन सुधकर शेवतेकर

मानदर्थक

डॉ. शरद कुलकर्णी;

प्राचार्य, त्रिभागप्रमुख,

राज्यशास्त्र विभाग, तुतन ज्ञानविद्यालय मेलू, जि. परभणी

1.1 प्रस्तावना :

नेतृत्व हे व्यवस्थापनाच्या अनेक तत्त्वांपैकी एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे. कोणत्याही कार्याच्या अंमलबजावणीत नेतृत्वाची अत्यंत गरज असते. एका नियोजित ध्येयपूर्तीकडे घेऊन जाण्यासाठी आणि कार्याचे नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्यासाठी अनेकदा योग्य नेतृत्वाची गरज भासते. नेतृत्व अनेक प्रकारचे असते. ते प्रशासकीय व्यवस्थापनाचे एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे.

स्वातंत्र्यपूर्व काळातील चळवळींप्रमाणेच विसाव्या शतकाचे सहावे व सातवे दशक हे भारतात पुन्हा एकदा आंदोलने, चळवळी, संघर्ष, संप यांनी दुमदुमू गेले. विद्यार्थी संघटना, शेतकरी, शेतमजूर, गिरणी कामगार, दलित, आदिवासी, स्त्रिया इत्यादी समाजातील तथाकथित दुय्यम स्थानावरील लोकांनी आपापल्या मागण्यांसाठी या वेळी जोरदार निदर्शने करून आपल्या आवाजाची समाजाला जाणीव करून दिली. १९६९-७१ मध्ये पश्चिम बंगाल, आंध्र, केरळमध्ये नक्षलवादी आंदोलनाला ऊत आला. महाराष्ट्राप्रमाणेच विहार, गुजरात, मध्य प्रदेशमध्ये महागाई, भ्रष्टाचार यांच्याविरोधात जोरदार आंदोलने झाली. १९७४ मध्ये गुजरात आणि बिहारमध्ये जयप्रकाश नारायणांच्या नेतृत्वाखाली 'संपूर्ण क्रांती'च्या घोषणा दुमदुमल्या. भ्रष्ट राज्यकर्ते, जातिव्यवस्था आणि कट्टर धार्मिकतेचा विरोध, राजनैतिक आणि आर्थिक परिवर्तन, सामाजिक आणि व्यक्तिगत सलोखा ही जनआंदोलनाची परिभाषा त्यांच्या आंदोलनाचा केंद्रबिंदू होता. महाराष्ट्रातील धुळ्याप्रमाणेच भोजपूर, छत्तीसगढ, आंध्र प्रदेश इथे आदिवासींनी मोठे संघर्ष केले. देशातल्या कानाकोपऱ्यांतून विविध मागण्यांसाठी आंदोलने झाली आणि त्यात विद्यार्थ्यांची आणि स्त्रियांची संख्या फार मोठी होती. अनेक व्यक्तिगत, कौटुंबिक अडचणी, सामाजिक बंधने यावर मात करित स्त्रिया आंदोलनात सहभागी होत होत्या, पण त्यांच्या हळूहळू लक्षात येऊ लागले की, ज्या प्रगतिवादी, क्रांतिवादी, साम्राज्यवादी इत्यादी संघटनांशी स्वतःला जोडून घेऊन त्या काम करत होत्या, त्या संघटनांमध्येसुद्धा लिंगभेद केला जात होता. धार्मिक आणि जातीयवादाविरोधात लढताना प्रत्यक्षात व्यवहारामध्ये मात्र पितृसत्ताक व्यवस्थेचाच पुरस्कार होई. बाहेर स्त्री-स्वातंत्र्यावर व स्त्री-पुरुष समतेवर भाषणे देणारे पुरुष घरात मात्र 'पुरुषसत्ताक' होते. हळूहळू स्त्रियांच्या समस्याही वाढत गेल्या आणि स्वतंत्र स्वायत्त संघटनांची गरज स्त्रियांना वाटू लागली. महिलांवर होणारे अत्याचार, पुरुषांवरच्या अत्याचारापेक्षा वेगळे आहेत. सामाजिक व्यवस्था, भांडवलशाही समाजरचना, पितृप्रधानता यांच्याशी स्त्रियांच्या शोषणविरोधात लढायचे तर ही लढाई अनेक स्तरांवर लढायला हवी, असे अनेक प्रश्न स्त्रियांपुढे होते.

1.2 संशोधनाची उद्दिष्टे :

- नेतृत्वाची संकल्पना स्पष्ट करणे
- स्वातंत्र्यपूर्व काळातील महिला नेतृत्वाचा आढावा घेणे



- भारतीय समाजामध्ये महिलांची स्थिती स्पष्ट करणे
- 73 व्या घटनादुरुस्तीचा आढावा घेणे

1.3 संशोधनाची गृहीतके :

- 73 व्या घटनादुरुस्ती मुळे महिला नेतृत्वाचा विकास झाला

1.4 संशोधन पध्दती :

संशोधकाने संशोधनाच्या विविध पध्दतींपैकी सर्वेक्षणात्मक संशोधन पध्दती व विश्लेषणात्मक संशोधन पध्दतीचा आधार घेतला आहे,

१९७५ साल हे सर्वत्र जगभरच एका नव्या क्रांतीचे बानावरण निर्माण करवून गेले. या काळापर्यंत फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटेन, लॅटिन अमेरिका, अमेरिकेतील ब्लॅक पँथर आंदोलन, चीनमधील नवजनवादी क्रांती अशा अनेक चळवळींतून समाजव्यवस्थेत बदल होत होते. स्त्रियांचे प्रश्न हे तर विश्वव्यापी आहेत हे लक्षात आल्यावर संयुक्त राष्ट्रसंघाने १९७५ हे महिला वर्ष म्हणून घोषित केले आणि ८ मार्च हा महिला दिवस म्हणून घोषित झाला, त्यालाही ब्रिटेनमधील गिरणी कामगार स्त्रियांनी केलेल्या चळवळीचा संदर्भ होता. स्त्रियांचे प्रश्न यानिमित्ताने पृष्ठस्तरावर येऊ लागले आणि सर्वत्र जगातच ते इतके जटिल होते की, पुढची दहा वी महिला दशक म्हणून घोषित करण्यात आली. दुर्दैवाने या बटनेला तीस वर्षे झाल्यावरही स्त्रियांच्या कित्येक समस्या अजून सुटलेल्या नाहीत. या काळात ठिकठिकाणी महिलांच्या अनेक संघटनांची स्थापना झाली. यातील कित्येक महिला अन्य राजकीय संघटनांमध्ये कार्यशील होत्या. तरी आताच्या नव्या संघटना फक्त स्त्रियांच्या स्वायत्त संघटना होत्या. त्यामध्ये पुरुष सदस्य नव्हते; पण महिलांच्या आंदोलनांमध्ये ज्यांना स्त्री-प्रश्नांबद्दल सहानुभूती आहे असे पुरुष धरणे, मोर्चात सामील होऊ शकत होते. महिलांनी, महिलांसाठी बनवलेल्या या संघटनांतून नवे महिला नेतृत्व आपापल्या पातळीवर जन्माला येऊ लागले होते. महिलांचे शोषण, महिलांवरील अत्याचार, अन्याय याविरोधात लढणे हा सुरुवातीचा उद्देश होता. असा विचार मनात येतो की, समजा महिला वर्ष घोषित झाले नसते, तर महिला आंदोलने झाली नसती का? शहादा आंदोलन, महागाईविरोधातली आंदोलने आणि भारतात ठिकठिकाणी झालेल्या आंदोलनातील स्त्रियांचा सहभाग पाहता महिलांनी आपल्या स्वातंत्र्यासाठी आंदोलने करणे ही एक पुढची नैसर्गिक पायरीच होती. ८ मार्च १९७५ हा दिवस भारतात प्रथमच स्त्रीमुक्ती दिन म्हणून साजरा झाला. पुण्यामध्ये माओवादी स्त्री संघटना, मुंबईत स्त्रीमुक्ती संघटना स्थापन झाल्या. 'लाल निशाण पक्षा'ने वृत्तपत्राचा विशेषांक प्रसिद्ध केला. ऑगस्टमध्ये 'साधना' साप्ताहिकाने महिला विशेषांक प्रसिद्ध केला. सप्टेंबरमध्ये दलित संघटनांनी देवदासी संमेलन आयोजित केले. ऑक्टोबरमध्ये पुण्यात 'संयुक्त महिला मुक्ती संघर्षांचे' आयोजन करण्यात आले आणि त्यात वेगवेगळ्या राजकीय संघटनांच्या स्त्रिया प्रथमच एकत्र आल्या. शिवाय प्राध्यापक, लेखक, शिक्षक, व्यावसायिक, कामगार, ग्रामीण स्त्रिया जात, धर्म विसरून यापलीकडे 'स्त्री' म्हणून अमणाऱ्या प्रश्नांच्या ऊहापोहासाठी प्रथमच एकत्र आल्या.

केंद्र सरकारने 1993 मध्ये केलेल्या 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांना घटनात्मक मान्यता मिळाली. या घटना दुरुस्तीमुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांना 33% आरक्षणामार्फत सत्तेत भागीदारी मिळाली. आता तर हे आरक्षण 50% झाले, पण हा कायदा काही आपोआप मिळाला नाही; त्यासाठी खूप संघर्ष करावा लागला. मात्र, प्रदीर्घ काळ चूल आणि मूल यात अडकलेल्या महिलांना राजकारणात सत्तेचा वाटा जरूर मिळाला, पण त्यांना अजूनही आपले अधिकार कोणते आहेत, महिला राजकारणात नेमकी कोणती



मकारात्मक भूमिका वजावू शकतात, याची त्यांना कल्पना नाही.त्यामुळेच अनेकदा त्यांचे पती, वतीने कारभार करत असतात.

कल्याणकारी राज्याच्या संकल्पनेचा सातत्याने विस्तार होत गेल्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रात विविध संघटना निर्माण झालेल्या दिसून येतात. अशा सर्व संघटनांसाठी प्रशामकीय नेतृत्वाची आवश्यकता असते. 'नेतृत्व म्हणजे संघटनेच्या ध्येयपूर्तीसाठी विविध व्यक्तींच्या क्रिया-प्रक्रियांचे संचालन, मार्गदर्शन, नियंत्रण व समन्वय करणे होय'. [१] नेतृत्वाच्या विविध विचारवंतांनी विविध व्याख्या केल्या आहेत. मॅरी पार्कर फॉलेटने नेतृत्वसंबंधी विचार मांडतांना म्हणतात 'केवळ प्रभुत्व स्थापन करणे, नेतृत्वाचे वास्तविक वैशिष्ट्य नाही' 'Leader & Export' या शोध निबंधात त्या म्हणतात 'जी आपल्या समूहात उन्हाह व शक्ती निर्माण करू शकते, जिना पुढे येऊ इच्छिणाऱ्याला प्रोत्साहित करणे माहीत असते, तसेच सदस्यांच्या प्रत्यक्ष क्षमतेचा योग्य उपयोग करणे माहीत असते, अशी व्यक्ती नेता असते'. [२]

1. पदावर आधारित नेतृत्व
2. व्यक्तिमत्त्वावर आधारित नेतृत्व
3. कार्यावर आधारित नेतृत्व.
4. राजकीय पक्षाचे नेतृत्व
5. शासनाचे नेतृत्व
6. शिक्षण संस्थांचे नेतृत्व
7. आर्थिक नेतृत्व
8. प्रशासकीय नेतृत्व
9. सामाजिक संघटनांचे नेतृत्व
10. नेतृत्वाचे मुख्य कार्य :
11. नेतृत्वासाठी आवश्यक गुण :

सत्तेच विकेंद्रीकरण हा केंद्रबिंदू मानून महाराष्ट्राचे शिल्पकार यशवंतराव चव्हाण यांनी पंचायतराज व्यवस्थेची मुहूर्तमेढ रोवली. महाराष्ट्रातील पंचायतराज व्यवस्था ही आदर्श व्यवस्था म्हणून संपूर्ण देशात मान्य झाली आहे. 73 व्या घटना दुरुस्तीमुळे पंचायतराज संस्थांना विशेषकरून ग्राम पंचायत व ग्रामसभांच्या शेवटच्या स्तरावरील संस्थांना घटनात्मक अधिकार प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे राज्यातील पंचायतराज व्यवस्थेला बळकटी मिळाली. देशातील महिलांना प्रत्यक्ष सहभाग देण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रेसर आहे. महिलांना सबला करण्याच्या पथावरील 73 वी घटनादुरुस्ती हे महत्वाचे पाऊल आहे.

भारतीय समाजामध्ये महिलांची स्थिती मागासलेली होती. स्त्रीयांचा विकास करण्याच्या दृष्टीने प्राचीन काळामध्ये कोणत्याही प्रकारचे वातावरण नव्हते. तरी काही स्वकीय आणि परकीय समाजसुधारकांनी महिलांची स्थिती व दर्जा सुधारण्यासाठी मोलाचे प्रयत्न केल्याचे आढळते. भारत स्वातंत्र्य झाल्यानंतर लिखित राज्यघटनेचा स्वीकार करून भारताने राज्यघटनेच्या माध्यमातून पारंपरिक पध्दतीस दुजारा देत स्त्री पुराणांना समान स्वरूपाचे अनेक राजकीय हक्क मान्य केले. यामुळे महिलांचा पुरुषाप्रमाणेच राजकीय विकास होण्यास हवा होता. परंतु भारतीय राज्यघटनेने महिलांना इतके अधिकार आणि हक्क प्रदान करून सुध्दा म्हणावा तेवढा विकास होऊ शकला नाही. राजकीय विकास करण्याच्या दृष्टीने राष्ट्रीय व राज्य स्तरावर प्रयत्न करण्यात आले,

Signature



पण महिलांचा सहभाग कमी प्रमाणात दिवून आला. म्हणूनच 73 वी घटना दुरुस्ती करून पंचायतराज संस्थामध्ये महिलांचा सहभाग वाढविण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न करण्यात आला होता.

लोकशाहीची प्रक्रिया गतिमान करण्यासाठी आणि भारताचा सर्वांगीण विकास करण्यासाठी महिलांचा सहभाग महत्वाचा आहे. हा सहभाग प्रत्यक्षात येण्यासाठीच स्थानिक स्वशासन संस्थांची स्थापना करण्यात आली आहे. या संस्था ग्रामीण क्षेत्रातील विविध दुर्बल घटकांच्या विनायास चालता देण्याम उपयोगी ठरतात. सामाजिक दृष्टिकोनातून विचार केला, तर स्वाभाविकच आपल्या लक्षात येईल. 50 टक्के पुरुष आणि 50 टक्के महिला आहेत. तरीमुद्दा हा वर्ग मागाम राहिल्याचे आढळते. कारण भारतीय ममाजावर पुरुषप्रधान संस्कृतीचा पगडा आहे. म्हणून या पारंपरिक व्यवस्थेला कुठेतरी पायबंद देणे आवश्यक होत. यात महिलांची भूमिका महत्वाची आहे. कारण महिला प्रतिनिधी ही बदलांची अग्रदूत मानली जाते. या संदर्भात पंडित जवाहरलाल नेहरू म्हणतात की, जर जनतेत जागृती निर्माण करावयाची असेल, तर अगोदर महिलांमध्ये जागृती निर्माण करा. एक वेळेस त्या पुढे आल्या की, स्वतःचे कुटुंब, गाव, शहर आणि संपूर्ण देश विकसित होण्यास वेळ लागणार नाही.

आपले निर्णय आपण घेऊन आपले भविष्य स्वतःच ठरविणे हे खऱ्या लोकशाही व्यवस्थेला अपेक्षित आहे. या दृष्टिकोनातून निर्णय प्रक्रियेत लोकांचा जास्तीत-जास्त सहभाग असावा म्हणून लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण करण्यात आले. भारतात मोठ्या प्रमाणात सामाजिक विविधता आहे. अशा विविधता असणाऱ्या समाजात सलोख्यांचे, मौत्रीचे, जिऱ्हाळ्यांचे संबंध स्थापन करण्यासाठी 73 व्या घटनादुरुस्तीने पंचायतराज व्यवस्थेमध्ये कलम 243(5) नुसार तिन्ही स्तरावर आरक्षण व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे. या आरक्षणामुळेच महिला नेतृत्वाला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली आहे. तसेच राजकीय क्षेत्रात वाढण्याची व सक्षम निर्णय घेण्याची कुवत त्यांच्यात निर्माण झाली आहे. 73 व्या घटनादुरुस्तीनुसार आरक्षण पुढीलप्रमाणे ठेवले गेले होते.

- अनुसूचित जाती व जमातीना लोकसंख्येच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात येईल. त्यापैकी 1/3 कमी नाही इतके त्या प्रवर्गातील महिलांसाठी आरक्षण.
- इतर मागासवर्गीयांसाठी आरक्षण 27 टक्के असेल, परंतु 1/3 पेक्षा कमी नाही इतके आरक्षण महिलांसाठी असेल.
- एकूण सदस्य कमीत-कमी 1/3 पेक्षा कमी नसेल इतके आरक्षण महिलांसाठी राखीव ठेवण्यात येईल.

73 वी घटनादुरुस्ती झाल्यानंतर ग्रामपंचायत, पंचायत समिती व जिल्हा परिषद या पंचायतीच्या त्रिस्तरीय व्यवस्थेत जेव्हा महिलांना आरक्षणाची तरतूद केली तेव्हा खऱ्या अर्थाने भारतीय स्त्री राजकारणात सक्रीय नेतृत्व करू लागली. सद्यःस्थितीचा (2019) आढावा घेतला तर स्वाभाविकच आपल्या लक्षात येईल की, भारतात पंचायतराज व्यवस्थेत कार्यरत असणाऱ्या महिलांची संख्या जवळपास निम्मी आहे. वास्तविकतः पंचायतीत केवळ 50 % टक्के इतपत आरक्षणाची व्यवस्था आहे. परंतु वज्याचशा पंचायतीत महिलांचा सहभाग 50% टक्के च्या वर गेलेला आहे.

1993 माली 73 व्या घटनादुरुस्तीने महिलांसाठी 33% जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. अर्थात या जागा राखीव ठेवण्यामागचे कारण म्हणजे महिलांच्या सामाजिक, राजकीय नेतृत्वाचा विकास करणे होय. म्हणजे 1947 ला भारतीयांची त्रिटिशांच्या गुलामगिरीतून मुक्तता झाली. भारत स्वतंत्र झाला.



आर्थिक,सामाजिक, राजकीय स्वातंत्र्य भारतीयांना मिळाले होते.परंतु असे अमले तरी तुकतेच स्वातंत्र्य मिळालेले असल्याच्या कारणास्तव भारतीयांचा समतोल प्रमाणात विकास म्हणावा तितका झाला नाही.कारण राजकीय नेतृत्व करण्याची मंघी केवळ पुरुषांनाच अधिक प्रमाणात असल्याने स्त्रीयांचा म्हणावा तितका विकास झाला नाही.अर्थात सामाजिक मलोन्ना काहिशा प्रमाणात समप्रमाणात नव्हता.स्वातंत्र्य मिळून 45 वर्षांचा काळ मार्ग गेला.तरी मूज भारतीयांनी महिलांना नेतृत्वाची मंघी अंधिकाधिक प्रमाणात दिली नाही. खरं तर महिलांना पंचायतीत समाविष्ट जोपर्यंत केले जात नाही, तोपर्यंत समतोल विकास करणे अशक्य आहे.हे राजीव गांधी पंतप्रधान असतांना त्यांना कळून चुकले होते. महात्मा गांधीजींच्या स्वप्रातील आदर्श रामराज्य जर परत आणायचे असेल, तर देशांच्या विकासात ग्रामीण विकासाला खरं महत्व आहे.हे राजीव गांधींनी ओळखले होते.म्हणूनच त्यांनी मुरुवातीला 1989 मध्ये विधेयक मांडले.परंतु त्यास सक्षम प्रतिमाद मिळाला नाही.मात्र गांधीनंतर पी.व्ही नरसिंहराव पंतप्रधान झाले आणि 1993 ला 73 वी घटनादुरुस्ती करण्यात आली.महिलांना 33% जागा आरक्षित ठेवण्यात आल्या.1993 ते 2018 या 25 वर्षांचा अभ्यास केल्यास असे दिसून येते की, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा व इतर बहुतांश राज्यांनी महिलांना 33 टक्क्यांवरून 50 टक्के आरक्षणाची व्यवस्था केली.देशात पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्र राज्याने उशीरा का होईना 2011 ला ही उणीव भरून काढली.50 टक्के जागा पंचायतीत राखीव ठेवल्या. वर्षानुवर्षांच्या समतेच्या संघर्षासाठी महिलांना लढावे लागले.अखेर त्याला यश आले.महिला स्थानिक स्वाराज्य संस्थेत सक्षमपणे नेतृत्व करू लागल्या व खज्या अर्थात 1993 ला केलेल्या घटना दुरुस्तीला यश आले.

निष्कर्ष :

73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे पंचायतराज व्यवस्था सक्षम झाली आहे.परंतु महिला आरक्षणामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना पंचायतराज संस्थेत सहभागांची मोठ्या प्रमाणात संधी मिळाली आहे.या संधीमुळेच महिला राजकारणात प्रवेश करू लागल्या आहेत.तसेच आपल्या नेतृत्वाच्या कार्यक्षमतेची चुणूक त्यांच्या कार्यातून स्पष्टपणे दाखवत आहे.स्थानिक स्वशासनामध्ये स्थिरावत असलेले महिला नेतृत्व हे पुरुषाहून सरस काम करत असल्याचे दिसून येत आहे.स्थानिक स्वशासनातील महिला सहभागात झालेली वाढ ही केवळ संख्यात्मक राहिलेली नसून,त्यांच्यात ही समाजाची योग्य घडी बसविण्याची क्षमता आहे. हे सिध्द झाले आहे.राजकारणातील महिलांचा सहभाग आरक्षणाच्या धोरणामुळे भविष्यामध्ये महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने सर्व हक्क उपभोगण्यास महाय्यकारी ठरेल असे वाटते.

शिफारशी :

- 73 व्या घटनादुरुस्तीमुळे महिला नेतृत्वाला चालना मिळाली आहे,परंतु आणखी यात गतीशिलता आणण्यासाठी स्वयःसहाय्यता गट,महिला मंडळ व इतर सामाजिक संस्थांनी अधिक वेळ देऊन त्याद्वारे राजकारणात येण्याची दारे खुली करण्यात यावी.
- महिलांना राजकीय प्रक्रियेद्वारे शक्ती प्रदान केल्यास त्यांच्यातील निर्णय क्षमता विकसित होईल.त्याद्वारे त्यांच्या कारभारातील गुणात्मक सहभाग वाढेल व त्यांचा चांगला परिणाम त्यांच्या कामगिरीवर होवून त्यांचा वैयक्तिक विकास होण्यास मदत होईल.



- महिला सरपंचाच्या व्यक्तिमत्वाचा विकास करण्यासाठी व त्यांच्यामध्ये नेतृत्वाचे गुण निर्माण करण्यासाठी सामाजिक कार्यावरोवरच इतर सार्वजनिक कार्यात देखील महभागी करून घेण्याचा प्रयत्न केला जावा.
- 73 व्या घटना दुरुस्तीचा ग्रामीण भागात व्यापक स्वरूपात प्रसार व प्रचार करण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.
- पंचायतराज संस्थेत नेतृत्व करत असलेल्या बहुतांश महिला या स्वबळावर पुढे आलेल्या नाहीत. म्हणून स्वातंत्र्यपणे व स्वबळावर महिला राजकारणात महभागी होण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले जावेत.

संदर्भग्रंथ सूची:

- सिरसाठ शाम /भगवासिंह बौनाडे,भारतातील स्थानिक स्वराज्य संस्था, विद्या बुक पब्लिशर्स, औरंगपुरा,औरंगाबाद.पान न.2,3,6
- यशमयंन,2002,महिला व राजकारण,विशेष अंक,वर्ष 2 रे,अंक चौथा, जानेवारी ते मार्च,पान न. 32
- ठोंबरे मतीश,जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक स्वशासन,कैलास पब्लिकेशन, औरंगपुरा,औरंगाबाद.पान न. 250.
- प्रशासकीय सिद्धान्त.(पृ.क्र.१३७) प्रा.व्ही.के.सलगरे. कैलास पब्लिकेशन्स. औरंगाबाद.
- प्रशासकीय विचारवंत. (पृ.क्र.१२१) लेखक: शाम शिरसाठ, जितेंद्र वासनिक, भगवानसिंग बौनाडे. प्रकाशक: ज्ञानसमिधा पब्लिशिंग वर्ल्ड. औरंगाबाद

Pal


PRINCIPAL
RAJIV GANDHI ARTS, COMMERCE
& SCIENCE COLLEGE, KARMAD
TQ. & DIST. AURANGABAD.